सोशल मीडिया से जुड़ें
Parivehan_Vishesh

www.newsparivahan.com

परिवहन विशेष

RNI No :- DELHIN/2023/86499
DCP Licensing Number : F.2 (P-2) Press/2023

वर्ष 03, अंक 162, नई दिल्ली, बुधवार 20 अगस्त 2025, मूल्य ₹ 5, पेज 8

देश का पहला ट्रांसपोर्ट दैनिक समाचार पत्र

आज का सुविचार

अगर मेहनत को आदत बना लिया जाए तो कामयाबी मुकद्दर बन जाती है।

03 ओखला में शिक्षा पर मंथन, जल्द खुलेगा 'आज़मी एजुकेशन सेंटर'
06 स्वास्थ्य बनाम प्लास्टिक और एल्युमीनियम
08 सुझाव से समाधान तक: अमृतसर से शुरू हुआ "राइजिंग पंजाब" अभियान

दिल्ली परिवहन आयुक्त से जनहित में छोटा सा सवाल ?

पिंकी कुंडू सह संपादक परिवहन विशेष

क्या दिल्ली परिवहन आयुक्त को भी पूर्व में रहे दो आयुक्त पद पर कार्यरत आयुक्तों की तरह लगता हैं की परिवहन विभाग तकनीकी विभाग नहीं गैर तकनीकी विभाग है ?

1. क्या परिवहन आयुक्त की नजर में आर आर जो किसी भी पद पर कार्य करने के लिए अधिकारी के लिए बने हैं उनका कोई तथ्य नहीं है ?

2. क्या परिवहन आयुक्त की नजर में माननीय सर्वोच्च न्यायालय भारत के द्वारा दिए गए दिशा निर्देश की भी कोई अहमियत नहीं है ?

3. क्या परिवहन आयुक्त की नजर में सड़क परिवहन एवम्राजमार्ग मंत्रालय द्वारा दिए गए दिशा निर्देश की भी कोई अहमियत नहीं है ?

4. क्या परिवहन आयुक्त की नजर में माननीय कैट द्वारा दिए गए दिशा निर्देश की भी कोई अहमियत नहीं है ?

5. क्या परिवहन आयुक्त की नजर में दिल्ली सरकार के कानून विभाग द्वारा जारी दिशा निर्देश की भी कोई अहमियत नहीं है ?

कुल मिलाकर परिवहन आयुक्त द्वारा जिस बेखौफ तरीके से दिल्ली परिवहन विभाग के मुख्य रूप से कार्यशैली में बनी शाखाओं के पदों पर गैर तकनीकी अधिकारियों की नियुक्त किया है उससे से तो साफ नजर आ रहा हैं की परिवहन आयुक्त की नज़र में दिल्ली परिवहन आयुक्त में किसी भी तकनीकी अधिकारी की आवश्यकता ही नहीं है या दूसरे शब्दों में समझे तो परिवहन विभाग तकनीकी कार्य करता ही नहीं है जिस कारण इस विभाग को तकनीकी अधिकारियों की आवश्यकता ही नहीं है।

दिल्ली में 2019 से

1. बढ़ने वाला जाम,

2. जनता को सुखद सुरक्षित समयानुसार सार्वजनिक सवारी सेवा उपलब्ध नहीं होना,

3. दिल्ली में बढ़ते वाहन हादसे,

4. दिल्ली की सड़को पर बिना परमिट, बिना इंश्योरेंस, बिना चालक लाइसेंस, बिना व्यवसायिक गतिविधि पंजीकरण नंबर, बाहरी राज्यों के निजी नंबर के वाहनों और बिना पंजीकरण के वाहनों द्वारा खुले आम व्यवसायिक गतिविधि करते पाया जाना

सिर्फ और सिर्फ परिवहन आयुक्त के द्वारा तकनीकी विभाग को गैर तकनीकी विभाग सिद्ध करने के कारण है।

दिल्ली में स्वयं विभाग द्वारा वाहन के पंजीकरण के लिए अनिवार्य वाहन माडल स्टेट अप्रूवल के अनुसार वाहन निर्मित ना होने के बावजूद पंजीकरण कर देना भी परिवहन आयुक्त के द्वारा विभाग को गैर तकनीकी विभाग सिद्ध करने के कारण संभव हो रहा हैं।

माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा तिपहिया तीन सवारी के लिए एक लाख की बंदिश लगाने पर तिपहिया तीन सवारी वाहनों को स्क्रैप हुए बिना नया वाहन रिप्लेस करने की पाबंदी होने के बावजूद **बिना तिपहिए तीन सवारी वाहनों के स्क्रैप** हुए नए तिपहिया तीन सवारी वाहनों को खरीदने की आज्ञा देकर स्वयं द्वारा बनाई एसओपी और माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना के साथ महिलाओं और जनता की सुरक्षा को दाव पर लगाना भी परिवहन आयुक्त के द्वारा विभाग को गैर तकनीकी विभाग सिद्ध करने के कारण संभव हो रहा हैं।

पेट्रोल वाहनों में सीएनजी किट लगाने के बाद उसकी जांच गैर तकनीकी अधिकारी द्वारा करवाकर वाहन फ्यूल मोड बदलकर पंजीकरण देने से सड़को पर चलते वाहनों में आग लगने से जान माल की हो रही हानि के लिए भी परिवहन आयुक्त के द्वारा विभाग को गैर तकनीकी विभाग सिद्ध करने के कारण संभव हो रहा हैं।

निष्कर्ष :- कुल मिलाकर दिल्ली परिवहन विभाग में जब तक तकनीकी पदों पर वापिस तकनीकी अधिकारी नियुक्त नहीं किए जाते **दिल्ली की सड़को पर जनता की सुरक्षा, जान माल की रक्षा सिर्फ और सिर्फ भगवान के हाथ में है ना की वाहन चालक के हाथ में, और इस सब का जिम्मेदार है दिल्ली परिवहन आयुक्त।**

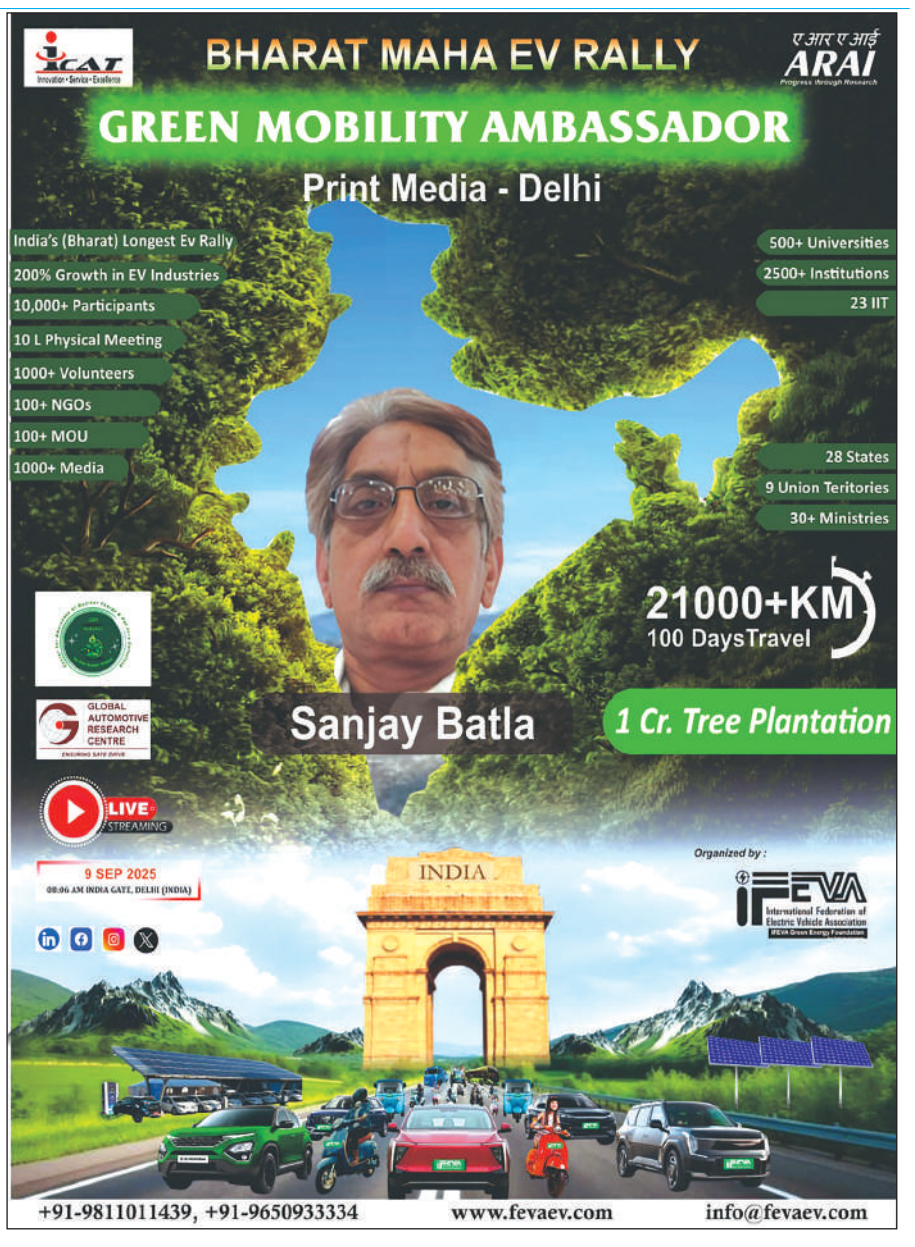

देश के पहले राष्ट्रपति से लेकर डॉ. कलाम तक ने किया इसमें सफर, जानें कहां देख सकते हैं ये अनोखी ट्रेन

यह लेख राष्ट्रपति सैलून के बारे में है जो भारतीय लोकतंत्र के इतिहास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था। इस सैलून का उपयोग भारत के पहले राष्ट्रपति डॉ. राजेंद्र प्रसाद से लेकर डॉ. एपीजे. अब्दुल कलाम तक कुल ग्यारह राष्ट्रपतियों ने किया था। यह सैलून न केवल तकनीक और शाही ठाठ-बाट का प्रतीक था बल्कि राष्ट्रपति और जनता के बीच की दूरी को भी कम करता था।

परिवहन विशेष न्यूज

नई दिल्ली। पटरियों पर दौड़ती ट्रेन को आम लोग हमेशा सफर और रफ्तार से जोड़ते रहे हैं, लेकिन कभी कोई रेल का डिब्बा राष्ट्रपति भवन का रूप भी ले सकता है। इस अनोखी ट्रेन को रेल संग्रहालय में देखा जा सकता है।

एक बार फिर राष्ट्रीय रेल संग्रहालय में नए रूप में सजा राष्ट्रपति सैलून अनोखी परिकल्पना का जीता-जागता उदाहरण है। चमचमाती लाल रंग की बॉडी, सुनहरी धारियों से सजा बाहरी हिस्सा और भीतर की आलीशान सुविधाएं इसे किसी शाही महल से कम नहीं बनातीं।

यह सिर्फ एक रेल कोच नहीं है बल्कि भारतीय लोकतंत्र के इतिहास की वह चलती-फिरती निशानी व शान है, जिसने राष्ट्रपति और जनता के बीच की दूरी को पटरियों के जरिये समेट था।

भारत के पहले राष्ट्रपति डॉ. राजेंद्र प्रसाद से लेकर डॉ. एपीजे. अब्दुल कलाम तक कुल 11 राष्ट्रपतियों ने इस सैलून में सफर किया था। रेल पटरियों पर दौड़ता यह सैलून तकनीक और शाही ठाठ- बाट के साथ भारत की लोकतांत्रिक धड़कनों को भी अपनी रफ्तार से जीवंत करता रहा।

भारतीय रेल ने 1953 में राष्ट्रपति के लिए एक विशेष सैलून का डिजाइन तैयार किया था। तीन साल की मेहनत के बाद 1956 में यह रेल सैलून तैयार हुआ और एक जनवरी 1957 को प्रथम राष्ट्रपति डॉ. राजेंद्र प्रसाद ने इसमें यात्रा की। उनकी यह यात्रा उस परंपरा की शुरुआत थी, जिसने राष्ट्रपति और जनता के बीच की दूरी मिटा दी।

दो कोचों में बंटा सैलून

राष्ट्रपति सैलून दो विशेष डिब्बों में बंटा है। यह कोच संख्या 9000 और 9001 से मिलकर बना है। पहले कोच संख्या 9000 कार 'ए' में राष्ट्रपति का दफ्तर, बैठक कक्ष, विश्राम कक्ष, अतिथि कक्ष, स्नानघर. आलीशान किचन और शौचालय शामिल है।

इस हिस्से में राष्ट्रपति अपनी औपचारिक बैठक और राजकीय कार्य करते थे। यहां 14.5 किलोग्राम चांदी के बर्तन थे, जिनमें राष्ट्रपति खाना खाते थे।

वहीं, दूसरे कोच संख्या 9001 कार 'बी' में चिकित्सक और सचिव का केबिन, भोजन कक्ष, रसोईघर तथा पेंट्री स्टोर जैसी सुविधाएं मौजूद है। यह कोच राष्ट्रपति के स्टाफ और टीम के लिए तैयार किया गया गया था।

तकनीकी कौशल और रफ्तार

शाही ठाठ का प्रतीक सैलून अधिकतम गति 90 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ती थी। वैक्यूम ब्रेक प्रणाली से लैस इस सैलून को चेन्नई की इंटीग्रल कोच फैक्ट्री (आईसीएफ) ने स्टील से तैयार किया था।

सैलून इन महामहिमों के सफर का रहा साक्षी

भारत के पहले राष्ट्रपति डॉ. राजेंद्र प्रसाद को रेल यात्रा का काफी शौक था। उन्होंने 11 जनवरी 1957 में दिल्ली से कुरुक्षेत्र तक के लिए राष्ट्रपति सैलून की पहली यात्रा शुरू की थी। पूरे कार्यकाल में उन्होंने राष्ट्रपति सैलून में कुल 44 बार यात्रा की थी।

देश के दूसरे राष्ट्रपति रहे डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने कार्यकाल में राष्ट्रपति सैलून में 19 बार यात्रा की थी। इसमें उनकी लगातार दस दिन चलने वाली यात्रा भी शामिल थी। इसके अलावा चौथे राष्ट्रपति रहे वी.वी. गिरि ने भी राष्ट्रपति सैलून में 12 बार यात्रा की थी।

डॉ. अवुल पाकिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम भारत के राष्ट्रपति के 11 वें राष्ट्रपति बने। उन्होंने राष्ट्रपति सैलून में तीन बार यात्रा की। इसके बाद राष्ट्रपति सैलून का संचालन बंद कर दिया गया।

भारत के 14 वें राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद ने कंडम हो रहे राष्ट्रपति सैलून को एक प्रदर्शनी के रूप में राष्ट्रीय रेल संग्रहालय में भेजने का सुझाव दिया। जिसके बाद वर्ष 2021 में सैलून को राष्ट्रीय रेल संग्रहालय में एक स्टार प्रदर्शनी के रूप में शामिल किया गया।

टेंपल्स ऑफ लिबरलाइजेशन एंड वेलफेयर एलाइड ट्रस्ट (पंजीकृत)

TOLWA

website : www.tolwa.in
Email : tolwadelhi@gmail.com
bathlasanjaybathla@gmail.com

रजिस्टर्ड अंडर सैक्शन 60 विद रजिस्ट्रेशन नंबर (152/02-03-2020), एमएसएमई रजिस्ट्रेशन नंबर उद्यम -डीएल - 0026470, नीति आयोग रजिस्ट्रेशन नंबर वीओ/एनजीओ/0303274/25-01-2022 दर्पण

रजिस्टर्ड कार्यालय :- 3, प्रियदर्शिनी अपार्टमेंट, ए -4 पश्चिम विहार, न्यू दिल्ली 110063
कॉरपोरेट कार्यालय :- 529, समयपुर, मेंन बवाना रोड, नियर बैंक ऑफ़ बड़ौदा दिल्ली 110042

सरकारी खजाने भरने का ठेका ट्रक मालिकों की नहीं, डिज़ल के दाम 60/- प्रती लीटर किये जाएँ - डॉ राजकुमार यादव

ट्रक मालिक गुमराह न हों,डिज़ल भी जीएसटी के दायरे मैँ हो, परिवहन उद्योग पर एकल जीएसटी 5% हो – उफ्तत्सा

नई दिल्ली – उफ्तत्सा राष्ट्रीय संयुक्त मोर्चा (ट्रक ट्रांसपोर्ट सारथी), जो देशभर के ट्रक चालकों, मालिकों और परिवहन व्यवसाईयों का प्रतिनिधित्व करने वाला एक प्रमुख संगठन है, ने बढ़ती डीजल कीमतों और परिवहन उद्योग की ज्वलंत समस्याओं के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद की है। अंतर्राष्ट्रीय क्रूड ऑयल की कीमतों में हालिया गिरावट के बावजूद भारत में डीजल की खुदरा कीमतों में वृद्धि ने ट्रक परिवहन क्षेत्र को गंभीर रूप से प्रभावित किया है, जिससे माल ढुलाई लागत और उपभोक्ता वस्तुओं की कीमतों में अनावश्यक वृद्धि हो रही है।उफ्तत्सा राष्ट्रीय संयुक्त मोर्चा ने अपनी प्रभावशाली भूमिका निभाते हुए उफ्तत्सा राष्ट्रीय संयुक्त मोर्चा (ट्रक ट्रांसपोर्ट सारथी) के बैनर तले ट्रक चालकों,ट्रक मालिकों और छोटे-मध्यम परिवहन व्यवसायियों के हितों की रक्षा के लिए समर्पित संगठन के रूप मैँ महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। यह मोर्चा परिवहन उद्योग में नीतिगत सुधारों, चालकों के कल्याण और आर्थिक स्थिरता के लिए काम अभूतपूर्व कार्य निष्पादन किया है। यह संगठन ट्रक चालकों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने, उनके कामकाजी हालात सुधारने और परिवहन क्षेत्र को और अधिक संगठित और टिकाऊ बनाने की दिशा में प्रभावशाली रूप से सक्रिय है। मोर्चा विभिन्न राज्यों के ट्रक यूनियनों को एक मंच पर लाता है, ताकि उनकी समस्याओं को राष्ट्रीय स्तर पर उठाया जा सके।

उफ्तत्सा राष्ट्रीय संयुक्त मोर्चा ने सरकार और नीति निर्माताओं से निम्नलिखित मांगें रखी हैं:

डीजल कीमतों में पारदर्शिता और कमी की जाये,अंतर्राष्ट्रीय क्रूड ऑयल की कीमतों में हालिया कमी (2025 में औसतन 69.19 अमेरिकी डॉलर प्रति बैरल) के बावजूद, भारत में डीजल कीमतें 92 रुपये प्रति लीटर से अधिक बनी हुई हैं। उफ्तत्सा मांग करता है कि सरकार डीजल पर उत्पाद शुल्क और अन्य करों में कमी करे, ताकि क्रूड ऑयल कीमतों में कमी का लाभ उपभोक्ताओं और परिवहन क्षेत्र तक पहुंचे व आम जनता को महंगाई से सीधे तौर पर छुटकारा मिल सके1

माल ढुलाई दरों में संशोधन के रूप मैँ बढ़ती ईंधन लागत के कारण ट्रक ऑपरेटरों की आय प्रभावित हो रही है, जबकि माल ढुलाई दरें अपरिवर्तित ही नहीं अपितु लगातार ढ़लान पर हैं। उफ्तत्सा मांग करता है कि माल ढुलाई दरों को ईंधन कीमतों के साथ समायोजित किया जाए, ताकि ट्रक चालकों और ऑपरेटरों को उचित मुनाफा मिल सके। ईंधन को भी अतिशीघ्र जीएसटी के अन्तर्गत लाने हेतु हर सम्भव प्रयास करते हुए इसके दायरे मैँ लाया जाये,परिवहन व्यवसाय के अन्तर्गत कार्यरत चालक, ट्रक मालिक व ट्रांसपोर्टर्स के साथ दोहरी नीति व नियम बंद हो1

डॉ राजकुमार यादव राष्ट्रीय अध्यक्ष-₹उफ्तत्सा₹ राष्ट्रीय संयुक्त मोर्चा(ट्रक ट्रांसपोर्ट सारथी) ने कहा

₹ईंधन व उनके टैक्स से कमाए जा रहे राजस्व को ट्रक चालकों, ट्रक मालिकों व परिवहन व्यवसाईयों के हितों के लिए प्रयोग में ले जाएं व इन्हें विभिन्न स्कीमों व सब्सिडी के तहत कम से कम 40% इनमे ही वितरित किए जाने की व्यवस्था हो, जिससे इनकी स्थिति व जीवनशैली मैँ अभूतपूर्व सुधार आ सकेगा, इनके गाढ़े परिश्रम व खून पशिने कमाई के पैसे को इस तरह अनावश्यक तरीके से खर्च करने का खेल अब और न खेला जाए1 भारत देश के नागरिक के रूप में एक बड़ा समुदाय परिवहन व्यवसाय से जुड़े होने के कारण तिरस्कृत,बहिष्कृत व अपमानित व खुद को ठगा सा महसूस कर रहा है इसके मान, सम्मान, स्वाभिमान के साथ खिलवाड़ न करते हुए इनके परिश्रम व इनके खून के आंसू से सनी कमाई एंव देश के प्रति समर्पण की भावना, ईमानदारी व एकाग्रता के साथ देश के लिए समर्पित कार्य निष्पादन की भावना को ठेस ना पहुंचा जाए1

लॉजिस्टिक्स लागत में कमी के अनुरूप भारत में लॉजिस्टिक्स लागत GDP का 13-14% है, जो वैश्विक औसत से अधिक है। उफ्तत्सा मांग करता है कि सरकार इंटरमोडल परिवहन और डिजिटल लॉजिस्टिक्स प्लेटफॉर्म को बढ़ावा दे, ताकि परिवहन लागत कम हो और दक्षता सम्पूर्णतः बढ़े।

परिवहन नीतियों में एकरूपता न होकर विभिन्न राज्यों में अलग-अलग कर और नियम परिवहन उद्योग को जटिल व सरकारी व्यवस्था को हास्यास्पद बनाते हैं। उफ्तत्सा एक समान राष्ट्रीय परिवहन नीति की मांग करता है, जो अंतर-राज्यीय परिवहन को सुगम व समरसता पूर्ण बनाए।

उफ्तत्सा का बयान -₹बढ़ती डीजल कीमतें न केवल ट्रक चालकों, ट्रक मालिकों और परिवहन व्यवसायियों की आजीविका को प्रभावित कर रही हैं, बल्कि यह आम उपभोक्ताओं पर भी महंगाई का बोझ प्रत्यक्ष रूप से डाल रही हैं जिससे दिन प्रतिदिन आम व मध्यमवर्गीय जनजीवन कष्टकर व असहनीय हो चला है 1 सरकार को तत्काल कदम उठाकर डीजल कीमतों को नियंत्रित करना चाहिए और परिवहन क्षेत्र के लिए दीर्घकालिक नीतिगत सुधार लागू करने चाहिए। हमारा संगठन ट्रक चालकों और श्रमिकों के हितों के लिए संघर्ष करने के लिए प्रतिबद्ध है,₹ उफ्तत्सा राष्ट्रीय संयुक्त मोर्चा1

मोर्चा ने सरकार से तत्काल संवाद शुरू करने और इन मांगों पर विचार करने की अपील की है। साथ ही, देशभर के ट्रक चालकों, ट्रक मालिकों और संलग्न परिवहन व्यवसाईयों से एकजुट होकर इस आंदोलन में शामिल होने का आह्वान किया है। उफ्तत्सा ने यह भी घोषणा की है कि यदि मांगें पूरी नहीं हुईं, तो अनिश्चितकालीन शांतिपूर्ण प्रदर्शन और अन्य जरूरी कदम उठाए जाएंगे।

संपर्क:
'उफ्तत्सा' राष्ट्रीय संयुक्त मोर्चा (ट्रक ट्रांसपोर्ट सारथी)

दृष्टिकोण का महत्व – एक रोचक गणित हिंदी में

अगर हम मानें कि:

A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z = क्रमशः 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26।

यानी A = 1, B = 2, C = 3 इस तरह।

अब हम ऐसे गुण को ढूंढते हैं जो 100% अंक प्राप्त करता है।

1. हम मान लेते हैं कि जीवन में ₹कड़ी मेहनत (HARDWORK)₹ के जरिए सफलता प्राप्त होती है।

H+A+R+D+W+O+R+K = 8+1+18+4+23+15+18+11 = 98%।

कड़ी मेहनत ज़रूरी है लेकिन यह 100% नहीं है।

2. अब ₹ज्ञान (KNOWLEDGE)₹ की बात करते हैं।

K+N+O+W+L+E+D+G+E = 11+14+15+23+12+5+4+7+5 = 96%।

ज्ञान महत्वपूर्ण है, लेकिन यह भी पूर्णता को छू नहीं पाता।

3. ₹भाग्य (LUCK)₹ भी कभी-कभी ज़रूरी माना जाता है।

L+U+C+K = 12+21+3+11 = 47%।

भाग्य केवल कठिन परिस्थितियों में मदद करता है, लेकिन पर्याप्त नहीं है।

4. ₹धन (MONEY)₹ जीवन में महत्वपूर्ण है।

M+O+N+E+Y = 13+15+14+5+25 = 72%।

धन जीवन को सुखमय बनाता है, लेकिन संपूर्ण संतोष नहीं दे सकता।

5. ₹नेतृत्व (LEADERSHIP)₹ एक प्रमुख गुण है।

L+E+A+D+E+R+S+H+I+P = 12+5+1+4+5+18+19+8+9+16 = 97%।

नेतृत्व जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, लेकिन यह भी पूर्ण आनंद नहीं ला सकता।

तो ऐसा क्या है जो 100% हो सकता है?

कोई अनुमान?

नहीं?

₹दृष्टिकोण (ATTITUDE)₹ ही वह है जो मनुष्य को पूर्ण सफलता की कुंजी देता है।

A+T+T+I+T+U+D+E = 1+20+20+9+20+21+4+5 = 100%।

निष्कर्ष:

कड़ी मेहनत या ज्ञान से भी ज़्यादा, जीवन में आपका ₹दृष्टिकोण₹ सबसे महत्वपूर्ण है। ₹दृष्टिकोण बदलो, जीवन बदल जाएगा।₹

बेहिसाब तबाही त्राहि-त्राहि...!

आसमान से 'बेहिसाब' बरस रही तबाही,
कहां जाएं इंसान कर रहा हैं त्राहि-त्राहि।
इधर कुआं-उधर खाई ये तूने क्यों बनाई,
मझधार में छोड़कर क्यों की जग हँसाई।
कौन कहां खोया किसने ली कहाँ पनाह,
दूर-दूर तक किसी का न था कोई गुनाह।

यहां से वहां तक सभी हो गए हैं लथपथ,
पांव में पड़ रहे छालें कैसे चले अग्निपथ।
इतना क्रोध न करों डूबे आकंठ गले तक,
ये पत्थर भी लेने लगे दौड़कर जान तक।
निगल लिए पहाड़ तो नहीं बचे प्राण तक,
रखवालें भी बेबस हुवें ना रहीं आन तक।

संजय एम तराणेकर

बछवारस / वत्स द्वादशी आज

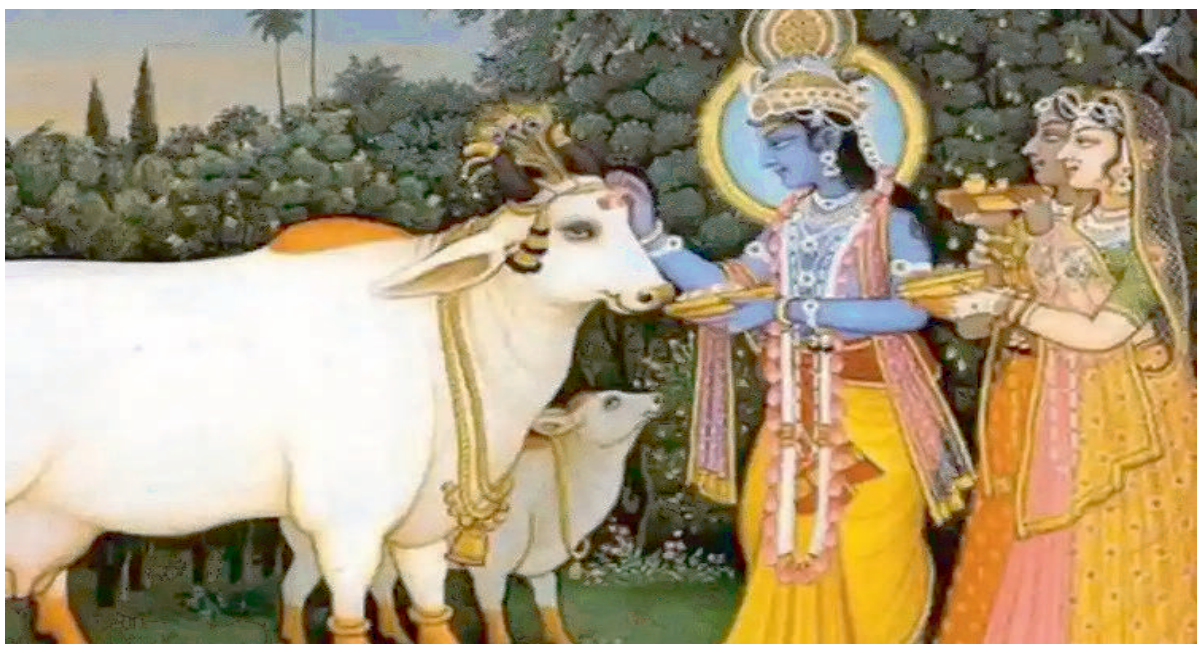

भाद्रपद मास (भादों) की कृष्णपक्ष की द्वादशी तिथि के दिन बछ बारस का पर्व मनाया जाता हैं। इस दिन पुत्रवती स्त्रियाँ अपने पुत्र के स्वास्थ्य और लम्बी उम्र के लिये गौमाता से प्रार्थना करती हैं और बछड़े वाली गाय का पूजन करती हैं। इस दिन चाकू से काटी गई वस्तुयें, गेहूँ, जौ, और गाय के दूध से बनी चीजों का सेवन निषेध हैं। एक दिन पहले ही रात्रि को बछबारस (Bachbaras) के लिये मूंग, मोठ, चने एवं बाजरा भिगो कर रख दिया जाता है। उसे भिजोना कहते हैं।

बछबारस / वत्स द्वादशी कब है?

==========

इस वर्ष बछवारस की पूजा एवं व्रत 20 अगस्त, 2025 बुधवार के दिन किया जायेगा।

बछवारस (वत्स द्वादशी) क्यों मनाते हैं?

==========

हमारे आराध्य श्री कृष्ण को गायों से बहुत प्रेम था। उन्होने गौ-सेवा के महत्व को लोगों को बताया और गाय को माता कहकर उसकी पूजा को प्रतिपादित किया भगवान श्री कृष्ण स्वयं गायों की सेवा किया करते थें। उनके गायों के प्रति इस प्रेम को देखकर स्वयं कामधेनू ने बहुला गाय का रूप लेकर नंदबाबा की गौशाला में स्थान लिया था। भगवान श्री कृष्ण का एक नाम गोपाल भी है। इस दिन पहली बार भगवान श्री कृष्ण गायों और बछड़ों को चराने के लिये गये थे। माता यशोदा ने श्री कृष्ण को खूब सजा-धजा कर और पूजा पाठ कराकर इस दिन गाय चराने के लिये भेजा था। उनके साथ उनके बड़े भाई बलराम भी थें। श्री कृष्ण उनके साथ गायों और उनके बछड़ों को लेकर चराने के लिये गये थे। इसलिये इस दिन सब लोग गौ-पूजा करके भगवान श्री कृष्ण द्वारा दिये गये गौ-सेवा के संदेश को सम्मान देकर इसे एक पर्व के रूप में मनाते हैं।

बछ बारस की पूजा कैसे करें? बछ बारस की पूजा विधि

==========

बछ बारस के दिन पुत्रवती स्त्रियाँ व्रत रखती है और गाय – बछड़ें की पूजा करती हैं। बछ बारस से एक दिन पहले रात्रि को बछबारस के लिये मूंग, मोठ, चने एवं बाजरा भिगो कर रख दिया जाता है। फिर प्रातः काल स्नानादि के बाद पूजा से पहले उसे कढ़ाई में छोंक कर पका लिया जाता हैं।

1. व्रत करने वाली स्त्री को बछ बारस के दिन प्रातः काल स्नानादि नित्य क्रिया से निवृत्त होकर स्वच्छ कपड़े पहननें चाहिये।

2. यदि आपके घर पर बछड़े वाली दूध देने वाली गाय हो तो उसे बछडे.के साथ स्नान करायें।

3. फिर गाय और उसके बछड़े को नया कपड़ा ओढाक़र, हल्दी-चंदन से तिलक करें और फूलों की माला पहनायें। अगर सम्भव तो उनेक सींगों को भी सजायें।

4. तत्पश्चात तांबे का बर्तन लेकर उसमें पानी भरें। उसमें तिल, अक्षत, इत्र और फूल ड़ालकर गाय पर छिड़के और उसके पैरों (खुर) पर जल ड़ाले। यह करते समय निम्नलिखित मंत्र का पाठ करें –

क्षीरोदार्णवसम्भूते सुरासुरनमस्कृते।
सर्वदेवमये मातर्गृहाणार्घ्यं नमो नमः॥

5. गाय माता के खुर पर लगी मिट्टी से अपने मस्तक पर टीका लगायें।

6. दीपक जलाकर गौमाता की आरती उतारें। भीगे चने, मूंग, मोठ एवं बाजरा गाय को अर्पित करें।

7. गौ पूजन के पश्चात बछ बारस की कहानी कहे या सुनें।

8. व्रत करने वाली स्त्री भिजोना (भीगा हुआ मूंग,मोठ, बाजरा और चने) पर पैसे रखकर अपनी सास या जेठानी को पैर छू करे दें।

9. बछ बारस के पूरे दिन व्रत रखकर रात को अपने ईष्ट देवता का ध्यान और पूजन करके भोजन करें।

10. इस दिन भोजन में गेहूँ और जौ नही खाना चाहिये और ना ही गाय के दूध से बनी किसी वस्तु का सेवन करना चाहियें। साथ ही चाकू से कुछ भी नही काटना चाहिये और न ही चाकू से कटी किसी वस्तु का सेवन करना चाहियें। इस दिन सब्जी भी काटना वर्जित हैं।

11. अगर आपके घर पर बछड़े वाली गाय न हो तो, आपके घर के आस-पास जहाँ भी बछड़े वाली गाय हो वहाँ इसी विधि से पूजा करें। पूजा के बाद उसके लिये दक्षिणा भी रखें।

12. यदि आपको बछड़े वाली गाय न मिले तो भी आप यह पूजा कर सकती है। उस परिस्थिति में आप गीली मिट्टी से गाय एवं बछडे. की प्रतिमा बनाकर उपरोक्त विधि से उनकी पूजा करे।

प्रेम पच्चीसा(भाग 5)

रोहन और माया, दो साधारण दिलों की कहानी, भोपाल से शहर में शुरू हुई। रोहन एक संवेदनशील कवि था, जिसकी कविताएँ प्रकृति, प्रेम और जीवन के सूक्ष्म रंगों को बयां करती थीं। माया, एक चित्रकार, अपने रंगों और ब्रश से कैनवास पर जीवन की खूबसूरती उतारती थी। दोनों की मुलाकात एक साहित्यिक समारोह में हुई थी, जहाँ रोहन अपनी कविता पढ़ रहा था और माया उसकी शब्दों की गहराई में खो गई थी। उनकी प्रेम कहानी एक कविता और चित्र की तरह धीरे-धीरे रंग भरती गई। शादी के बाद, दोनों ने एक साधारण मगर सुखी जीवन शुरू किया। शादी के एक साल बाद, माया ने एक खूबसूरत बालिका को जन्म दिया। उस दिन सुबह का सूरज कुछ अलग ही चमक रहा था। रोहन अस्पताल के कमरे में माया के पास बैठा था जब नर्स ने उनकी बेटी को उनकी गोद में रखा। छोटी-सी, नन्हीं आँखों वाली उस बच्ची को देखकर रोहन की आँखें नम हो गईं। उसने बच्ची का नाम सुझाया राशि, जो उनके प्रेम और सपनों का प्रतीक थी। माया ने मुस्कुराते हुए सहमति दी।

रोहन ने राशि को अपनी बाहों में उठाया और धीरे से कहा, ₹तू मेरी सबसे सुंदर कविता है।₹ उस पल में, रोहन को लगा जैसे उसका जीवन अब पूर्ण हो चुका है। माया, जो अभी भी थकान और खुशी के मिश्रित भावों में थी, ने रोहन की ओर देखा और कहा, ₹अब हमारी कहानी में एक नया रंग जुड़ गया है।₹ हम दोनों की राशि के सभी गुण राशि में देखने मिलेंगे।

राशि के आने से रोहन और माया का जीवन बदल गया। रोहन, जो पहले अपनी कविताओं में खोया रहता था, अब रातों को राशि को सुलाने के लिए लोरियाँ लिखने लगा। उसकी कविताओं में अब एक नई गहराई थी—एक पिता का प्रेम, एक बच्ची की मुस्कान, और एक परिवार की उमंग। माया ने अपने चित्रों में राशि की मासूमियत को उतारना शुरू किया। उसका कैनवास अब रंगों से नहीं, बल्कि भावनाओं से जीवंत हो उठा।

हालांकि, नई जिम्मेदारियों ने उनके जीवन में चुनौतियाँ भी लाईं। रोहन को अपनी कविताओं के लिए समय निकालना मुश्किल होने लगा। माया को भी अपने चित्रों के लिए प्रेरणा ढूँढने में समय लगता था। लेकिन दोनों ने एक-दूसरे का साथ कभी नहीं छोड़ा। रात को जब राशि सो जाती, रोहन और माया एक-दूसरे के साथ खुले आसमान में छोटे से रेडियो पर विविध भारती के मधुर छाया गीत सुन कर सो जाते अपने सपनों को फिर से बुनते।

एक दिन, रोहन ने माया से कहा, ₹क्यों न हम राशि के लिए कुछ खास करें? एक ऐसी दुनिया बनाएँ, जहाँ वह अपनी कल्पनाओं को उड़ान दे सके।₹ माया ने उत्साह से जवाब दिया, ₹हाँ, हम एक किताब बनाएँगे—तुम्हारी कविताएँ और मेरे चित्र। राशि के लिए, और उन सभी बच्चों के लिए जो सपने देखते हैं।₹ इस विचार ने उनके जीवन में नई ऊर्जा भर दी। रोहन ने बच्चों के लिए कविताएँ लिखना शुरू किया, जिसमें जादुई जंगल, बातें करने वाले पशु, और सितारों की कहानियाँ थीं। माया ने इन कविताओं को अपने रंगों से सजाया। राशि, जो अब कुछ महीनों की हो चुकी थी, अपनी माँ के चित्रों को देखकर हँसती और तालियाँ बजाती लेकिन उसे नींद पापा के कंधे पर आती।

रोहन और माया की कहानी अब केवल उनकी नहीं थी। राशि के साथ, उनका जीवन एक नई कविता, सुख भरी कहानी बन चुका था, जिसमें हर दिन एक नया छंद/ कथानक जुड़ता सभी पास पड़ोसी, रिश्तेदार राशि के पहले जन्म दिन पर जवाहर चौक भोपाल आए। बर्थडे केक रोहन – माया ने राशि के हाथ पकड़ कर कटवाया तो सभी महबान गा उठे, बार बार ये दिन आए,,,। रोहन और माया ने न केवल अपनी बेटी के लिए, बल्कि हर उस बच्चे के लिए एक दुनिया रची, जो सपनों में विश्वास करता है। उनका जीवन पथ अब भी प्रगति के पथ पर अग्रसर है चुनौतियों और खुशियों के साथ। लेकिन हर कदम पर, रोहन की कविताएँ, माया के चित्र, और राशि की मुस्कान उनकी कहानी को और सुंदर बनाती है।

देखते देखते राशि तीन साल कि हो गई। एक शाम रोहन, माया अपने स्कूटर पर राशि को आगे खड़ा करके जहांगीराबाद अपने रिश्तेदार से मिलकर घर लौट रहे थे कि एक बकरी का बच्चा स्कूटर से टकराया,,,,कि

(भाग6)

राजेन्द्र रंजन गायकवाड

लोगों के बोल - कांग्रेस का घुसपैठियों से प्रेम संबंध आज़कल का नहीं, काफ़ी पुराना और ऐतिहासिक हैं - 1983 में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने बांग्लादेशी घुसपैठियों को बचाने के लिए IMDT Act लागू किया था

उत्तर प्रदेश, संजय साग़र सिंह। बांग्लादेशी घुसपैठ अब भी एक यथार्थ खतरा है, खासकर सीमावर्ती और शहरी इलाकों में, इससे बिल्कुल स्पष्ट है कि यह केवल एक क़ानूनी मुद्दा नहीं, राष्ट्रीय अस्तित्व और भविष्य की दिशा का प्रश्न है। घुसपैठ और IMDT Act, 1983 जैसे कानूनों पर, खासकर राष्ट्रीय सुरक्षा, जनसांख्यिकीय असंतुलन, और स्थानीय नागरिकों के अधिकारों को लेकर देश में लंबे समय से बहस चलती रही है। इस गंभीर विषय पर लोगों का कथन एक संवेदनशील असुरक्षा के गंभीर मुद्दे की ओर इशारा करता है, जो भारत में लंबे समय से राजनीतिक, सामाजिक और देश की सुरक्षा विमर्श का हिस्सा रहा है।

आइए लोगों के साथ हुई आज़ की चर्चा में तथ्यों के साथ इस मुद्दे को समझते हैं। लोगों ने बताया कि कांग्रेस का घुसपैथियों से प्रेम संबंध आज़कल का नहीं काफ़ी पुराना और ऐतिहासिक हैं। 1983 में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने बांग्लादेशी घुसपैठियों को बचाने के लिए (Illegal Migrants Determination by Tribunals) Act, 1983 – लागू किया था। इसका उद्देश्य यह था कि यह तय किया जा सके कि कोई ₹अवैध प्रवासी₹ और घुसपैठिये है या नहीं। जो घुसपैठियों की पहचान और निष्कासन के लिए लाया गया था लेकिन इसके प्रावधान इतने उलटे एवं कठिन और ढीले थे कि वे उल्टा घुसपैथियों के संरक्षण बन गए।

उन्होंने कहा - इस एक्ट में घुसपैठिया साबित करने की जिम्मेदारी पीड़ित या राज्य प्रशासन पर थी आरोपी घुसपैठिये की नहीं थी। यह भारतीय साक्ष्य क़ानून डॉ बाबा साहब के संबिधान से उल्टा था, हमारे संबिधान में दोष साबित करने की जिम्मेदारी आरोपी की होती है। लेक़नि 1983 में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के द्वारा लाये गए इस कानून की वजह से बांग्लादेशी घुसपैठियों को पहचानना और उन्हें देश से बाहर निकालना बेहद कठिन हो गया था। यह कानून बांग्लादेशी घुसपैठियों को देश से निकालने के लिए नहीं बल्कि राजनीतिक कारणों से बचाने के लिए लाया गया था और इस ढीले क़ानून का दुरुपयोग करके करोड़ों अवैध घुसपैठिए भारत को घर्मशाला समझ के देश में बस गए।

IMDT Act, 1983 - इंदिरा गांधी का बनाया वो कानून था जिसने बांग्लादेशी घुसपैठियों को भारत में बसाने का रास्ता खोला और करोड़ों घुसपैठिए IMDT की आड़ लेकर भारत में घुस आए वो पहले असम, विहार, झारखण्ड, उत्तरप्रदेश फ़रि बंगाल और अब पूरे भारत देश के असली नागरिकों के हक़ अधिकारों को चुरा के देश को कमजोर कर रहे है!

उन्होंने आगे बताया कि यह कानून असम आंदोलन (1979–1985) के दौरान और बाद में काफी विवादित रहा। इसका असर यह हुआ कि असम, पश्चिम बंगाल, बिहार, यूपी, त्रिपुरा, मेघालय और केरल जैसे राज्यों में जनसांख्यिकीय बदलाव साफ दिखने लगे। स्थानीय नागरिकों की नौकरियाँ, काम-धंधे, रोज़ी-रोटी, रोजगार, ज़मीन, हक़-अधिकार और संसाधन छिनने लगे। धार्मिक और सामाजिक संतुलन प्रभावित हुआ। कई जगह हिंसा, दंगे और सांप्रदायिक तनाव पैदा हुए। धीरे-धीरे करोड़ों अवैध घुसपैठिए दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, बेंगलुरु, कलकत्ता, केरल सहित पूरे देश में फैलने लगे।

तब सुप्रीम कोर्ट ने प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की सरकार पर घुसपैठ को रोकने में विफलता का आरोप लगाया और 2005 में सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला आया। इस IMDT Act को असंवैधानिक घोषित करते हुए रद्द कर दिया और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह कानून ₹राष्ट्र की अखंडता और सुरक्षा₹ के खिलाफ है।

देश की सुरक्षा और नागरिकता का सवाल:

उन्होंने यह भी कहा, डॉ बाबा साहब का संबिधान भारत में रहने वाले हर वास्तविक और असली नागरिक के हक़ अधिकारों की रक्षा करता हैं, लेक़नि अवैध घुसपैठ से देश पर आर्थिक बोझ, असुरक्षा, भीतरघाती खतरा, और राजनीतिक अस्थिरता जैसी तमाम समस्याएं पैदा होती है। अबैध संख्या और लाईन बढ़ने से, इस विकराल समस्या के कारण देश के असली और सच्चे भारतीय नागरिकों को काम-धंधे, रोज़ी-रोटी, नौकरी, रोज़गार, बिजली, पानी, राशन, दवाएं, स्वास्थ्य सुविधाएँ और घर, मकान, जमीन उपलब्ध होने में भी दिक्क़ते आती हैं, तो देश का लोकतंत्र और असली नागरिकों के बैसिक हक़ अधिकार भी कमजोर होते है।

आज की स्थिति क्या है?

NRC (National Register of Citizens) और CAA (Citizenship Amendment Act) जैसे प्रयास अबैध संख्या और लाईन बढ़ने की इस विकराल समस्या से निपटने की कोशिश हैं, लेकिन देश विरोधी राजनीति और आपसी टकराव इसमें बड़ा रोड़ा बन रहे हैं। जबकि ये राष्ट्र की अखंडता एवं सुरक्षा और स्थानीय नागरिकों के हक़-अधिकार की रक्षा के लिए बहुत ज़रूरी हैं।

शहरी क्षेत्रों में प्रभावः उन्होंने यह भी बताया कि कई बांग्लादेशी घुसपैठिये अवैध रूप से दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, बेंगलुरु, कलकत्ता जैसे बड़े शहरों में आकर बस गए। इन इलाकों में वे श्रमिक, घरेलू सहायक, रिक्शा चालक, कबाड़ी आदि जैसे पेशों में दिखते हैं। कुछ मामलों में ये लोग नकली दस्तावेज़ों के ज़रिये भारत की नागरिक सुविधाएं भी प्राप्त कर लेते हैं।

बांग्लादेशी घुसपैठः यथार्थ खतरा?

वर्तमान स्थितिः साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि बांग्लादेशी घुसपैठ पर कई रिपोर्टें यह दर्शाती हैं कि सीमावर्ती राज्यों - जैसे कि असम, पश्चिम बंगाल, बिहार, यूपी, झारखण्ड, त्रिपुरा, मेघालय और केरल सहित अन्य राज्यों में यह एक वास्तविक समस्या रही है। हालांकि सुरक्षा एजेंसियां और BSF ने निगरानी कड़ी की है, लेक़नि राजनीतिक टकराब के कारण अनुमानित सीमा लंबाई में से लगभग 800 किमी अवरुद्ध (fenced) नहीं की जा सकी है। porous borders और स्थानीय राजनीतिक मिलीभगत के चलते यह समस्या पूरी तरह खत्म नहीं हुई। तमाम राजनीतिक अडचनों के बाबजूद इसके लिए मोदी सरकार ने एक विशेष निगरानी परियोजना लागू करने की तैयारी कर रही हैं।

4. सुरक्षा और रणनीतिः भारत सरकार व BSF की तकनीकी/सामरिक पहलकदमी

कंक्रीट बाड़ और तकनीकी निगरानीः BSF दक्षिण बंगाल फ्रंटियर (लगभग 913 किमी) पर PTZ (Pan-Tilt-Zoom) कैमरे और रात-देखने वाले सेंसर लगाए हैं, जो बिना बाड़ व क्षेत्रीय कमजोरी वाले क्षेत्रों में निगरानी में मदद करते हैं।

विशेष निगरानी परियोजनाः भारत-बांग्लादेश सीमा (और पाकिस्तान सीमा) के लगभग 600 'vulnerable patches' पर इन्फ्रारेड सेंसर, अलार्म और अतिरिक्त मानवबल तैनात करने की योजना लागू की गई है। सुरक्षा समन्वय और वार्ताः हाल में BSF और बांग्लादेशी सीमा प्रहरी (BGB) के बीच सीमा सुरक्षा, अवैध गतिविधियों और संपर्क बढ़ाने पर द्विपक्षीय चर्चा हुई।

वोट-बैंक पॉलिटिक्स की भूमिका

लोगों ने आरोप लगाते हुए बताया कि बंगाल तृणमूल कांग्रेस "अप्पीज़मेंट पॉलिटिक्स" के चलते बंगालदेशी घुसपैठ को बढ़ावा दे रही है और फर्जी दस्तावेजों के ज़रिए अबैध शरणर्थियों और बंगलादेशी घुसपैथियों को भारत की नागरिकता दिला रही है इसीलिए पश्चिम बंगाल में NRC के खिलाफ 'नो NRC मूवमेंट' का नेतृत्व TMC ने किया था और आगामी चुनाव में ममता अभी हिंदी और बंगाली भाषा का टकराब भी कराएगी।

जनसंख्या आंकड़ेः अनुमानित संख्या और राज्यों में बसी आबादी

2004 में गृह राज्य मंत्री श्रीप्रकाश जयस्वाल ने संसद में कहा कि लगभग 1.2 करोड़ (12 million) अवैध बांग्लादेशी अवैध प्रवासी भारत में रह रहे हैं, जिनमें से 6 million पश्चिम बंगाल में थे। लेक़नि कांग्रेस के ढीले प्रावधानों उलटे संरक्षक कानूनों की बजह से आज़ पुरे देश में लगभग 6 करोड़ से भी अधिक घुसपेथीयें और अवैध प्रवासी भारत में असली नागरिकों के हक़ अधिकार चोरी करके बड़े आराम से रह रहे हैं। त्रिपुरा, बिहार (सीमांचल क्षेत्रः किशनगंज, अररिया, कटिहार, पूर्णिया), झारखण्ड, उत्तर प्रदेश आदि में भी बड़ी संख्या में बांग्लादेशी अवैध प्रवासी पाए जाते रहे हैं।

डेंगू निरोधक (रोकथाम)

डेंगू अथवा 'डेंगी' / 'डेंगू बुख़ार' / 'डेंगू फीवर' / 'डेंगू ज्वर'

एक ख़तरनाक संक्रामक रोग है। डेंगू को ₹हड्डी तोड़ बुख़ार₹ के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इसके कारण शरीर व जोड़ों में बहुत दर्द होता है। मलेरिया की तरह डेंगू बुख़ार भी मच्छरों के काटने से फैलता है। डेंगू सभी मच्छर से नहीं फैलता है। यह केवल कुछ जाति के मच्छर से फैलता है। इस रोग का वाहक एड़ीज मच्छर की दो प्रजातियां हैं- एडीज एजिपटाई (Aedes aegypti) तथा एडीज एल्बोपेक्टस के नाम से जाने जाते हैं।

>> डेंगू बुखार के कारण <<

डेंगू बुखार दिन में काटने वाले

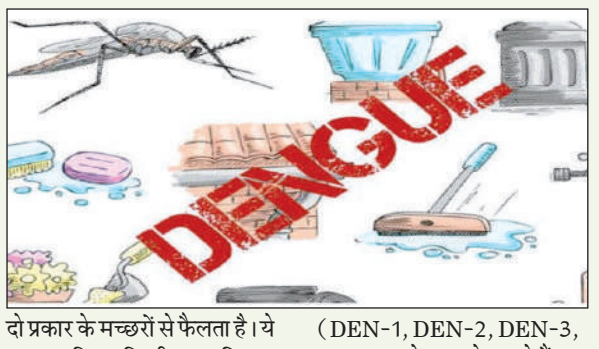

दो प्रकार के मच्छरों से फैलता है। ये मच्छर एडिज इजिप्टी तथा एडिज एल्बोपेक्टस के नाम से जाने जाते हैं। Dengue Fever "डेंगू" वायरस के संक्रमण द्वारा होता है, इसे "डेन वायरस" भी कहते हैं। डेंगू वायरस चार प्रकार के होते हैं, जिसे डेन-1, डेन-2, डेन-3 और डेन-4 (DEN-1, DEN-2, DEN-3, DEN-4) के नाम से जानते हैं। DEN 1 और DEN 3 के मुकाबले DEN 2 और DEN 4 कम खतरनाक होते हैं।

डेंगू सभी मच्छर से नहीं फैलता। यह केवल कुछ जाति के मच्छर से ही फैलता है जो कि मुख्यतः "फ्लाविविरिडे" परिवार तथा "फ्लाविविरस" जीन का हिस्सा होते हैं।

>>डेंगू रोकथाम<<

क्योंकि यह मच्छर के काटने से होता है इसलिए मच्छरों को पैदा होने से रोकना ही इसका मुख्य बचाव है। इसके अलावा बारिश के मौसम व इसके बाद शरीर को ढक कर रखने चाहिए जिससे मच्छर काट न सकें

उपचार के रूप में शारीरिक सहन क्षमता (इम्यूनिटी) मुख्य रूप से निर्णायक भूमिका निभाती है इसके लिए गिलोय का सेवन अमृत के समान है

विशेषतः इस रोग में लापरवाही बिल्कुल न बरतें अन्यथा यह शीघ्र ही जानलेवा हो सकता है।

कमर दर्द का रामबाण

महिलाओं और पुरुषों में कमर दर्द महामारी की तरह फ़ैल चुका है, रात में जरा सी कूलर की हवा लग जाए या ठंडक हो जाए तो सुबह उठना बैठना मुश्किल हो जाता है, वायु के कारण होने वाले जोड़ो, हाथ पैरो के दर्द, साइटिका आदि सब में यह फयदा करेगा। महिलाओं की एक आम समस्या श्वेत प्रदर (सफ़ेद पानी) की यह ख़ास दवा है। मासिक के समय में भयंकर कमजोरी आ जाती है सारा दिन निढाल पड़े बीत जाता है तो यह लड्डू ठीक कर देगा, हाथ पैरों का कांपना झुनझुनी, सुन्नपन, ऐठन आदि सब ठीक हो जाता है. गर्भाशय के कई रोगों में यह काम करता है।

निर्माण विधि आधा किलो गाय के दूध में दो चम्मच पिसी सोंठ मिलाकर उबालें और ठंडा हो जाने पर इसमें साफ़ किये हुए आधा किलो मेथी दाना भिगो दें जब मेथी दाना ठीक से फूल जाए तो इसको तेज धूप में सुखा लें, भली भाति सूख जाने पर महीन पीसकर देसी घी में हल्का भून लें।

छोटीपिप्पर, सोंठ, कालीमिर्च, दालचीनी सब 15-15 ग्राम लेकर महीन कूट पीसकर रख लें।

डेढ़ किलो देसी शक्कर (लाल वाली) या खांड महीन पीसकर रख ले।

250 ग्राम बबूल गोंद साफ़ करके देसी घी में भून कर कूट कर तैयार कर लें।

खसखस 50 ग्राम मध्यम आंच पर भून लें।

सिंघाड़े का आटा एक किलो लेकर इसे भी देसी घी में हलकी आंच पर तब तक भूने जब तक रंग हल्का लाल और सुगंध न आने लगे। अब इसी गरम आटे में सब चीजे मिला कर ठीक से घुटाई कर लें और लड्डू बनाकर रख लें। इसको बनाते समय पानी का इस्तेमाल नहीं करना है कुछ लोग चाशनी बनाकर उसमे लड्डू बनाते है जो बाद में इतना सूख जाता है की खाते नही बनता।गरम आटे में सब सामग्री मिलाने से लड्डू बन जाते है फिर भी कोई परेशानी हो तो थोड़ा सा घी मिला लें. मैंने जब बनाया तो लड्डू बाँधने की बजाय पंजीरी जैसा बनाया वह भी खाने में अच्छा लगता है। मात्रा एवं सेवन विधि लगभग 20 ग्राम तक मात्रा में प्रातः सायं नाश्ते के समय लें. इसको खाने के बाद दूध पीना अधिक उपयोगी है!

बच्चा जिस परिवेश में पलता है, जिस भाषा को सुनता है, जिसमें बोलना सीखता है उससे उसका एक घनिष्ठ संबंध/अपनत्व हो जाता है।

यदि वही भाषा उसकी शिक्षा का माध्यम बनती है तो वह विद्यालय में आत्मीयता का अनुभव करने लगता है। उसे किसी भी विषय को समझने के लिए अधिक मेहनत नहीं करनी पड़ती। दूसरी भाषा में किसी बात को सीखने-समझने में लगने वाला समय उसका बच जाता है। हमारे मनीषी कहतें हैं कि राष्ट्रीयता गहराई से टिकाये रखने के लिए किसी भी देश के बच्चों को उसकी नीची या ऊँची कक्षा की, समस्त/सारी शिक्षा उनकी मातृभाषा के जरिये ही मिलनी चाहिए। यह स्वयं सिद्ध बात है कि देश के नौजवान यदि अपनी भाषा में शिक्षा पाकर उसे पचा न लें जिसे हृदयंगम न कर लें, तब तक वह अपने देश की सभ्यता/संस्कृति के साथ, अपना जीता-जागता संबंध पैदा कर नहीं सकते। यह हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए कि हम अपनी प्रांतीय भाषाओं का उपयोग शुरु करें और हिन्दी को राष्ट्रभाषा के रूप में उसका स्वाभाविक गठजोड़ करें। प्रांतीय कामकाज प्रांतीय भाषाओं में करें और राष्ट्रीय/सामाजिक समस्त कामकाज हिन्दी में ही करें। हमारे देश/प्रांतों की भिन्न-भिन्न प्रांतीय भाषाओं का आपसी समन्वय बनाने के लिए हमारी संविधान-सम्मत, राष्ट्रीय भाषा हिंदी/देवनागरी लिपि को प्रभुता/सम्पन्नता स्थापित करना हमारा प्रमुख अधिकार एवं कर्तव्य बन जाता है। ध्यान रहे कि विदेशी भाषा जानना/सीखना प्रगति है, जैसे हम शरीर/स्वास्थ्य का ध्यान रखते हैं लेकिन अपनी सभी भाषाओं के साथ-साथ अपनी राष्ट्रीय राजभाषा में पारंगत होना, अपनी आत्मा का विकास करने जैसा है।

यमुना बाजार इलाके के बाढ़ग्रस्त क्षेत्र का दौरा किया मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने

मुख्य संवाददाता/ सुषमा रानी

नई दिल्ली। दिल्ली में यमुना नदी का जलस्तर बढ़ने और बाढ़ को देखते हुए मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता स्वयं पूरे हालात पर नजर रख रही हैं। आज उन्होंने एक बार फिर बाढ़ग्रस्त इलाके का दौरा किया और बाढ़ प्रबंधन व कंट्रोल सिस्टम का जायजा लिया। यमुना बाजार स्थित बाढ़ग्रस्त बस्ती में मुख्यमंत्री नंगे पांव बाढ़ के पानी में उतर गईं। उन्होंने बाढ़ से पीड़ित लोगों से बात की और आश्वासन दिया कि सरकार उनके साथ है। मुख्यमंत्री का यह भी कहना था कि दिल्ली के यमुना से सटे इलाकों में बाढ़ की स्थिति नियंत्रण में है।

मुख्यमंत्री आज सुबह यमुना बाजार स्थित प्राचीन हनुमान मंदिर के सामने बनी बस्ती में पहुंची। उनके साथ बाढ़ से जुड़े विभागों के आला अधिकारी भी मौजूद थे। मुख्यमंत्री वहां पहले सीढ़ियों से दीवार की ओर पहुंची। उन्हें अंदर बस्ती के लोग छतों व आसपास बाढ़ के पानी के बीच नजर आए। उनके पीछे बाढ़ का तेज पानी लहलहा रहा था। पीड़ित लोगों को देखकर मुख्यमंत्री रुक नहीं पाई। उन्होंने जूतियां उतारी और नंगे पैर बाढ़ के पानी में उतर गईं। किसी को भी यकीन नहीं था कि मुख्यमंत्री अचानक बाढ़ के पानी में उतर जाएंगी। उन्हें बाढ़ के पानी में चलता देख पीड़ित लोग भी उनके पास आने को आतुर नजर आए। मुख्यमंत्री ने उनका हालचाल पूछा और बताया कि सरकार बाढ़ पर निगरानी रखे हुए है। किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए सरकार की ओर से पूरी तैयारियां हैं। मुख्यमंत्री ने उन्हें आश्वस्त किया कि दिल्ली सरकार उनके साथ खड़ी है। सरकार बाढ़ पीड़ितों को हरसंभव मदद उपलब्ध कराएगी। मुख्यमंत्री बाढ़ग्रस्त इलाकों ओर पानी के बीच करीब आधे घंटे तक रहीं।

मुख्यमंत्री गुप्ता ने जानकारी दी कि यमुना नदी का जलस्तर आज सुबह कुछ समय के लिए 206 मीटर को छूने के आसपास था। लेकिन अब स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है। उन्होंने बताया कि यह क्षेत्र यमुना के फ्लड प्लेन का लो-लाइन इलाका है, इसलिए पानी यहां तक पहुंच गया, लेकिन इससे आगे नहीं बढ़ा। उन्होंने स्पष्ट किया कि दिल्ली में बाढ़ जैसी कोई भी स्थिति नहीं है। यह जलस्तर का अधिकतम चढ़ाव था और अब पानी उतरने की दिशा में है। स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में है। मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि प्रशासन लगातार कंट्रोल रूम से बाढ़ के हालात की निगरानी कर रहा है। वैसे बाढ़ का पानी जिस गति से आ रहा है, उसी अनुपात में आगे निकल भी रहा है। मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि यहां रहने वाले परिवारों से सरकार ने अनुरोध किया था कि वे अस्थायी रूप से सुरक्षित स्थानों पर चले जाएं, लेकिन कई लोग अभी भी वहीं पर रह रहे हैं। फिलहाल बाढ़ की स्थिति नियंत्रण रखी जा रही है। आवश्यकता होगी तो लोगों को यहां से निकालकर वैकल्पिक आवासों तक पहुंचाया जाएगा। मुख्यमंत्री ने विश्वास जताया कि यमुना का जलस्तर अब तेजी से नीचे जाएगा और लोगों को किसी गंभीर असुविधा का सामना नहीं करना पड़ेगा।

भाजपा ने दिल्ली में किया तिरंगा घोटाला, फर्जी राष्ट्रभक्ति की खुली पोल- संजय सिंह

मुख्य संवाददाता

नई दिल्ली। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में हुए करोड़ों रुपए के तिरंगा खरीद घोटाले को लेकर भाजपा की देशभक्ति पर सवाल खड़ा किया है। ''आप'' के वरिष्ठ नेता संजय सिंह ने कहा कि रेखा गुप्ता सरकार द्वारा दिल्ली में तिरंगा झंडा खरीद में घोटाला करने के बाद अब भाजपा के फर्जी राष्ट्रभक्ति की पोल खुल चुकी है। हर घर तिरंगा अभियान के तहत भाजपा सरकार ने 4 करोड़ रुपए के 7 लाख तिरंगे बांटने थे, लेकिन उसने टेंडर में तय साइज से छोटा तिरंगा लोगों में बांट दिया। सिर्फ इतना ही नहीं, तिरंगे को 15 अगस्त से पहले हर घर तक पहुंचाना था, लेकिन सरकार ने टेंडर ही 16 अगस्त को खोला और टेंडर खुलने से पहले ही कंपनी ने 60 रुपए के झंडे की जगह 15 रुपए वाला झंडा भाजपा सरकार को सप्लाई कर दिया।

मंगलवार को ''आप'' मुख्यालय पर प्रेसवार्ता कर सांसद संजय सिंह ने कहा कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी होने का दावा करने वाली, राष्ट्रवाद का ढिंढोरा पीटने वाली और राष्ट्र भक्ति व देशभक्ति पर दूसरे दलों के नेताओं को रोज अपमानित करने वाली भाजपा का एक ऐसा घोटाला सामने आया है, जिसे सुनकर पूरा देश हैरान हो जाएगा। आखिर कोई पार्टी भाजपा की आन-बान और शान तिरंगे झंडे की खरीद में कैसे घोटाला कर सकती है? भाजपा ने तिरंग झंडा खरीदने में भी घोटाला कर दिया। ऐसा घोटाला देश की जनता ने कभी नहीं सुना होगा। लेकिन यह घोटाला सीएम रेखा गुप्ता के नेतृत्व में दिल्ली की भाजपा सरकार ने किया। रेखा गुप्ता सरकार ने भारत की आन, बान और शान तिरंगा झंडा खरीदने में घोटाला किया है।

उन्होंने मीडिया को दस्तावेजी सबूत दिखाते हुए कहा कि हर घर तिरंगा योजना के तहत दिल्ली की भाजपा सरकार को 7 लाख तिरंगा झंडा बांटना था, जिसकी कुल कीमत 4 करोड़ रुपए था। तिरंगा झंडे की साइज 900 मिलीमीटर गुणा 1350 मिलीमीटर थी। तिरंगे झंडे को 6 फीट के डंडे के साथ सरकार को सप्लाई करना था। कंपनी को 900 मिलीमीटर चौड़ा और 1350 मिलीमीटर लंबा झंडा 6 फीट के डंडे के साथ सप्लाई करना था। लेकिन ढोंगी देशभक्तों की पार्टी भाजपा ने झंडे और डंडे में भी घोटाला कर लिया। लेकिन झंडे की निर्धारित साइज को घटाकर 711 मिलीमीटर लंबा और 508 मिलीमीटर चौड़ा कर दिया और डंडे की साइट 6 फीस से घटाकर 4 फीट कर दिया। भाजपा सरकार ने तिरंगे के नाम पर झंडे-डंडे में घोटाला कर दिया।

उन्होंने कहा कि तिरंगे की सप्लाई करने को लेकर जारी टेंडर में तीन कंपनियों ने भाग लिया। अनिरत कांट्रैक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, स्पेश फॉर बिजनेस सोल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड और विनायक प्रोडक्ट कंपनी ने टेंडर में भाग लिया। तिरंगे डंडे का टेंडर 4 करोड़ रुपए का था और बिना टेंडर खोले अनिरत कांट्रैक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड से कमीशन लेकर उसको तिरंगे झंडे की सप्लाई का ऑर्डर दे दिया गया। एक झंडे की कीमत 60 रुपए रखी गई थी, लेकिन कंपनी ने 60 रुपए की जगह 15 रुपए का झंडा दिल्ली की भाजपा सरकार को दे दिया। लेकिन इन बेइमानों को कोई फर्क नहीं पड़ा। आश्चर्य की बात यह है कि 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस था, लेकिन टेंडर 16 अगस्त को खोला गया।

संजय सिंह ने पीएम नरेंद्र मोदी, भाजपा और सीएम रेखा गुप्ता से पूछा कि क्या आप लोगों में कोई भी शर्म नहीं बची है। रोज तमाम चीजों में घोटाला तो करते ही हैं, कम से कम भारत की आन, बान और शान राष्ट्रीय तिरंगे को तो बक्श देते। कम से कम हमारे शहीदों की आत्माओं को तो बक्श देते। कम से कम स्वतंत्रता दिवस पर याद किए जाने वाले वीर सपूतों की याद में एक सही कार्यक्रम कर लेते। तिरंगा झंडा की खरीद में भी चोरी, बेइमानी और भ्रष्टाचार कर रहे हैं, इससे ज्यादा शर्मनाक बात और क्या हो सकती है? झंडा खरीद की गहनता से जांच होनी चाहिए और जिम्मेदार लोगों को गिरफ्तार कर जेल में डालना चाहिए।

काउंसलर अफरीन ने अपना कीमती समय निकालकर फ़न वे लर्निंग एनजीओ के बच्चों को टीबी के बारे में जानकारी दी।

संघी गिरोह का हिटलरी राष्ट्रवाद!

हमारे राष्ट्रगान के रचयिता कविवर रविंद्रनाथ ठाकुर (टैगोर) ने एक बार कहा था -- ₹नेता जब अपने दल का झंडा पकड़कर गांव और शहर की गलियों में घुस नहीं पाता, तब अपने हाथों में राष्ट्र का झंडा पकड़ लेता है, ताकि जनता उसे ही राष्ट्र समझने की गलती कर दें। मुझे डर लगता है कि पश्चिम के राष्ट्रवाद के गर्भ से पैदा हिटलर किसी दिन राष्ट्रवाद की ओट लेकर भारत नहीं पहुंच जाएं।₹ टैगोर की लगभग सौ साल पहले दी गई चेतावनी आज सच साबित हो गई है। भारत में हिटलरी राष्ट्रवाद पहुंच गया है और इसके प्रतिनिधि के रूप में भाजपा नेताओं के हाथ में तिरंगा लहरा रहा है। जो दल हमारे आधुनिक राष्ट्र की धर्मनिरपेक्ष बुनियाद और संवैधानिक मूल्यों को ही छिन्न-भिन्न करने का खेल खेल रही है, विविधता में एकता के बहुलतावाद को खत्म करके उसे एकरंगी बहुसंख्यकवाद में बदलने की कोशिश कर रही है, वहीं दल आम जनता की देशभक्ति की भावना से सबसे ज्यादा खिलवाड़ कर रही है और इस खिलवाड़ को ही राष्ट्रवाद के रूप में स्थापित करने की कोशिश कर रही है। यदि भाजपा अपने खेल में सफल हो जाती है, तो निश्चित मानिए, एक आधुनिक और वैज्ञानिक चेतना संपन्न राष्ट्र के निर्माण में 'हम भारत के लोग' असफल हो जायेंगे।

यह असफलता हमारा दरवाजा खटखटा रही है। धीरे-धीरे ही सही, गाँधी के साथ सावरकर के फोटो भी सजने लगी हैं, जिसे हमने स्वाधीनता दिवस के उत्सव में कुछ जगहों में इस बार देखा है। पेट्रोलियम मंत्रालय द्वारा इस बार स्वाधीनता दिवस के अवसर पर जारी विज्ञापन में सावरकर तिरंगे से भी ऊपर टंगे हुए हैं। लाल किले से हिटलरी राष्ट्रवाद के प्रतिनिधि प्रधानमंत्री ने आरएसएस का गुणगान कर ही दिया है, जिसका वास्तव में रिकॉर्ड आजादी के आंदोलन के साथ धोखेबाजी और अंग्रेजों की मुखबिरी का ही था। अब देश की युवा पीढ़ी को उच्च स्तर से ज्ञान संपन्न करने की कोशिश हो रही है कि आजादी का इतिहास गांधीजी और भगतसिंह से नहीं बनता, कांग्रेस और कम्युनिस्टों से नहीं बनता, बल्कि संघी गिरोह और उसके नायक सावरकर, गोलवलकर और गोडसे से बनता है।

ये लोग बार-बार देश के लोगों को यह बताना चाहते है कि काँग्रेस कमेटी में नेहरू को छोड़ सब पटेल को प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते थे। पर यह नहीं बताना चाहते है कि ये वे सरदार पटेल थे, जिन्होंने महात्मा गांधी की हत्या के लिए आरएसएस को सीधा जिम्मेदार ठहराया था, उसकी निंदा की थी और उस पर प्रतिबंध लगाया था। जो संघी गिरोह नेहरू बनाम पटेल का विवाद खड़ा करता है, उसे तो अव्वल इसी बात का जवाब देना चाहिए कि लालकृष्ण अडवाणी के रहते प्रधानमंत्री के रूप में झोला उठाकर चल देने वाले फकीर जी कैसे विराज गए? और राजनाथ सिंह जैसे आदमी से गृह मंत्रालय छीन कर अमित शाह को कैसे दे दिया गया, जिनकी गुंडागर्दी का रिकॉर्ड उनके सामने ही संसद में बखान किया जाता है?

संघी गिरोह और मोदी की ईमानदारी का सबूत तो पहले चंडीगढ़ के मेयर के चुनाव में और अब हरियाणा की एक प्रधानी के चुनाव में ही दिख गया है। अब बिहार का चुनाव सामने है। वहाँ भी ये जिस ईमानदारी से चुनाव की तैयारी में लगे हैं, उसे लेकर चुनाव आयोग को सर्वोच्च न्यायालय आईना दिखा चुका हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र की भाजपा

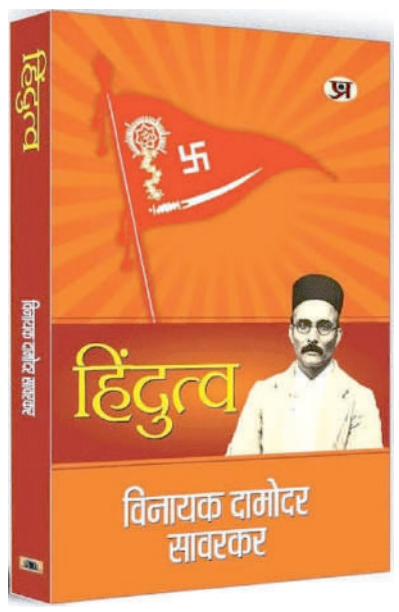

सरकार और उसकी बी-टीम बने चुनाव आयोग को अंतरिम आदेश दे दिया है कि जिन पैंसठ लाख लोगों को आपने मतदाता सूची से बाहर किया है, उनके नाम सार्वजनिक किए जाएं और उन सभी को मतदाता के रूप में पंजीकृत किया जाएं, जिनके पास आधार कार्ड हैं।

अब चुनाव आयोग की बोलती बंद है। राहुल गांधी द्वारा एक विधानसभा में वोट चोरी के सबूत उजागर किए जाने के बाद अब देश भर के मतदाता सूचियों की जो सीमित छानबीन की जा रही है, उससे राहुल द्वारा वोट चोरी के उजागर पैटर्न की ही पुष्टि हो रही है कि किस प्रकार चुनाव आयोग के साथ मिलीभगत करके भाजपा ने फर्जी तरीके से अपने समर्थकों के नाम मतदाता सूची में शामिल किए हैं और फर्जी मतदान करवाया है। इससे यह भी आशंका बलवती हो गई है कि पिछला लोकसभा चुनाव भाजपा ने जीत नहीं था, बल्कि फर्जी तरीके से विपक्ष को हराया गया है। यह आशंका जितनी बलवती होगी, मोदी सरकार की वैधता भी उतनी ही कमजोर होगी।

इस सरकार का फर्जीवाड़ा जितना उजागर हो रहा है, उतनी ही जोर-शोर से राष्ट्रवाद के नारे लगाते हुए वह अपनी वैधता बनाए रखने की कोशिश कर रही है। लेकिन संकट इतना गहरा है कि इस राष्ट्रवाद के भी चिथड़े उड़ते नजर आ रहे हैं। संघी गिरोह का राष्ट्रवाद कितना 'राष्ट्रवादी' है, इसका पता अमेरिकी साम्राज्यवाद के आगे उसके घुटनाटेकू रवैए से साफ जाहिर होता है, जिसकी मांग पर देश की संपत्ति को बेचा जा रहा है और विदेशी मालों के लिए इस देश के बाजार को खोला जा रहा है, खेती-किसानी को चौपट किया जा रहा है। इसका नतीजा आम जनता को महंगाई, बेरोजगारी, गरीबी के रूप में भुगतना पड़ रहा है। आज जनता खैरात पर जिंदा है और उसका स्वाभिमान कहीं खो गया है।

लेकिन यही संकट है, जिस पर जनता को लामबंद करके संघी गिरोह के नकली राष्ट्रवाद को मात दी जा सकती है। इस देश के हर नागरिक को मतदाता के रूप में पंजीकृत होने और हर मतदाता के बुनियादी नागरिक अधिकारों की लड़ाई को आगे बढ़ाने का रास्ता इसी लामबंदी से निकलेगा।

शोतोकान कराटे बेल्ट ग्रेडिंग टेस्ट पुरस्कार समारोह में राघव को फाइटर व वंश कुमार को स्टूडेंट ऑफ द ईयर का खिताब दिया गया

मुख्य संवाददाता

यूनिवर्सल मार्शल आर्ट्स, चण्डीगढ़ ने शोतोकान कराटे बेल्ट ग्रेडिंग टेस्ट पुरस्कार समारोह का आयोजन किया, जिसका उद्देश्य शोतोकान कराटे की कला को आत्मरक्षा और व्यक्तित्व विकास के एक अनुशासन के रूप में बढ़ावा देना है। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए इंटरनेशनल अकादमी ऑफ़ शोतोकान कराटे (आईएएसके) दिल्ली के चीफ़ इंस्ट्रक्टर रविंदर कुमार ने कहा कि कराटे और आत्मरक्षा प्रशिक्षण को बड़े स्तर पर बढ़ावा दिया जा सके।

यूनिवर्सल मार्शल आर्ट्स के निदेशक एवं मुख्य कोच सतीश कुमार ने बताया कि संस्था का लक्ष्य पूरे भारत में स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों तथा आम जनता के बीच शोतोकान कराटे का प्रशिक्षण फैलाना है, ताकि लोग आत्मरक्षा के महत्व को समझ सकें और सुरक्षित एवं स्वस्थ जीवन की ओर बढ़ सकें।

इस अवसर पर विशिष्ट अतिथि पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता एवं यूनिवर्सल ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन (यूएचआरओ) के चेयरमैन अशोक बेक्टर ने कराटे और आत्मरक्षा प्रशिक्षण को विद्यार्थियों और समाज में बढ़ावा देने में पूरा सहयोग देंगे। इस मौके पर गेस्ट ऑफ ऑनर सिटीजन अवेयरनेस ग्रुप के अध्यक्ष सुरेंद्र वर्मा ने बच्चों को प्रोत्साहित किया कि इस क्षेत्र में नाम और शोहरत पाने के लिए कठिन प्रैक्टिस की जरूरत है।इस बेल्ट ग्रेडिंग टेस्ट में विभिन्न शहरों से 200 छात्रों ने भाग लिया, जिनमें से 150 योग्य छात्रों को सफलतापूर्वक अगले स्तर पर पदोन्नत किया गया। सतीश कुमार ने विद्यार्थियों को प्रेरित किया कि वे आत्मरक्षा और मार्शल आर्ट्स वेपन ट्रेनिंग में आगे आएं, क्योंकि नियमित अभ्यास आत्मविश्वास को बढ़ाता है, तनाव कम करता है और शरीर व मन को ऊर्जावान बनाता है।

इस अवसर पर जतिन कुमार (रॉकी) को बेस्ट फाइटर, राघव को फाइटर व वंश कुमार को स्टूडेंट ऑफ द ईयर का खिताब दिया गया। सतीश कुमार ने बताया कि विशेष प्रशिक्षक सतपाल, परवीन कुमार और जतिन कुमार ने विद्यार्थियों को उच्च स्तरीय प्रशिक्षण देने के लिए कड़ी मेहनत की। उनके मुताबिक यूनिवर्सल मार्शल आर्ट्स में प्रवेश 4 वर्ष की आयु से ही शुरू हो जाता है, जिसमें छोटे बच्चे भी समय पर मार्शल आर्ट का लाभ उठा सके।

ओखला में शिक्षा पर मंथन, जल्द खुलेगा 'आज़मी एजुकेशन सेंटर'

परिवहन विशेष न्यूज

नई दिल्ली: ओखला क्षेत्र में शिक्षा को लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में डॉ ज़मीर आज़मी , अबरार अहमद मक्की, शमशाद आज़मी,साजिद मुजीब ,एडवोकेट शहंशाह , अहसन आज़मी, अकमल लैब आज़मी, अजमल , आज़मी साहब , हामिद संजरी, इरफान भाई, कमाल हाशमी, मोहम्मद ग़ानिम ख़ान, नुसरत सुल्ताना, रईस आलम, रेहाना तनवीर,शमा खान , साजिद अली, शबनम मोमिन, शाइस्ता ख़ान और शम्स आग़ाज़ रमीज़ रज़ा सहित कई समाजसेवी और शिक्षा से जुड़े लोग मौजूद रहे।

बैठक में फ्री एजुकेशन के मुद्दे पर विस्तार से चर्चा की गई और आगे की रणनीति तैयार की गई। वक्ताओं ने जोर देकर कहा कि शिक्षा हर

बच्चे का मौलिक अधिकार है और इसे समाज के हर तबके तक पहुँचाना सामूहिक जिम्मेदारी है। ओखला जैसे इलाकों में बड़ी संख्या में बच्चे हैं जो आर्थिक कठिनाइयों के कारण पढ़ाई पूरी नहीं कर पाते।

इस मौके पर हीलिंग हैंड्स चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से घोषणा की गई कि संस्था बहुत जल्द ₹आज़मी मेडिकल सेंटर₹ की तर्ज पर ₹आज़मी एजुकेशन सेंटर₹ की शुरुआत करने जा रही है। इस शिक्षा केंद्र में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चों को निःशुल्क और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराई जाएगी।

मीटिंग में लोगों ने इस पहल का स्वागत किया और कहा अगर निःशुल्क शिक्षा का केंद्र शुरू होता है तो यह बच्चों के भविष्य के लिए बहुत बड़ा कदम होगा।

बैठक में यह भी चर्चा हुई कि शिक्षा केंद्र को आधुनिक तकनीक, प्रशिक्षित शिक्षकों और करियर मार्गदर्शन कार्यक्रमों से सुसज्जित किया जाएगा ताकि बच्चों का सर्वांगीण विकास हो सके। समाज के विभिन्न वर्गों का मानना है कि यह कदम न सिर्फ़ बच्चों के लिए फायदेमंद होगा बल्कि खास कर ओखला क्षेत्र के सामाजिक और शैक्षिक विकास की नई दिशा तय करेगा।

एक समाज श्रेष्ठ समाज संस्था ने हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत घर घर जाकर तिरंगा लगाया

परिवहन विशेष न्यूज

नई दिल्ली: एक समाज श्रेष्ठ समाज संस्था अध्यक्ष योगेन्द्र कुमार साहू सदस्य मनीष साहू के नेतृत्व में संस्था के माध्यम से 79 वें स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी के आह्वान पर 13 अगस्त से 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत संस्था पदाधिकारियों ने हल्द्वानी में घर घर जाकर तिरंगा लगाया

इस दौरान एक समाज श्रेष्ठ समाज संस्था अध्यक्ष योगेन्द्र कुमार साहू सदस्य दीपक कुमार ने संयुक्त रूप से कहा कि 1947 में तिरंगा को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अपनाकर प्रत्येक भारतीय के लिए गौरव का क्षण प्राप्त हुआ है क्योंकि भारत का राष्ट्रीय ध्वज देश की स्वतंत्रता एवं लोकतांत्रिकता को दर्शाता है और यह भारत देश की एकता अखंडता प्रगति उन्नति समृद्धि खुशहाली का सूचक है इसलिए हम सभी भारतीयों का यह परम कर्तव्य है कि भारत माता भारतीय राष्ट्रीय

ध्वज के मान सम्मान के प्रति त्याग तपस्या समर्पण भाव के साथ कर्तव्य पथ पर सतत डटे रहने के लिए संकल्पित होकर यह संकल्प लें की हम सभी भारतीय एकता के एक सूत्र में बंधकर भारत देश को विश्वगुरु बनाने के लिए हम आस्था निष्ठा दृढ़ संकल्प शक्ति के साथ हमेशा धर्महित समाजहित भारतहित में कार्य करते रहेंगे इसीलिए शहीदों ने अपने अद्वितीय साहस और पराक्रम से भारत देश की गौरव गाथा को लिखा है उनका अद्भुत शौर्य हमारे स्वर्णिम इतिहास की एक मुकुटमणि है जो मातृभूमि की रक्षा और स्वाभिमान के लिए कैसी परिश्रम की पराकाष्ठा हो ये शहीदों का सम्पूर्ण जीवन हम सभी भारतीयों को दृढ़ संकल्प शक्ति साहस के सुपथ पर चलने और भारत माता कि सेवा करने के लिए हमेशा प्रेरित करता है जिससे हम भारतीय अपनी देशभक्ति को और विराट रूप से प्रखर कर भारत देश को विश्व के शिखर पर कीर्तिमान स्थापित करने में अपना अहम योगदान देकर भारत देश को विश्वगुरु बनाने में सहयोग करें जिससे विजयी विश्व तिरंगा प्यारा संपूर्ण ब्रह्मांड में बड़ी शान के साथ हमेशा लहराता रहे

इस दौरान तिरंगा लगने में एक समाज श्रेष्ठ समाज संस्था अध्यक्ष योगेन्द्र कुमार साहू सूरज मिस्त्री मनीष साहू निखिल कुमार दीपक कुमार सुशील राय अमन कुमार सूरज कुम्हार विजय डंगवाल मुकेश कुमार आदि लोग उपस्थित रहे।

आगरा के बुद्धा पार्क विकास को मिली 10 करोड़ की स्वीकृति, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से हुई सकारात्मक भेंटवार्ता

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का सकारात्मक निर्णय न केवल आगरा के पर्यटन विकास में एक नया अध्याय जोड़ेगा, बल्कि स्थानीय पिछड़ा एवं दलित समाज के हित में भी एक बड़ा कदम साबित होगा -- उपेन्द्र सिंह

आगरा, संजय साग़र सिंह। बुद्धा पार्क, आगरा के कायाकल्प की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने इसके विकास हेतु ₹10 करोड़ की धनराशि स्वीकृत की है। यह निर्णय भारतीय जाटव समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं भाजपा के वरिष्ठ नेता उपेन्द्र सिंह के नेतृत्व में हुआ एक महत्वपूर्ण संवाद और प्रयासों का परिणाम है।

दिनांक 3 अगस्त 2025 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से हुई 15 मिनट से अधिक समय की सौहार्दपूर्ण भेंटवार्ता में उपेन्द्र सिंह के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल ने ज्ञापन प्रस्तुत किया था। मुख्यमंत्री ने ज्ञापन में उल्लिखित प्रत्येक बिंदु को गंभीरता से लेते हुए सभी विषयों पर विस्तृत चर्चा की और त्वरित कार्रवाई का आश्वासन दिया।

भेंटवार्ता के उपरांत मुख्यमंत्री कार्यालय से कार्यवाही की प्रति प्राप्त हो चुकी है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि योगी सरकार ने विषय को प्राथमिकता से लिया है। इसके पश्चात सहायक नगर आयुक्त शिशिर कुमार से उपेन्द्र सिंह एवं नेत्रपाल सिंह ने बुद्धा पार्क परियोजना की प्रगति को लेकर विस्तार से चर्चा की।

18 अगस्त 2025 को मुख्यमंत्री के OSD से हुई फोनवार्ता में ज्ञापन के सभी बिंदुओं पर पुनः चर्चा हुई। उन्होंने जानकारी दी कि सभी मांगों पर आवश्यक प्रशासनिक कार्रवाई पूरी कर ली गई है तथा प्रगति से संबंधित रिपोर्ट शीघ्र ही प्रतिनिधिमंडल को उपलब्ध करा दी जाएगी।

इसके अतिरिक्त, आगरा के धनौली क्षेत्र के मजरा नगला कारे में 70 से अधिक आवासों के संदर्भ में भू-परिवर्तन की प्रक्रिया भी माननीय मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार प्रगति पर है, जिससे स्थानीय निवासियों को बड़ी राहत मिलने की संभावना है।

बुद्धा पार्क परियोजना की प्रगति को लेकर चर्चा पर भारतीय जाटव समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं भाजपा के वरिष्ठ नेता उपेन्द्र सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का सकारात्मक निर्णय न केवल आगरा के पर्यटन विकास में एक नया अध्याय जोड़ेगा, बल्कि स्थानीय पिछड़ा एवं दलित समाज के हित में भी एक बड़ा कदम साबित होगा।

पत्रकार और चिकित्सा सुरक्षा : केवल कार्ड नहीं, विश्वास की गारंटी भी हो

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त पत्रकारों और उनके आश्रितों के लिए 21–22 अगस्त को लखनऊ में दो दिवसीय शिविर आयोजित करने की घोषणा स्वागतयोग्य कदम है। स्टेट हेल्थ एजेंसी (सांची) द्वारा आयोजित इस शिविर में पत्रकारों को आयुष्मान कार्ड प्राप्त करने और पुराने कार्डों को अद्यतन कराने का अवसर मिलेगा। पहली नज़र में यह मात्र प्रशासनिक पहल लग सकती है, किन्तु इसके निहितार्थ कहीं गहरे हैं।

पत्रकार समाज लोकतंत्र की रीढ़ है। जो दिन-रात जनता के मुद्दे उठाता है, सत्ताधीशों से सवाल करता है और सूचनाओं को आमजन तक पहुँचाता है, वही तब सबसे अधिक असुरक्षित दिखता है जब बात उसकी स्वास्थ्य सुरक्षा की आती है। अनेक उदाहरण हैं जहाँ पत्रकार आर्थिक तंगी या उपचार की अनुपलब्धता के कारण कठिन परिस्थितियों का सामना करते रहे। ऐसे में यह योजना केवल "कार्ड वितरण" भर नहीं है, बल्कि यह संकेत है कि

पत्रकारों की सुरक्षा अब सरकार की प्राथमिकता में आ रही है।

फिर भी, कुछ प्रश्न अनिवार्य हैं।

* क्या यह पहल केवल डेटा-आधारित लाभ तक सीमित रहेगी या वास्तव में समय पर अस्पतालों में बेड, दवा और उपचार सुनिश्चित करेगी?

* क्या पत्रकारों को सरकारी और निजी अस्पतालों दोनों में समान रूप से सम्मानजनक व्यवहार मिलेगा?

* और सबसे महत्वपूर्ण — क्या योजना की पहुँच ग्रामीण और छोटे कस्बों के पत्रकारों तक भी उतनी ही सहज होगी, जितनी राजधानी के प्रेस क्लब तक है?

संपादकीय दृष्टि से यह भी कहना होगा कि "शिविर संस्कृति" किसी स्थायी समाधान का विकल्प नहीं हो सकती। स्वास्थ्य सुरक्षा एक निरंतर अधिकार है, कोई अस्थायी सुविधा नहीं। पत्रकार समाज के लिए यह अपेक्षा स्वाभाविक है कि स्वास्थ्य बीमा योजनाएँ न केवल तकनीकी रूप से सशक्त हों, बल्कि उनके क्रियान्वयन में पारदर्शिता और तत्परता भी हो।

अंततः, यह शिविर पत्रकारों को केवल कार्ड नहीं, बल्कि विश्वास दे सके — यही इसकी सबसे बड़ी सफलता होगी। क्योंकि जब लोकतंत्र की आवाज़ उठाने वाले स्वस्थ रहेंगे, तभी लोकतंत्र भी स्वस्थ रह पाएगा।

पति की जानबूझकर घरेलू कामों में अयोग्यता : बदलते रिश्तों का संकट

विवाह केवल साथ रहने का नाम नहीं, बराबरी की साझेदारी है। घरेलू काम भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं जितनी नौकरी या व्यवसाय। जानबूझकर अयोग्यता दिखाना रिश्तों को खोखला कर देता है। बराबरी से जिम्मेदारी बाँटना ही खुशहाल परिवार की नींव है। आधुनिक विवाह तभी टिकाऊ होगा जब साझेदारी और सम्मान दोनों हों।

डॉ. प्रियंका सौरभ

आधुनिक जीवनशैली ने जहाँ रिश्तों में नए अवसर खोले हैं, वहीं कई नई चुनौतियाँ भी खड़ी कर दी हैं। शिक्षा, रोजगार और तकनीक ने महिलाओं को पहले से अधिक स्वतंत्र और आत्मनिर्भर बनाया है। आज की महिला घर के दायरे से निकलकर नौकरी, व्यवसाय और प्रशासनिक जिम्मेदारियों तक सक्रिय रूप से पहुँच रही है। लेकिन विडंबना यह है कि घर की दहलीज़ के भीतर उसकी स्थिति उतनी नहीं बदली जितनी बदलनी चाहिए थी। अधिकांश परिवारों में अभी भी घरेलू कार्यों की जिम्मेदारी लगभग पूरी तरह से महिलाओं पर ही डाल दी जाती है।

इस समस्या का एक नया और चिंताजनक रूप सामने आया है – पति द्वारा घरेलू कामों में जानबूझकर अयोग्यता दिखाना। इसे पश्चिमी समाज में वेपनाइज्ड इनकंपिटेंस कहा जाता है, जिसका सीधा अर्थ है कि पति जानबूझकर घरेलू काम बिगाड़कर यह जताता है कि वह इन कार्यों में सक्षम ही नहीं है। नतीजतन पत्नी को ही दोबारा सब कुछ करना पड़ता है और धीरे-धीरे घर का पूरा बोझ उसी के कंधों पर आ जाता है।

कल्पना कीजिए कि पत्नी कहती है कि रसोई में सब्ज़ी बनाओ। पति नमक इतना डाल देगा कि खाना खाने लायक ही न रहे। या फिर कपड़े धोते समय वह रंगीन और सफेद कपड़े एक साथ डाल देगा ताकि वे खराब हो जाएँ। बच्चे को होमवर्क कराने की जिम्मेदारी मिले तो वह आधे मन से बैठकर बच्चा और उलझा दे। ऐसे मामलों में वह बाद में सहजता से कह देता है – ₹देखो, मुझसे नहीं होता, तुम ही कर लो।₹ इस तरह बार-बार की गई ऐसी घटनाएँ पत्नी को मजबूर कर देती हैं कि वह सब कुछ स्वयं संभाले।

यह प्रवृत्ति केवल आलस्य का रूप नहीं है, बल्कि मानसिकता की गहराई में छिपा हुआ लैंगिक भेदभाव है। समाज ने सदियों से यह धारणा बना दी है कि घरेलू काम महिलाओं का दायित्व है और पुरुष केवल बाहर की जिम्मेदारियों तक सीमित हैं। लेकिन आज के समय में जब महिलाएँ बाहर भी बराबर की जिम्मेदारी उठा रही हैं, तब यह तर्क न तो न्यायसंगत है और न ही स्वीकार्य।

कोरोना महामारी और लॉकडाउन के दौरान यह स्थिति और स्पष्ट होकर सामने आई। जब दफ्तर घरों में सिमट गए, बच्चे पूरे समय घर में रहने लगे और बाहर से सहायक मिलना बंद हो गया, तब लाखों परिवारों में यह देखा गया कि महिलाओं पर काम का बोझ कई गुना बढ़ गया। वे दिनभर ऑनलाइन मीटिंग्स में भी थीं और साथ ही तीन वक्त का खाना बनाने, बच्चों को पढ़ाने, सफाई करने और बुज़ुर्गों की देखभाल करने की जिम्मेदारी भी निभा रही थीं। पति जहाँ तक संभव हुआ, इन जिम्मेदारियों से बचते रहे और बहाना यही रहा कि वे घर के कामों में उतने माहिर नहीं हैं। इस परिस्थिति ने कई रिश्तों में तनाव को जन्म दिया और कई परिवारों में तलाक और अलगाव की घटनाएँ बढ़ीं।

महिलाएँ अब पहले जैसी स्थिति में चुपचाप समझौता नहीं कर रही हैं। शिक्षित और आत्मनिर्भर होने के कारण वे बराबरी की मांग कर रही हैं। उनके लिए विवाह अब केवल परंपरा निभाने का नाम नहीं है, बल्कि एक साझेदारी है। इस साझेदारी का अर्थ है कि दोनों साथी मिलकर घर की जिम्मेदारियाँ बाँटें। जब पति जानबूझकर अयोग्यता दिखाता है तो यह सीधे-सीधे पत्नी के आत्मसम्मान और मानसिक स्वास्थ्य पर चोट करता है। कई बार यह स्थिति डिप्रेशन, चिंता और थकान का कारण बन जाती है।

मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी यह प्रवृत्ति रिश्तों को नुकसान पहुँचाती है। रिश्ता तभी मजबूत होता है जब उसमें बराबरी और विश्वास का भाव हो। यदि एक पक्ष बार-बार जिम्मेदारी से भागे और दूसरा पक्ष मजबूरी में सब कुछ ढोता रहे तो धीरे-धीरे नाराज़गी, कड़वाहट और दूरी बढ़ जाती है। पत्नी को लगता है कि उसकी मेहनत को महत्व नहीं दिया जा रहा और पति को लगता है कि वह अपनी सुविधा से बच निकला है। यह असंतुलन लंबे समय तक नहीं चल सकता।

अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी इस विषय पर शोध हुए हैं। अमेरिका, कनाडा और यूरोप के कई समाजशास्त्रीय अध्ययनों में पाया गया है कि घरेलू कार्यों का असमान वितरण तलाक का एक बड़ा कारण है। भारत में भी यही प्रवृत्ति देखने को मिल रही है। बदलते शहरी जीवन, दोहरे रोजगार और छोटे परिवारों की पृष्ठभूमि में महिलाएँ अधिक मुखर हो रही हैं और बराबरी की मांग खुलकर रख रही हैं।

इस समस्या का समाधान केवल कानून या सामाजिक दबाव से नहीं निकलेगा, बल्कि यह पति-पत्नी के आपसी संवाद और समझदारी से ही संभव है। पुरुषों को यह समझना होगा कि घरेलू कार्य केवल साधारण काम नहीं हैं, बल्कि वे परिवार की नींव को मजबूत रखते हैं। यदि रसोई का काम, बच्चों की पढ़ाई या घर की सफाई समय पर और ठीक से न हो तो घर का वातावरण बिगड़ जाता है और तनाव बढ़ता है। इसलिए इन्हें हल्के में लेना या केवल महिला पर थोपना उचित नहीं।

इसी तरह महिलाओं को भी यह ध्यान रखना चाहिए कि वे बिना कहे हर जिम्मेदारी अपने ऊपर न लें। कई बार महिलाएँ यह सोचकर चुप रह जाती हैं कि ₹वह नहीं करेगा तो मुझे ही करना होगा।₹ धीरे-धीरे यह पैटर्न स्थायी हो जाता है और पति जिम्मेदारी से बचने का आदी बन जाता है। इसलिए आवश्यक है कि शुरुआत से ही दोनों के बीच काम बाँटने की आदत विकसित हो।

आख़िरी चीख़ (लघु कथा)

गाँव की पगडंडी पर शाम का अँधेरा उतर रहा था। खेतों से लौटते लोग अपनी-अपनी झोपड़ियों में जा चुके थे। लेकिन मनीषा अब तक नहीं लौटी थी। माँ की आँखें बार-बार दरवाज़े की चौखट पर टिक जातीं। पिता थककर पंचायत के चौपाल तक गए, मगर जवाब मिला—

"लड़की भाग गई होगी... कल लौट आएगी।"

सुबह हुई तो खेतों की मेड़ पर गाँव हिल गया। हँसती-खिलखिलाती उन्नीस बरस की कली अब निर्जीव पड़ी थी। कपड़ों के साथ उसकी इज़्ज़त भी तार-तार की जा चुकी थी।

पुलिस आई, कागज़ी खानापूर्ति हुई। रिपोर्ट लिखने से पहले ही कहा गया—

"ये तो खुद की गलती से हुआ होगा।"

पिता ने चीखकर कहा— "क्या इंसाफ़ सिर्फ अमीरों के लिए है?"

गाँव खामोश रहा। दरिंदों की हँसी कानों में गूँजती रही।

माँ की सूखी आँखें और पिता का टूटा हुआ मन सारा सच बयाँ कर रहे थे।

रात को वही खेत हवाओं से कराह रहा था। मनीषा की चीखें अब भी वहाँ गूंज रही थीं—

"मैं भागी नहीं थी... मुझे बचा लो..."

--- डॉ. प्रियंका सौरभ

सुनो नहरों की पुकार : जनजागरण अभियान

"आस्था का सच्चा स्वरूप यही है कि हम प्रकृति का सम्मान करें, नहरों को निर्मल रखें और आने वाली पीढ़ियों को स्वच्छ जल का उपहार दें।"

"सुनो नहरों की पुकार" मिशन हमें यह सिखाता है कि असली पूजा नदियों और नहरों को स्वच्छ रखना है। पूजा सामग्री बहाना एक परंपरा नहीं, बल्कि एक भूल है। प्लास्टिक, कपड़े, मूर्तियाँ और कचरा नहरों को विषैला बना रहे हैं। इससे न केवल जल प्रदूषित होता है, बल्कि कृषि, पशु और मानव स्वास्थ्य पर भी गंभीर असर पड़ता है। यह मिशन आस्था और पर्यावरण को जोड़ने का प्रयास है। संकल्प लें—नहरों को प्रदूषित नहीं करेंगे, जल को बचाएँगे और जीवन को सुरक्षित रखेंगे। यही सच्ची श्रद्धा है और यही आने वाली पीढ़ियों के लिए सबसे बड़ा उपहार है।

- डॉ. सत्यवान सौरभ

नहरें केवल पानी की धाराएँ नहीं होतीं। ये खेतों की हरियाली की लहर हैं, पशुओं की प्यास बुझाने वाली धारा हैं, और गाँव-गाँव में जीवन की गूँज बिखेरती संस्कृति की निसर्ग-गाथा हैं। परंतु आज ये जीवन-रेखाएँ मनुष्य की भूलों से आहत हैं। पूजा के बाद की सामग्री, कपड़े, मूर्तियाँ, प्लास्टिक, सिंदूर और यहाँ तक कि मृत पालतू पशुओं तक को लोग नहरों में डाल देते हैं। आस्था के नाम पर यह प्रदूषण, जल और जीवन दोनों के लिए अभिशाप बन गया है।

इसी पीड़ा से जन्मा है—"सुनो नहरों की पुकार"— एक जागरूकता अभियान, जिसकी शुरुआत रोहतक में डा. जसमेर सिंह हुड्डा (संयोजक) एवं हिसार में मा० भूपेंद्र सिंह गोदारा द्वारा हुई और जिन्होंने पिछले कुछ वर्षों में हजारों दिलों तक दस्तक दी।

मास्टर भूपेंद्र गोदारा और साथियों का संकल्प

गुरेरा गाँव की मिट्टी से उठे मास्टर भूपेंद्र गोदारा ने यह बीड़ा उठाया कि नहरों को उनकी पवित्रता लौटाई जाए। उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चले—सुबेदार मेजर दलीप सिंह, टेकचन्द बागड़ी, श्री दलवीर पोटलिया, रिटायर्ड आचार्य विजेन्द्र सिंह, कृष्ण कुमार, प्राचार्य अजीत सिंह, निहाल सिंह गोदारा, श्री पवन कुमार और अनेक जागरूक साथी।

इन सबका विश्वास है कि जब तक समाज अपनी आदतें नहीं बदलेगा, तब तक नहरों की आत्मा को शांति नहीं मिलेगी।

पिछले कई वर्षों की यात्रा : एक संकल्प, एक तपस्या

कोरोना के भयावह समय में भी, यह कारवाँ नहीं रुका। रविवार हो या छुट्टी का दिन, त्यौहार हो या बरसात—टीम अपने हाथों में तख्तियाँ लिए नहरों के किनारे खड़ी मिलती है। तख्तियों पर लिखे शब्द जैसे जनता से संवाद करते हैं—"जल है तो कल है", "नहरों को प्रदूषित मत करो", "आस्था है तो स्वच्छता भी हो"। इस यात्रा में हिम्मत सिंह, रामुर्ती, नरेंद्र कुल्हड़िया, प्रवीण वकील, सुरेंद्र गोदारा, संदीप, सीताराम, शेर सिंह, विकास गोदारा, रामभगत पुनिया, जैसे समाजसेवियों ने स्वर मिलाया। वहीं सुमन गोदारा, संतोष गोदारा, रचना, पुष्पा, कमला, सुनीता, शीला, तारा देवी, सुदेश ढांडा जैसी महिलाओं ने इस अभियान को और गहराई दी।

गुरेरा से इंस्पेक्टर उदयभान गोदारा ने भी समाज से आह्वान किया कि जब तक यह आवाज़ हर गली-मोहल्ले तक नहीं पहुँचेगी, तब तक बदलाव अधूरा रहेगा।

नहरें आहत क्यों हैं?

वह जलधारा जो खेतों में सुनहरे बालियाँ उगाती है, वही जब प्लास्टिक और पूजा सामग्री के बोझ से दब जाती है, तो विष बन जाती है। इस प्रदूषित जल से मिट्टी बीमार होती है, फसलें अस्वस्थ होती हैं और अंततः वही अन्न और सब्ज़ी हमारे थालियों में पहुँचती हैं।

यह केवल खेती तक सीमित नहीं—नहरों से पानी पीने वाले पशु और जीव भी रोगों से ग्रसित हो जाते हैं। वैज्ञानिक चेतावनी दे चुके हैं कि यह प्रदूषण कैंसर, हृदय रोग और अनेक असाध्य बीमारियों का कारण बन रहा है।

धर्म की नई परिभाषा

अभियान का मूल संदेश यही है—धर्म का अर्थ है प्रकृति की रक्षा।

भगवान को प्रसन्न करने का सबसे सच्चा मार्ग यही है कि हम जल को शुद्ध रखें, पेड़ों की रक्षा करें और जीव-जंतुओं की सुरक्षा करें। पूजा सामग्री को नहर में बहाना धर्म नहीं, बल्कि अधर्म है।

मास्टर भूपेंद्र गोदारा बार-बार प्रश्न करते हैं—

"हे प्रभु, आपके नाम पर लोग प्रकृति का इतना अपमान क्यों कर रहे हैं? यह कैसी आस्था है, जो जीवनदायिनी नहरों को विष से भर रही है?"

उनकी पीड़ा ही इस आंदोलन का प्रकाश बनी।

जनता की भागीदारी से ही बदलाव

हर अभियान का प्राण जनता की भागीदारी होती है। जब-जब समाज ने ठान लिया, तब-तब असंभव भी संभव हुआ। "सुनो नहरों की पुकार" ने हजारों लोगों की सोच बदल दी है। अब लोग पूजा सामग्री को नहरों में बहाने के बजाय मिट्टी में दबाने, पौधों के नीचे रखने या खाद बनाने की ओर बढ़ रहे हैं।

यह छोटे-छोटे कदम हैं, मगर इन्हीं से भविष्य के लिए बड़ा परिवर्तन संभव होगा।

जीवन बचाना है तो नहरें बचानी होंगी

यह अभियान केवल एक चेतावनी नहीं, बल्कि एक प्रार्थना भी है—

"नहरों को स्वच्छ रखो, जीवन को सुरक्षित रखो।"

नहरें यदि बचेंगी तो खेत हरे-भरे रहेंगे, पशु-पक्षी जीवित रहेंगे, और आने वाली पीढ़ियों के चेहरे पर मुस्कान बनी रहेगी।

"सुनो नहरों की पुकार" दरअसल हमारी अंतरात्मा की भी पुकार है—

जो हमें याद दिलाती है कि जल ही जीवन है, और इसे बचाना हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है।

सीरवी समाज जीडिमेटला के नवनिर्वाचित पदाधिकारियों का सम्मान समारोह

जगदीश सीरवी

गांधी नगर स्थित काग निवास पर सीरवी समाज जीडिमेटला के नवनिर्वाचित पदाधिकारियों के सम्मान समारोह कार्यक्रम में उपस्थित अध्यक्ष रावतराम बर्फा, उपाध्यक्ष 1 सोहनलाल परिहार, उपाध्यक्ष 2 दुर्गाराम मुलेवा, सचिव प्रेम पंवार, सह सचिव मंगलराम पंवार, कोषाध्यक्ष भंवरलाल काग, भारतीय जनता पार्टी पाली लोकसभा युवा नेता सुनील सीरवी, संतोष चोयल, अर्जुनलाल बर्फा, हेमाराम, सोहनलाल नितेश काग, शेषाराम परिहारीया, मिश्रीलाल वर्फा मोहनलाल सेणचा, केवलचन्द सेपटा, शेषाराम पंवार, मांगीलाल काग, सुखाराम, उदाराम, मंगलाराम काग, चुतराराम सोनपुरा, मोहनलाल काग कानाराम बर्फा, भुण्डाराम वर्फा राजुराम लचेटा चंदणाराम चोयल सोहनलाल हाम्बड़, चौथाराम पंवार, थानाराम पंवार, हरिसिंह उदावत, मोहनलाल बर्फा, अशोक हाम्बड़, व समाज बन्धु।

ट्रंप के टैरिफ़ को बेअसर करने भारतीय उद्योगों, अर्थव्यवस्था को जीएसटी सुधारों क़ा बूस्ट डोज़ - उपभोक्ताओं व राष्ट्र के लिए नई आर्थिक दिशा

एडवोकेट किशन सनमुखदास भावनानी
गोंदिया महाराष्ट्र

वैश्विक स्तरपर पूरी दुनियाँ जानती है कि ट्रंप नें अपने राष्ट्रपति पद के चुनावी अभियानों, भाषणों में 24 घंटे में युद्ध समाप्ति, अमेरिकी फर्स्ट, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन जैसे अनेकों वादे किए थे।जनवरी 2025 में राष्ट्रपति पद संभालते ही उन्हें पूरा करने की दिशा में कदम बढ़ा दिए हैं, जो हम करीब 8 महीनों से देख रहे हैं। इसी क्रम में दुनियाँ के तमाम देशों पर टैरिफ लगाने की बात भी कही थी जिसे अब वह पूरा करने पर तुले हुए हैं। मैं एडवोकेट किशन सनमुखदास भावनानीं गोंदिया महाराष्ट्र यह मानता हूं कि इससे पूरी दुनियाँ हिल गई है, हालांकि ट्रंप द्वारा टैरिफ़ के डंडे के बल पर अनेक देशों से अपने मन मुताबिक एग्रीमेंट करवाकर उन्हें टैरिफ से कुछ हद तक छूट दे दी गई है, परंतु भारत पर अभी 50 पेर्सेंट टैरिफ लगाया गया है, जिससे भारत के फार्मा, कृषि स्टील इत्यादि अनेक क्षेत्रों पर फर्क पड़ने की संभावना जताई जा रही है, दरअसल अब 27 अगस्त से 25 पेर्सेंट इसे दोगुना कर 50 पेर्सेंट तक करने का ऐलान किया है। इस फैसले से भारत के करीब 40 अरब डॉलर के निर्यात- जिसमें ज्वेलरी, वस्त्र और फुटवियर जैसे सेक्टर शामिल हैं, पर सीधा खतरा मंडरा रहा है। यही नहीं, भारत- अमेरिका के बीच होने वाली द्विपक्षीय व्यापार वार्ता भी इसी विवाद की वजह से रोक दी गई। यह वार्ता 25 से 29 अगस्त के बीच प्रस्तावित थी, लेकिन अमेरिकी ट्रेड टीम का दौरा अचानक रद्द कर दिया गया इसीलिए माननीय पीएम द्वारा 18 अगस्त 2025 को देरशाम इकोनामिक एडवाइजरी कमेटी की बैठक बुलाई गई थी जिसमें सात केंद्रीय मंत्री व नीति आयोग सहित अनेको संस्थाएं ने भाग लिया जिसमें जीएसटी रिफॉर्म पर भी चर्चा हुई। मीडिया में अंदाज लगाया जा रहा है कि अब जीएसटी स्लैप दो सिलेबेस 5 पेर्सेंट व 18 पेर्सेंट तक सीमित कर दिया जाएगा, उधर 18-19 अगस्त 2025 को चीनी विदेश मंत्री भारत दौरे पर हैं, इसके पूर्व कल ज्वलेंसकी ने हमारे पीएम महोदय से बात की, उसके बाद अलास्का बैठक के बाद पुतिन ने भी 18 अगस्त 2025 को देर शाम भारत भारतीय पीएम को फोन कर अलास्का मीटिंग के बारे में जानकारी दी, जिससे भारत की प्रतिष्ठा में चार चांद लगनें को रेखांकित किया जा सकता है।इसलिए आज हम मीडिया में उपलब्ध जानकारी के सहयोग से इस आर्टिकल के माध्यम से चर्चा करेंगे, ट्रंप के टैरिफ़ को बेअसर करने भारतीय उद्योगों, अर्थव्यवस्था को जीएसटी सुधारों क़ा बूस्ट डोज़ - उपभोक्ताओं व राष्ट्र के लिए नई आर्थिक दिशा।

साथियों बात अगर हम वैश्विक अर्थव्यवस्था आज इस मोड़ पर खड़ी होने की करेंतो, ट्रंप प्रशासन द्वारा भारत समेत कई देशोंपर 50 पेर्सेंट तक के आयात टैरिफ लगाने की घोषणा ने अंतरराष्ट्रीय व्यापार संतुलन को हिला दिया है। भारत जैसे उभरते हुए देश के लिए यह टैरिफ न केवल निर्यात क्षेत्र पर दबाव डालते हैं बल्कि घरेलू उद्योग और उपभोक्ता बाजार पर भी असर डाल सकते हैं। ऐसे समय में भारत सरकार ने जीएसटी सुधारों के रूप में 'बूस्टर डोज' देने की जरूरत महसूस की, जिससे न केवल टैरिफ के प्रभाव को बेअसर किया जा सकेगा बल्कि घरेलू मांग, उत्पादन और उपभोग की गति भी तेज होगी।अंतरराष्ट्रीय राजनीति और वैश्विक व्यापार की दुनियाँ में आर्थिक हथियारों का इस्तेमाल तेजी से बढ़ रहा है। ट्रंप प्रशासन ने अमेरिका को "अमेरिका फर्स्ट" की नीति पर खड़ा किया, जिसके तहत उसने भारत समेत कई देशों पर ऊँचे टैरिफ लगा दिए। इन टैरिफ का उद्देश्य अमेरिकी उद्योगों की रक्षा करना था, लेकिन इसका सीधा असर भारत के निर्यात, उद्योगों और उपभोक्ताओं पर पड़ेगा।ऐसे समय में भारत सरकार ने घरेलू अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए जीएसटी सुधारों का रास्ता चुना। ये

सुधार न केवल अमेरिकी टैरिफ के प्रभाव को संतुलित करेंगे बल्कि उपभोक्ताओं को राहत और उद्योगों को सुरक्षा भी देंगे। "अमेरिका द्वारा भारत पर थोपे गए भारी-भरकम टैरिफ के बीच पीएम ने सोमवार शाम 6:30 बजे एक बेहद अहम बैठक बुलाई थी। यह बैठक उनके आधिकारिक आवास 7, लोक कल्याण मार्ग पर हुई, जिसमें वित्तमंत्री समेत सात केंद्रीय मंत्री भी शामिल हुए। मीडिया का कहना है कि इस मीटिंग में भारत की अर्थव्यवस्था पर अमेरिकी टैरिफ के असर की समीक्षा की गई और आगे की रणनीति तय की गई ऐसा मीडिया से ज्ञात हुआ।

साथियों बात अगर हम अमेरिका के 50 पेर्सेंट टैरिफ का पृष्ठभूमि के भारत पर असर पढ़ने की करें तो, अमेरिका ने हाल ही में चीन, भारत, मेक्सिको और यूरोप के कुछ देशों पर उच्च टैरिफ लागू करने का संकेत दिया है। भारत से निर्यात होने वाले स्टील, एल्युमिनियम, टेक्सटाइल, आईटी हार्डवेयर, फार्मा और ऑटो पार्ट्स पर सीधा असर पड़ सकता है।टैरिफ से भारतीय कंपनियों की लागत बढ़ेगी, जिससे अमेरिकी बाजार में उनकी प्रतिस्पर्धा कम होगी। भारत का आईटी और फार्मा सेक्टर, जो अमेरिकी बाजार पर काफी निर्भर हैं, विशेष रूप से चुनौती का सामना करेंगे, इससे भारत का ट्रेड बैलेंस बिगड़ सकता है और डॉलर के मुकाबले रुपये पर दबाव आ सकता है।यानें साफ है कि अमेरिकी टैरिफ एक आर्थिक हथियार की तरह है, जिसे भारत की वृद्धि की गति धीमी करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। इसकी काट के रूप में भारत का जीएसटी सुधारों का बूस्टर डोज के रूप में जवाब है, भारत सरकार ने इसे केवल व्यापारिक समस्या न मानकर घरेलू आर्थिक अवसर में बदलने की रणनीति बनाई है। इसी क्रम में हाल ही में पीएम द्वारा स्वतंत्रता दिवस पर जीएसटी सुधारों की घोषणा की गई थी।ये सुधार वस्तुतः "बूस्टर डोज" हैं, जिनका लक्ष्य है-(1) घरेलू खपत बढ़ाना (2) उद्योगों की लागत घटाना (3) टैक्स प्रणाली को सरल और पारदर्शी बनाना (4) वैश्विक निवेशकों को आकर्षित करना (5) निर्यातकों को प्रोत्साहन देना। जीएसटी सुधारों की मुख्य विशेषताएँ- (1) मल्टी-रेट सिस्टम का सरलीकरण -पहले जीएसटी की दरें 0 पेर्सेंट, 5 पेर्सेंट, 12 पेर्सेंट, 18 पेर्सेंट और 28 पेर्सेंट थीं। सुधारों के बाद अधिकांश वस्तुएं 12 पेर्सेंट और 18 पेर्सेंट के बीच लाने की संभावना है, इससे टैक्स स्लैब कम होकर सरल और पारदर्शी बन जायेगा। (2) ई-कॉमर्स और एमएसएमई को राहत-छोटे उद्योगों को अब सालाना ₹2 करोड़ तक टर्नओवर पर जीएसटी से छूट मिलेगी (3) ई- कॉमर्स कंपनियों के लिए एकीकृत फाइलिंग सिस्टम लागू किया गया है। (4) इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) को आसान बनाना (5) अब उद्योगों को ऑटोमेटिक आईटीसी रिफंड मिलेगा। (6) कैश फ्लो की दिक्कतें कम होंगी और कारोबार का माहौल सुधरेगा। (7) निर्यात क्षेत्र के लिए विशेष प्रावधान (8) निर्यातकों को टैक्स रिफंड 15 दिनों में मिलने का प्रावधान। (9) सेज़ और मेक इन इंडिया यूनिट्स को अतिरिक्त टैक्स राहत। निर्यात क्षेत्र के लिए विशेष प्रावधान- (1) निर्यातकों को टैक्स रिफंड 15 दिनों में मिलने का प्रावधान। (2)सेज़ और मेक इन इंडिया यूनिट्स को अतिरिक्त टैक्स राहत। (3) उपभोक्ताओं को सीधा फायदा (4) रोजमर्रा की वस्तुओं जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स, मोबाइल, वस्त्र और खाद्य पदार्थों पर टैक्स दरें घटाई गईं। (5) इससे मुद्रास्फीति पर नियंत्रण होगा और उपभोक्ता खर्च बढ़ेगा।अमेरिकी टैरिफ और जीएसटी सुधारों का आपसी संबंध- (1) अमेरिका के टैरिफ का मकसद भारत के निर्यात को नुकसान पहुंचाना है।(2) भारत ने इसके जवाब में घरेलू खपत और उत्पादन पर जोर देकर यह सुनिश्चित किया कि टैरिफ का असर सीमित हो।उदाहरण के लिए-यदि अमेरिका भारतीय टेक्सटाइल पर 50 पेर्सेंट टैरिफ लगाता है, तो भारतीय कंपनियां घरेलू बाजार में कम टैक्स रेट और सरल जीएसटी प्रक्रिया का लाभ उठाकर अपनी बिक्री बढ़ा सकती हैं। (3) इसी तरह फार्मा सेक्टर को टैक्स रिफंड स्कीम और इनपुट क्रेडिट से राहत मिलेगी।

साथियों बात अगर हम जीएसटी रिफॉर्म्स से उपभोक्ताओं व उद्योगों को फायदों की करें तो, उपभोक्ताओं के लिए फायदे- (1) जीएसटी सुधारों का सबसे बड़ा लाभ आम उपभोक्ता को मिलेगा। (2) वस्तुओं पर कम टैक्स दरें- जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स और पैकेज्ड फूड। (3) अधिक पारदर्शिता-अब टैक्स चोरी और कैस्केडिंग इफेक्ट कम होगा। (4) महंगाई पर नियंत्रण- पेट्रोलियम उत्पादों को आंशिक रूप से जीएसटी में लाने की चर्चा भी इससे जुड़ी है। (5) बढ़ती खपत-कम कीमतों से मांग बढ़ेगी, जिससे अर्थव्यवस्था में गति आएगी।उद्योगों के लिए फायदे-(1) टैक्स का सरलीकरण -उद्योगों का प्रशासनिक बोझ कम होगा। (2) कैश फ्लो सुधरेगा-तेज आईटीसी रिफंड से निवेश और उत्पादन में तेजी आएगी। (3) घरेलू बाजार में सुरक्षा कवच-अमेरिकी टैरिफ से निर्यात घटने की स्थिति में घरेलू बिक्री को बढ़ावा मिलेगा। (4) वैश्विक निवेश आकर्षण-सरल टैक्स प्रणाली विदेशी कंपनियों को भारत में निवेश करने के लिए प्रेरित करेगी।

अतः अगर हम ऊपर पूरे विवरण का अध्ययन करें उसका विशेषण करें तो हम पाएंगे कि ट्रंप के टैरिफ़ को बेअसर करने भारतीय उद्योगों, अर्थव्यवस्था को जीएसटी सुधारों क़ा बूस्ट डोज़ - उपभोक्ताओं व राष्ट्र के लिए नई आर्थिक दिशा अंतरराष्ट्रीय राजनीति व वैश्विक व्यापार की दुनियाँ में आर्थिक हथियारों का इस्तेमाल तेज़ी से बढ़ रहा हैलाल किले की प्राचीर से पीएम का जीएसटी रिफॉर्म का आगाज़- टैरिफ भारत के लिए बाधा नहीं बल्कि अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर, उपभोक्ता केंद्रित बनाने का अवसर हैं।

सस्ती हो सकती हैं छोटी कारें और मोटरसाइकिल, सरकार कर रही जीएसटी घटाने की प्लानिंग

एचएसबीसी की रिपोर्ट के अनुसार भारत में छोटी कारों पर जीएसटी 28% से घटकर 18% होने पर कीमतें लगभग 8% तक कम हो सकती हैं। वर्तमान में यात्री वाहनों पर 29% से 50% तक कर लगता है। नई प्रणाली में छोटी कारों पर जीएसटी कम हो सकता है जबकि बड़ी कारों पर विशेष दर लागू हो सकती है जिससे उनकी कीमतों में भी कमी आएगी।

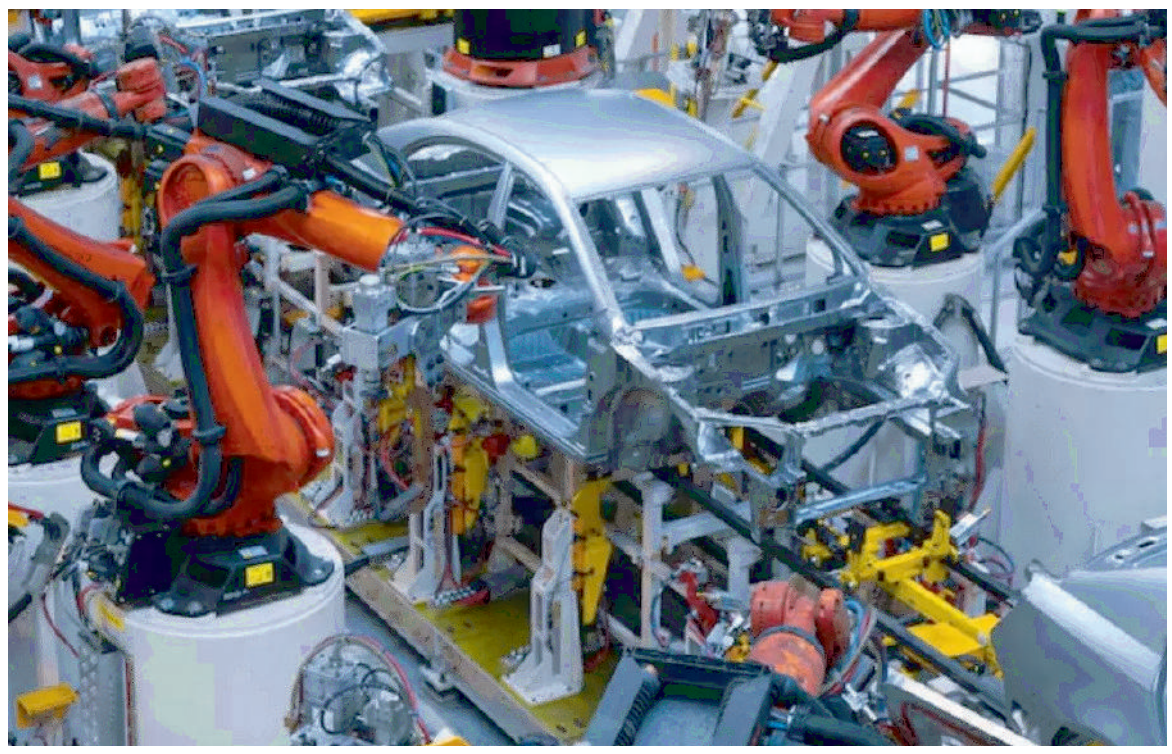

नई दिल्ली। वैश्विक बैंकिंग समूह एचएसबीसी ने ताजा रिपोर्ट में कहा कि यदि सरकार वर्तमान GST दर को 28 प्रतिशत से घटाकर 18 प्रतिशत करती है, तो भारत में छोटी कारों की कीमतों में लगभग आठ प्रतिशत की कमी आ सकती है। अभी यात्री वाहनों पर 29 से 50 प्रतिशत के बीच कर लगता है। इसमें 28 प्रतिशत GST और क्षतिपूर्ति उपकर शामिल है। यह वाहन के आकार और लंबाई के आधार पर लगाया जाता है। रिपोर्ट में कहा गया है कि नई प्रणाली में सरकार छोटी कारों पर GST को 28 से घटाकर 18 प्रतिशत कर सकती है।

वहीं, बड़ी कारों के लिए 40 प्रतिशत की विशेष दर पेश की जा सकती है। इससे क्षतिपूर्ति सेस को हटाया जा सकता है। यदि यह बदलाव लागू होता है, तो छोटी कारों की कीमतों में लगभग आठ प्रतिशत और बड़ी कारों की कीमत में 3-5 प्रतिशत तक की कमी आ सकती है। रिपोर्ट में कहा गया है कि GST में कमी का सभी दोपहिया निर्माताओं को लाभ मिलेगा। हालांकि, इससे सरकार के GST संग्रह में 4-5 अरब डालर की कमी आ सकती है।

छोटी कारों पर कम टैक्स का फायदा

फिलहाल 1200cc तक इंजन वाली और 4 मीटर से कम लंबाई की छोटी कारों पर 28% GST और 1% (पेट्रोल) या 3% (डीजल) सेस लगता है। इस तरह टैक्स भार काफी बढ़ जाता है। प्रस्ताव है कि इन गाड़ियों पर टैक्स को घटाकर 18% कर दिया जाए। इसका सीधा असर कार की कीमत पर पड़ेगा और ग्राहकों को गाड़ियां सस्ती मिल सकती हैं।

मिड-साइज कारों पर मामूली राहत

1200cc (पेट्रोल) या 1500cc (डीजल) से ज्यादा इंजन क्षमता वाली मिड-साइज कारों पर अभी 28% GST और 15% सेस यानी कुल 43% टैक्स लगता है। प्रस्तावित बदलाव के बाद इस टैक्स को घटाकर 40% किया जा सकता है, यानी ग्राहकों को यहां भी कुछ राहत मिल सकती है।

लग्जरी कार और SUV पर स्थिति जस की तस

1500 cc से अधिक इंजन क्षमता वाली लग्जरी कारों और बड़ी SUV पर अभी 28% GST और 20-22% सेस लगता है। इन्हें फिलहाल टैक्स में राहत मिलने की संभावना नहीं है। बल्कि सरकार अतिरिक्त शुल्क लगाकर इन्हें मौजूदा टैक्स स्तर पर ही बनाए रख सकती है।

बाइक चलाने वालों को भी फायदा

एंट्री लेवल मोटरसाइकिलों पर अभी 28% GST लगता है। प्रस्ताव है कि इसे घटाकर 18% किया जा सकता है। अगर ऐसा होता है, तो 350cc तक की बाइक सस्ती हो सकती हैं। वहीं 350cc से ऊपर वाली बाइक्स पर 40% टैक्स लगाने की बात सामने आई है। अभी इन पर 28% GST और 3% सेस यानी कुल 31% टैक्स लगता है, यानी हाई-एंड बाइक्स महंगी हो सकती हैं।

2025 हीरो ग्लैमर एक्स 125 लॉन्च; क्रूज कंट्रोल, तीन राइडिंग मोड समेत मिला पैनिक ब्रेक अलर्ट फीचर

परिवहन विशेष न्यूज

हीरो मोटोकॉर्प ने भारत में Hero Glamour X को लॉन्च कर दिया है। यह कई बेहतरीन फीचर्स से लैस है। कंपनी का दावा है कि इसमें कुछ ऐसे फीचर्स दिए गए हैं जो 125cc सेगमेंट की मोटरसाइकिल में पहली बार देखने को मिलेंगे। हीरो ग्लैमर एक्स अपने खास फीचर्स की वजह से और भी आकर्षक हो जाती है। यह मोटरसाइकिल युवाओं को काफी पसंद आएगी।

नई दिल्ली। हीरो मोटोकॉर्प ने भारत में 2025 Hero Glamour X 125 को लॉन्च कर दिया है। इसे कई बेहतरीन फीचर्स के साथ लेकर आया गया है। इसमें दिए गए कई फीचर्स तो 125cc की सेगमेंट की मोटरसाइकिल में पहली बार दिया गया है। इन फीचर्स की वजह से ग्लैमर एक्स और भी ज्यादा खास हो जाती है। आइए नई हीरो ग्लैमर के बारे में विस्तार में जानते हैं कि इसे किन बेहतरीन फीचर्स के साथ लेकर आया गया है।

Hero Glamour X की कीमत

2025 Hero Glamour X 125 दो वेरिएंट ड्रम और डिस्क वेरिएंट में लॉन्च किया गया है। इसके ड्रम वेरिएंट की एक्स-शोरूम कीमत 89,999 रुपये है, जबकि डिस्क वेरिएंट की एक्स-शोरूम कीमत 99,999 रुपये है।

Hero Glamour X का इंजन

Hero Glamour X में 124.7cc एकल सिलेंडर Sprint EBT इंजन का इस्तेमाल किया गया है। यह इंजन 11.4bhp की पावर जनरेट करता है। यह इंजन स्मूद राइड के लिए बैलेंसर शाफ्ट और साइलेंट कैम चेन के साथ आता है। इसमें नया बास-हेवी सिग्नेचर एग्जॉस्ट है और Hero का दावा है कि यह बेहतर माइलेज देता है।

Hero Glamour X का डिजाइन

इसमें राइडर की सुविधा के लिए बाइक में Hero ब्रांडेड अंडर-सीट स्टोरेज, चौड़े हैंडलबार, 790 mm सीट ऊंचाई और 16% बड़ा पिलियन सीट एरिया दिया गया है। इसमें 170 mm ग्राउंड क्लियरेंस, आरामदायक राइडिंग पोज़चर और वाइड नायलॉन ग्रिप टायर्स भी मिलते हैं। बाइक को पांच करल ऑप्शन में लेकर आया गया है, जो Matt Magnetic Silver, Candy Blazing Red, Metallic Nexus Blue, Black Teal Blue, और Black Pearl Red है।

Hero Glamour X के फीचर्स

इसमें सबसे खास है क्रूज कंट्रोल, जो इसे 125cc सेगमेंट की पहली बाइक बनाता है जिसमें यह फीचर मिलता है। इसमें तीन राइड मोड दिया गया है, जो Eco, Road, और Power है। इसके साथ ही फुल LED लाइटिंग, USB Type-C चार्जिंग पोर्ट, और फुली डिजिटल LCD क्लस्टर के साथ 60+ फंक्शन्स जैसे टैर्न-बाय-टर्न नेविगेशन, कॉल/एसएमएस अलर्ट्स, गियर इंडिकेटर, फ्यूल एफिशिएंसी डेटा, रेंज टू एम्प्टी, ब्राइटनेस एडजस्टमेंट और ब्लूटूथ कनेक्टिविटी जैसे फीचर्स भी दिए गए हैं।

2025 Hero Glamour X 125 में पैनिक ब्रेक अलर्ट दिया गया है, जो अचानक ब्रेक लगाने पर इंडिकेटर को फ्लैश करता है और एक फ्रंट डिस्क ब्रेक ऑप्शन भी मिलता है। इसके एक्सेसरीज पैकेज में बैकरेस्ट, नक्ल गार्ड, टैंक नी पैड्स, शॉर्ट विंडस्क्रीन, इंजन गार्ड, बेले पैन और फेंडर एक्सटेंशन ऑफर किया जा रहा है।

पोर्श लाएगी शानदार और जबरदस्त इलेक्ट्रिक एसयूवी, 1,000 किमी तक देगी ड्राइविंग रेंज।

लग्जरी कार निर्माता कंपनी पोर्श जल्द ही नई केयेन ईवी लॉन्च करने वाली है। यह इलेक्ट्रिक एसयूवी कई बेहतरीन फीचर्स के साथ आएगी और इसमें 1000 km तक की ड्राइविंग रेंज देने वाला बैटरी पैक होगा। केयेन ईवी में 1000 bhp तक की पावर जनरेट करने वाला इलेक्ट्रिक मोटर होगा। इसे 2026 तक लॉन्च किए जाने की उम्मीद है और शुरुआती कीमत 2 करोड़ रुपये से ऊपर हो सकती है।

नई दिल्ली। लग्जरी कार निर्माता कंपनी जल्द ही नई Porsche Cayenne EV लेकर आने वाली है। कंपनी इस इलेक्ट्रिक SUV को कई बेहतरीन फीचर्स के साथ लेकर आएगी। इसके साथ ही इसमें एसा बैटरी पैक दिया जाएगा, जो काफी ज्यादा ड्राइविंग रेंज देगा। आइए Porsche के इस इलेक्ट्रिक SUV के बारे में विस्तार में जानते हैं कि इसे किन खास फीचर्स के साथ लेकर आया जाएगा और इसकी ड्राइविंग रेंज कितनी रहने वाली है।

कैसा होगा डिजाइन?

Cayenne EV अपने पेट्रोल इंजन वाले मॉडल की तुलना में एक अधिक साफ और अधिक एयरोडायनामिक लुक अपनाएगी। इसके ग्रिल का एरिया करीब बंद होगा, जिसमें केवल किनारों पर असतत वर्टिकल स्लिट्स होंगे, जो पहियों के चारों ओर हवा को प्रवाहित करने के लिए एयर कर्टन के रूप में कार्य करते हैं। बाकी डिजाइन के रूप में बम्पर पर सक्रिय ग्रिल शटर, 20-इंच के एयरोडायनामिक अलॉय व्हील्स, और एक नए ग्लासहाउस के साथ फिर से डिजाइन किए गए दरवाजे के पैनल शामिल होंगे। इसमें एक फिक्स्ड रियर क्वार्टर विंडो भी शामिल है। इसके पीछे की तरफ पतली नई टेल लाइट्स एसयूवी की चौड़ाई में फैली होंगी।

कितना मिलेगा ड्राइविंग रेंज?

Cayenne EV संभवतः Porsche की लाइनअप में Taycan से ऊपर लेकर आया जाएगा। यह कंपनी की फ्लैगशिप इलेक्ट्रिक एसयूवी के रूप में आएगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक, Porsche Cayenne EV में 1,000 bhp तक की पावर जनरेट करने वाला इलेक्ट्रिक मोटर होगा। वहीं, इसमें मिलने वाला बैटरी पैक फुल चार्ज होने के बाद 1,000 km तक का ड्राइविंग रेंज दोगा। ayenne EV भारतीय बाजार में प्रदर्शन-उन्मुख लक्जरी EVs के लिए एक नया बेंचमार्क स्थापित कर सकती है।

कब होगी लॉन्च?

इलेक्ट्रिक Cayenne फेसलिफ्टेड पेट्रोल और प्लग-इन हाइब्रिड मॉडल के साथ आएगी। इसे साल 2026 तक लॉन्च किए जाने की उम्मीद है। इस साल के अंत में लॉस एंजिल्स मोटर शो के लिए एक संभावित ग्लोबल डेब्यू भी किया जा सकता है। उम्मीद है कि इसकी एक्स-शोरूम कीमत 2 करोड़ रुपये से काफी ऊपर होगी। यह BMW XM और Mercedes-Benz G580 जैसी गाड़ियों से मुकाबला करते हुए दिखाई देगी।

मारुति फ्रोंक्स की सिर्फ 28 महीनों में हुई पांच लाख यूनिट्स की बिक्री, जानें इस एसयूवी की सफलता का राज

मारुति फ्रोंक्स देश की प्रमुख वाहन निर्माताओं में शामिल मारुति सुजुकी की ओर से कई सेगमेंट में वाहनों की बिक्री की जाती है। निर्माता की ओर से ऑफर की जाने वाली कॉम्पैक्ट एसयूवी Fronx ने हाल में ही नई उपलब्धि को हासिल किया है। किस तरह की उपलब्धि को एसयूवी ने हासिल किया है। इसमें कैसे फीचर्स दिए जाते हैं। आइए जानते हैं।

नई दिल्ली। भारत में कई सेगमेंट में वाहनों की बिक्री कई निर्माताओं की ओर से की जाती है। मारुति सुजुकी की ओर से भी कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट में फ्रॉन्क्स की बिक्री की जाती है। लॉन्च होने के सिर्फ 28 महीनों में ही इस एसयूवी ने नई उपलब्धि को हासिल किया है। किस तरह की उपलब्धि एसयूवी ने हासिल की है। इसमें किस तरह के फीचर्स को दिया जाता है। किस कीमत पर एसयूवी को ऑफर किया जाता है। हम आपको इस खबर में बता रहे हैं।

मारुति फ्रॉन्क्स ने हासिल की उपलब्धि

मारुति सुजुकी की ओर से ऑफर की जाने वाली कॉम्पैक्ट एसयूवी Maruti Fronx ने नई उपलब्धि को हासिल किया है। निर्माता की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक इस एसयूवी ने हाल में ही पांच लाख यूनिट्स की बिक्री की उपलब्धि हासिल की है। खास बात यह है कि यह उपलबधि सिर्फ 28 महीनों में ही हासिल की गई है।

अधिकारियों ने कही यह बात

मारुति सुजुकी के मैनजिंग डायरेक्टर और सीईओ ने कहा कि हम अपने ग्राहकों के प्रति अत्यंत आभारी हैं कि उन्होंने FRONX को अपनी पसंदीदा गाड़ी के रूप में चुना और इसे भारत में सबसे ज्यादा बिकने वाली कॉम्पैक्ट SUVs में से एक बनाया। यह उपलब्धि भारत की विनिर्माण उत्कृष्टता और भविष्य के डिज़ाइन वाले वाहनों के प्रति ग्राहकों की स्वीकार्यता को दर्शाती है। अपनी बोल्ड स्टाइलिंग, कैटेगरी में सर्वश्रेष्ठ माइलेज और उन्नत तकनीकी विशेषताओं के साथ, FRONX ने घरेलू और विदेशी बाज़ारों में तेज़ी से लोकप्रियता हासिल की।

कैसे हैं फीचर्स

Maruti Fronx में निर्माता की ओर से कई बेहतरीन फीचर्स को ऑफर किया जाता है। इसमें एलईडी हेडलाइट्स, एलईडी डीआरएल, ऑटो हेडलैंप, एलईडी कनेक्टिड टेल लाइट, रियर वाइपर और वॉशर, स्पॉयलर, स्किड प्लेट, शॉर्क फिन एंटीना, ड्यूल टोन एक्सटीरियर, फैब्रिक सीट, टिल्ट और टेलीस्कोपिक स्टेयरिंग व्हील, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ओआरवीएम, पुश बटन स्टार्ट/स्टॉप, की-लैस एंट्री, स्टेयरिंग माउंटिड कंट्रोल्स, हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट, रियर एसी वेंट, फुटवेल इलूमिनेशन, 22.86 सेमी इंफोटेनमेंट सिस्टम, आर्किमिस ऑडियो सिस्टम, एपल कार प्ले, एंड्राइड ऑटो, चार स्पीकर, दो ट्वीटर, हेड-अप डिस्प्ले, 360 डिग्री जैसे फीचर्स मिलते हैं।

कितना दमदार इंजन

मारुति की ओर से फ्रॉन्क्स में 1.2 लीटर नेचुरल एस्पिरेडिट, 1.2 लीटर सीएनजी और एक लीटर की क्षमता का टर्बो पेट्रोल इंजन का विकल्प दिया जाता है। इसमें 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन से एसयूवी को 66 किलोवाट की पावर और 113 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिलता है। वहीं टर्बो इंजन से 73.6 किलोवाट की पावर और 147.6 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिलता है।

कितनी है कीमत

मारुति फ्रॉन्क्स को भारत में 7.58 लाख रुपये की एक्स शोरूम कीमत पर ऑफर किया जाता है। इसके टॉप वेरिएंट की एक्स शोरूम कीमत 13.06 लाख रुपये है।

टाटा हैरियर का वेरिएंट लाइनअप बदला, जानें किसमें मिलते हैं कौन-से फीचर्स?

टाटा मोटर्स ने Harrier के वेरिएंट लाइनअप में बदलाव किए हैं जिससे अब यह 12 वेरिएंट में उपलब्ध है। शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 15 लाख रुपये से शुरू होती है। कंपनी ने कुछ वेरिएंट को हटा दिया है और नए फीचर्स जोड़े हैं। अब हैरियर Smart Pure X Adventure X और Fearless X जैसे वेरिएंट में मिलेगी। टॉप मॉडल में ADAS JBL म्यूजिक सिस्टम और स्टेल्थ एडिशन जैसे फीचर्स हैं।

नई दिल्ली। टाटा मोटर्स ने हाल ही में भारतीय बाजार में Tata Harrier के दो वेरिएंट Adventure X और Adventure X Plus को लॉन्च किया है। इन दोनों वेरिएंट को लॉन्च करने के बाद अब कंपनी ने हैरियर के लाइनअप में बदलाव किया है। इन बदलावों के बाद हैरियर की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 15 लाख रुपये से शुरू होती है।

1. Tata Harrier का वेरिएंट लाइनअप

हैरियर के Smart (O), Pure, Pure+, Adventure, Adventure+, Fearless, और Fearless+ वेरिएंट को लाइनअप से हटा दिया गया है। इसे अब केवल 12 वेरिएंट में ऑफर किया जा रहा है, जो Smart, Pure X, Pure X Dark, Adventure X, Adventure X Dark, Adventure X+, Adventure X+ Dark, Fearless X, Fearless X Dark, Fearless X+, Fearless X+ Dark, और Fearless X+ Stealth है। आइए जानते हैं कि यह वेरिएंट किन फीचर्स के साथ आते हैं।

2. Tata Harrier Smart

स्मार्ट वेरिएंट में सात इंच का डिजिटल कॉकपिट और 17-इंच के अलॉय व्हील दिए जाते हैं। इसके साथ ही पैसेंजर की सेफ्टी के लिए छह एयरबैग, ABS के साथ EBD, ESP, रोल-ओवर मिटिगेशन, ट्रैक्शन कंट्रोल और कॉर्नर स्टेबिलिटी कंट्रोल भी मिलता है। साथ ही ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल, इल्युमिनेटेड लोगो के साथ टिल्ट- और टेलिस्कोपिक-एडजस्टेबल स्टीयरिंग, और दूसरी पंक्ति के लिए AC वेंट्स मिलते हैं।

इसके अलावा, Bi-LED प्रोजेक्टर हेडलाइट्स, LED DRLs, टर्न इंडिकेटर, टेल लाइट्स, और एक सीट बेल्ट रिमाइंडर सिस्टम के साथ ही 60:40 स्प्लिट दूसरी-पंक्ति की सीटें, दोनों पंक्तियों में एडजस्टेबल हेडरेस्ट, फ्रंट-रो कप होल्डर, रिवर्स पार्किंग सेंसर, ब्रेक डिस्क वाइपिंग, हिल स्टार्ट असिस्ट, और एक इलेक्ट्रिक टेलगेट रिलीज जैसे फीचर्स मिलते हैं।

3. Tata Harrier Pure X

प्योर X वेरिएंट में स्मार्ट वेरिएंट से ज्यादा फीचर्स मिलते हैं। इसमें ऐश ग्रे फैब्रिक अपहोल्स्ट्री और एक पैनोरमिक सनरूफ दिया गया है। 10.25-इंच डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और बेहतर दृश्यता के लिए एक 360-डिग्री कैमरा जैसे फीचर्स मिलते हैं। साथ ही 360-डिग्री कैमरा, क्रूज कंट्रोल, ऑटोमैटिक हेडलाइट्स, रेन-सेंसिंग वाइपर, और

ऑटो-फोल्ड के साथ इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ORVMs भी दिया जाता है।

इसमें वायरलेस एप्पल कारप्ले और एंड्रॉइड ऑटो, वॉयस कमांड, और दोनों पंक्तियों में USB Type-A और Type-C पोर्ट भी मिलता है। केबिन में स्टोरेज के साथ एक फ्रंट आर्मरेस्ट, चार-तरफा ऊंचाई-समायोज्य ड्राइवर सीट, चार स्पीकर, रिमोट चाबी के साथ पुश-बटन स्टार्ट, रियर वाइपर और वॉशर, एक शार्क-फिन एंटीना, रूफ रेल्स, और पैडल शिफ्टर्स भी मिलते हैं।

4. Tata Harrier Pure X Dark

इस वेरिएंट Pure X के सभी फीचर्स मिलते हैं। इसके अलावा, इसमें 18-इंच ब्लैक अलॉय व्हील्स, एक ब्लैकस्टोन इंटीरियर थीम, और खास #Dark बैजिंग के साथ एक बोल्ड सौंदर्य प्रदान करता है, जिससे इसे एक खास लुक मिलता है।

5. Tata Harrier Adventure X

एडवेंचर X वेरिएंट में लेदरेट इंटीरियर्स और एक पावर्ड ड्राइवर सीट दी जातीहै। इसमें मल्टीपल ड्राइव मोड्स City, Sport, और Eco, साथ ही Normal, Rough, और Wet जैसे ट्रेल रिस्पॉन्स मोड भी मिलते हैं। इसमें छह स्पीकर के साथ ही 45W USB Type-C चार्जिंग पोर्ट, रियर डिफॉगर, रियर पार्सल ट्रे और फ्रंट सीट बैक पॉकेट्स भी दिया जाता है।

6. Tata Harrier Adventure X Dark

इसमें एडवेंचर X वेरिएंट के सभी फीचर्स मिलते हैं। इसके साथ ही 8-इंच ब्लैक अलॉय व्हील्स, एक ब्लैकस्टोन इंटीरियर थीम, और #Dark बैजिंग दी जाती है।

7. Tata Harrier Adventure X Plus

एडवेंचर X+ वेरिएंट में ADAS के 12 फीचर्स दिए जाते हैं। इसमें ऑटो-होल्ड के साथ एक इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक (EPB) और ड्राइवर डोज-ऑफ अलर्ट सिस्टम के साथ ESP भी मिलता है।

8. Tata Harrier Adventure X+ Dark

यह वेरिएंट एडवेंचर X+ फीचर्स को सिग्नेचर #Dark स्टाइलिंग के साथ आगे बढ़ाता है, जिसमें 18-इंच ब्लैक अलॉय व्हील्स और एक ब्लैकस्टोन इंटीरियर थीम शामिल है।

9. Tata Harrier Fearless X

फियरलेस X वेरिएंट कई बेहतरीन फीचर्स के साथ आती है। इसमें 12.3-इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम नौ-स्पीकर JBL म्यूजिक सिस्टम दिया जाता है। इसमें 18-इंच के अलॉय व्हील्स, वेंटिलेटेड फ्रंट सीटें, मेमोरी फंक्शन, पावर्ड ड्राइवर सीट, विंड कम्फर्ट हेडरेस्ट, सन ब्लाइंड्स, कप होल्डर्स, रियर आर्मरेस्ट, फ्रंट और रियर कनेक्टेड लाइट्स, सीक्वेंशियल टर्न इंडिकेटर, वायरलेस चार्जिंग, एंबिएंट लाइटिंग, TPMS, एक स्मार्ट की, ऑटो-डिमिंग IRVM के साथ ही फॉलो-मी-होम हेडलाइट फंक्शन भी दिया गया है।

10. Tata Harrier Fearless X Dark

इस वेरिएंट में फियरलेस X के सभी वेरिएंट मिलते हैं। इसके अलावा, 19-इंच ब्लैक अलॉय व्हील्स, एक ब्लैकस्टोन इंटीरियर थीम, और अधिक आक्रामक और प्रीमियम लुक के लिए #Dark बैजिंग दी गई है।

11. Tata Harrier Fearless X+

फियरलेस X+ वेरिएंट में कई बेहतरीन फीचर्स मिलते हैं। इसमें Level 2 ADAS सूट के 20 फीचर्स मिलते हैं। इसके साथ ही 10-स्पीकर JBL म्यूजिक सिस्टम, चार-तरफा पावर्ड को-ड्राइवर सीट, iRA कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी, AQI डिस्प्ले के साथ एक एयर प्यूरीफायर, डिस्प्ले के साथ एक टेरेन रिस्पॉन्स मोड सेलेक्टर, LED लाइट बार्स पर वेलकम, गुडबाय एनीमेशन, कॉर्नरिंग फंक्शन के साथ LED फॉग लाइट्स, रियर फॉग लाइट, फ्रंट पार्किंग सेंसर, हिल डिसेंट कंट्रोल, एक कूल्ड फ्रंट आर्मरेस्ट, रिमोट AC ऑन/ऑफ कार्यक्षमता जैसे फीचर्स दिए जाते हैं।

12. Tata Harrier Fearless X+ Stealth

स्टेल्थ एडिशन एक मैट स्टेल्थ ब्लैक पेंट के साथ ऑफर किया जाता है। इसमें खास स्टेल्थ बैज, 19-इंच मैट ब्लैक अलॉय व्हील्स, कार्बन नॉयर इंटीरियर थीम, आर्केड ऐप स्टोर, स्लाइडिंग आर्मरेस्ट, एलेक्सा होम2कार कनेक्टिविटी, इनबिल्ट मैप माय इंडिया नेविगेशन दिया जाता है। इसके साथ ही ADAS के 22 फीचर्स दिए जाते हैं, जो इसे लाइनअप में सबसे तकनीकी रूप से उन्नत और देखने में सबसे आकर्षक वेरिएंट बनाता है।

कहानी: दुनिया के बेस्ट पापा

विजय गर्ग

पाँच दिन की छूट्टियाँ बिता कर जब ससुराल पहुँची तो पति घर के सामने स्वागत में खड़े थे। अंदर प्रवेश किया तो छोटे से गैराज में चमचमाती गाड़ी खड़ी थी स्विफ्ट डिजायर!

मैंने आँखों ही आँखों से पति से प्रश्न किया तो उन्होंने गाड़ी की चाबियाँ थमाकर कहाः-'कल से तुम इस गाड़ी में कॉलेज जाओगी प्रोफेसर साहिबा!'

'ओह माय गॉड!!'' ख़ुशी इतनी थी कि मुँह से और कुछ निकला ही नही। बस जोश और भावावेश में मैंने तहसीलदार साहब को एक जोरदार झप्पी देदी और अमरबेल की तरह उनसे लिपट गई। उनका गिफ्ट देने का तरीका भी अजीब हुआ करता है। सब कुछ चुपचाप और अचानक!! खुद के पास पुरानी इंडिगो है और मेरे लिए और भी महंगी खरीद लाए। 6 साल की शादीशुदा जिंदगी में इस आदमी ने न जाने कितने गिफ्ट दिए। गिनती करती हूँ तो थक जाती हूँ। ईमानदार है रिश्वत नही लेते । मग़र खर्चीले इतने कि उधार के पैसे लाकर गिफ्ट खरीद लाते है।

लम्बी सी झप्पी के बाद मैं अलग हुई तो गाडी का निरक्षण करने लगी। मेरा फसन्दीदा कलर था। बहुत सुंदर थी।

फिर नजर उस जगह गई जहाँ मेरी स्कूटी खड़ी रहती थी।

हठात! वो जगह तो खाली थी।

'स्कूटी कहाँ है?' मैंने चिल्लाकर पूछा।

'बेच दी मैंने, क्या करना अब उस जुगाड़ का? पार्किंग में इतनी जगह भी नही है।'

'मुझ से बिना पूछे बेच दी तुमने??'

'एक स्कूटी ही तो थी; पुरानी सी। गुस्सा क्यूँ होती हो?'

उसने भावहीन स्वर में कहा तो मैं चिल्ला पड़ीः-'स्कूटी नही थी वो। मेरी जिंदगी थी। मेरी धड़कनें बसती थी उसमें। मेरे पापा की इकलौती निशानी थी मेरे पास। मैं तुम्हारे तौफे का सम्मान करती हूँ मगर उस स्कूटी के बिना पे नही। मुझे नही चाहिए तुम्हारी गाड़ी। तुमने मेरी सबसे प्यारी चीज बेच दी। वो भी मुझसे बिना पूछे।'' मैं रो पड़ी।

शौर सुनकर मेरी सास बाहर निकल आई। उसने मेरे सर पर हाथ फेरा तो मेरी रुलाई और फुट पड़ी। 'रो मत बेटा, मैंने तो इससे पहले ही कहा था। एक बार बहु से पूछ ले। मग़र बेटा बड़ा हो गया है। तहसीलदार!! माँ की बात कहाँ सुनेगा? मग़र तू रो मत। और तू खड़ा-खड़ा अब क्या देख रहा है वापस ला स्कूटी को।'

तहसीलदार साहब गर्दन झुकाकर आए मेरे पास। रोते हुए नही देखा था मुझे पहले कभी। प्यार जो बेइन्तहा करते हैं। याचना भरे स्वर में बोलेः- सॉरी यार! मुझे क्या पता था वो स्कूटी तेरे दिल के इतनी करीब है। मैंने तो कबाड़ी को बेचा है सिर्फ सात हजार में। वो मामूली पैसे भी मेरे किस काम के थे? यूँ ही बेच दिया कि गाड़ी मिलने के बाद उसका क्या करोगी? तुम्हे ख़ुशी देनी चाही थी आँसू नही। अभी जाकर लाता हूँ।'

फिर वो चले गए।

मैं अपने कमरे में आकर बैठ गई। जड़वत सी। पति का भी क्या दोष था। हाँ एक दो बार उन्होंने कहा था कि ऐसे बेच कर नई ले ले। मैंने भी हँस कर कह दिया था कि नही यही ठीक है।

लेकिन अचानक स्कूटी न देखकर मैं बहुत ज्यादा भावुक हो गई थी। होती भी कैसे नही। वो स्कूटी नही 'औकात' थी मेरे पापा की।

जब मैं कॉलेज में थी तब मेरे साथ में पढ़ने वाली एक लड़की नई स्कूटी लेकर कॉलेज आई थी। सभी सहेलियाँ उसे बधाई दे रही थी।

तब मैंने उससे पूछ लियाः- 'कितने की है?

उसने तपाक से जो उत्तर दिया उसने मेरी जान ही निकाल ली थीः-' कितने की भी हो? तेरी और तेरे पापा की औकात से बाहर की है।'

अचानक पैरों में जान नही रही थी। सब लड़कियाँ वहाँ से चली गई थी। मगर मैं वही बैठी रह गई। किसी ने मेरे हृदय का दर्द नही देखा था। मुझे कभी यह अहसास ही नही हुआ था कि वे सब मुझे अपने से अलग ₹गरीब₹समझती थी। मगर उस दिन लगा कि मैं उनमे से नही हूँ।

घर आई तब भी अपनी उदासी छूपा नही पाई। माँ से लिपट कर रो पड़ी थी। माँ को बताया तो माँ ने बस इतना ही कहा₹ छिछोरी लड़कियों पर ज्यादा ध्यान मत दे! पढ़ाई पर ध्यान दे!'

रात को पापा घर आए तब उनसे भी मैंने पूछ लियाः-'पापा हम गरीब हैं क्या?'

तब पापा ने सर पे हाथ फिराते हुए कहा था'-हम गरीब नही हैं बिटिया, बस जरासा हमारा वक़्त गरीब चल रहा है।'

फिर अगले दिन भी मैं कॉलेज नही गई। न जाने क्यों दिल नही था। शाम को पापा जल्दी ही घर आ गए थे। और जो लाए थे वो उतनी बड़ी खुशी थी मेरे लिए कि शब्दों में बयाँ नही कर सकती। एक प्यारी सी स्कूटी। तितली सी। सोन चिड़िया सी। नही, एक सफेद परी सी थी वो। मेरे सपनों की उड़ान। मेरी जान थी वो। सच कहूँ तो उस रात मुझे नींद नही आई थी। मैंने पापा को कितनी बार थैंक्यू बोला याद नही है। स्कूटी कहाँ से आई? पैसे कहाँ से आए ये भी नही सोच सकी ज्यादा ख़ुशी में। फिर दो दिन मेरा प्रशिक्षण चला। साईकिल चलानी तो आती थी। स्कूटी भी चलानी सीख गई।

पाँच दिन बाद कॉलेज पहुँची। अपने पापा की 'औकात' के साथ। एक राजकुमारी की तरह। जैसे अभी स्वर्णजड़ित रथ से उतरी हो। सच पूछो तो मेरी जिंदगी में वो दिन ख़ुशी का सबसे बड़ा दिन था। मेरे पापा मुझे कितना चाहते हैं सबको पता चल गया।

मग़र कुछ दिनों बाद एक सहेली ने बताया कि वो पापा के साईकिल रिक्सा पर बैठी थी। तब मैंने कहा नही यार तुम किसी और के साईकिल रिक्शा पर बैठी हो। मेरे पापा का अपना टेम्पो है।

मग़र अंदर ही अंदर मेरा दिमाग झनझना उठा था। क्या पापा ने मेरी स्कूटी के लिए टेम्पो बेच दिया था। और छः महीने से ऊपर हो गए। मुझे पता भी नही लगने दिया।

शाम को पापा घर आए तो मैंने उन्हें गोर से देखा। आज इतने दिनों बाद फुर्सत से देखा तो जान पाई कि दुबले पतले हो गए है। वरना घ्यान से देखने का वक़्त ही नही मिलता था। रात को आते थे और सुबह अँधेरे ही चले जाते थे। टेम्पो भी दूर किसी दोस्त के घर खड़ा करके आते थे।

कैसे पता चलता बेच दिया है।

मैं दौड़ कर उनसे लिपट गई!ः-'पापा आपने ऐसा क्यूँ किया?' बस इतना ही मुख से निकला। रोना जो आ गया था।

' तू मेरा गुरूर है बिटिया, तेरी आँख में आँसू देखूँ तो मैं कैसा बाप? चिंता ना कर बेचा नही है। गिरवी रखा था। इसी महीने छुड़ा लूँगा।'

'आप दुनिया के बेस्ट पापा हो। बेस्ट से भी बेस्ट।इसे सिद्ध करना जरूरी कहाँ था? मैंने स्कूटी मांगी कब थी?क्यूँ किया आपने ऐसा? छः महीने से पैरों से सवारियां ढोई आपने। ओह पापा आपने कितनी तक़लीफ़ झेली मेरे लिए? मैं पागल कुछ समझ ही नही पाई।' और मैं दहाड़े मार कर रोने लगी। फिर हम सब रोने लगे। मेरे दोनों छोटे भाई। मेरी मम्मी भी।

पता नही कब तक रोते रहे ।

वो स्कूटी नही थी मेरे लिए। मेरे पापा के खून से सींचा हुआ उड़नखटोला था मेरा। और उसे किसी कबाड़ी को बेच दिया। दुःख तो होगा ही।

अचानक मेरी तन्द्रा टूटी। एक जानी-पहचानी सी आवाज कानो में पड़ी। फट-फट-फट,, मेरा उड़नखटोला मेरे पति देव यानी तहसीलदार साहब चलाकर ला रहे थे। और चलाते हुए एकदम बुद्दू लग रहे थे। मगर प्यारे से बुद्दू।

बेजवाब मुख्य चुनाव आयुक्त

देश के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के चेहरे पर तल्खी और चिंता की लकीरें पढ़ी जा सकती थीं। वह कुछ गुस्से में भी लग रहे थे। बेशक 'वोट चोरी' के गंभीर आरोपों के बीच उन्हें चुनावी शुद्धता और निष्पक्षता साबित करनी थी, लेकिन अधिकांश समय वह एकालाप की स्थिति में रहे। मुख्य चुनाव आयुक्त अपनी पहली प्रेस वार्ता में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के आरोपिया सवालों के संतोषजनक जवाब नहीं दे सके। सिर्फ इतना ही कहा कि 'वोट चोरी' शब्द उचित नहीं है। वे संविधान का अपमान करते हैं। संसद और आम मतदाता के विवेक का अपमान करते हैं।' दरअसल इस मुद्दे को सार्वजनिक रूप से उछालने या चुनाव आयोग और भाजपा-आरएसएस की मिलीभगत सरीखे पूर्वाग्रही आरोप लगाने की जरूरत नहीं होनी चाहिए थी। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को आयोग के कार्यालय में आमंत्रित कर सकते थे, क्योंकि दोनों व्यक्ति संवैधानिक पदों पर आसीन हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त विपक्ष के नेता के आरोपों और उनकी आशंकाओं को सुनते और एक संतोषजनक जवाब देने की कोशिश करते। दुर्भाग्य और विडंबना है कि ऐसा नहीं किया जा सका, बल्कि दोनों ही मैदान में कूद पड़े। यह बिल्कुल भी लोकतांत्रिक नहीं था, लेकिन मुख्य चुनाव आयुक्त राजनीतिक जुबां में बोलते रहे कि चुनाव आयोग आरोपों से नहीं डरता। वोटर को अपराधी कहना ठीक नहीं है।

चुनाव आयोग के कंधे पर बंदूक रख कर सियासत न करें। ज्ञानेश कुमार ने राहुल गांधी को दो टूक कहा-'या तो सात दिनों में हलफनामा दें अथवा देश से माफी मांगें। तीसरा कोई विकल्प नहीं है।'' दरअसल इस बयान में धमकी भी निहित है। चुनाव आयुक्त से यह अपेक्षा नहीं की जाती। राहुल गांधी की टीम ने क्या अपराध किया है, जो वह देश से माफी मांगें? टीम ने आयोग के दस्तावेजी तथ्यों से 'वोट चोरी' का जो निष्कर्ष निकाला है, उसे चुनाव आयोग ही गलत साबित कर कांग्रेसी टीम को बेनकाब कर सकता था। मुख्य चुनाव आयुक्त ऐसा क्यों नहीं कर पाए? उन्हें हलफनामा ही क्यों चाहिए? भाजपा नेताओं के 'वोट चोरी' के पुराने आरोपों पर हलफनामे क्यों नहीं मांगे गए? चुनाव आयोग तटस्थ, ईमानदार और पारदर्शी नहीं लगता। पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त हलफनामे को गैर-जरूरी मानते हैं। बहरहाल अब 'वोट चोरी' कमोबेश बिहार विधानसभा चुनाव का मुख्य मुद्दा बन गया है। मताधिकार को संविधान से जोड़ कर नेरेटिव तैयार किया गया है। लोग भ्रमित होकर भावुकता में बह सकते हैं। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव 'वोटर अधिकार यात्रा' पर हैं। चुनाव आयोग की खूब छीछालेदर की जा रही है। हालांकि मुद्दा अब भी सर्वोच्च अदालत के विचाराधीन है। अगली सुनवाई 22 अगस्त को है। चुनाव आयोग ने इतना जरूर किया है कि जिन 65.64 लाख मतदाताओं के नाम सूचियों से काट दिए गए हैं, उन्हें आयोग की वेबसाइटों पर सार्वजनिक किया गया है। अंतिम संतुष्टि सर्वोच्च अदालत की होगी, क्योंकि अदालत ने इतने नाम काट देने के 'कारण' भी पूछे हैं। शीर्ष अदालत ने इस आशय का अंतरिम आदेश दिया था। अदालत ने स्थानीय भाषा के और अंग्रेजी अखबारों समेत टीवी एवं सोशल मीडिया में अच्छी तरह उनके नाम छापने और प्रसारित करने के आदेश भी दिए थे। चुनाव आयोग को ऐसा ही करना पड़ेगा। 'वोट चोरी' न भी कहें, लेकिन मतदाता सूचियों में गड़बड़ी एक पुरानी और सर्वत्र व्याप्त विसंगति रही है। बेशक मतदाता सूचियों के पुनरीक्षण किए जाते रहे हैं। चुनाव आयोग को बिंदुवार जवाब देना चाहिए कि बाहरी देशों के कितने अवैध वोटर हैं, जिनके नाम सूची से काट दिए गए हैं।

स्क्रॉल, जानें, दोहराएं: शॉर्ट-फॉर्म सामग्री स्टूडेंट माइंड्स को फिर से आकार दे रही है

विजय गर्ग

टिकटोक, इंस्टाग्राम रील्स और यूट्यूब शॉर्ट्स जैसी शॉर्ट-फॉर्म सामग्री के उदय ने छात्रों को जानकारी का उपभोग करने के तरीके को गहराई से प्रभावित किया है और परिणामस्वरूप, उनके दिमाग को कैसे आकार दिया जा रहा है। यह "स्क्रॉल, सीखना, दोहराना" चक्र संभावित लाभ और महत्वपूर्ण कमियों दोनों के साथ एक जटिल तस्वीर प्रस्तुत करता है।

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अंतहीन स्क्रॉलिंग से घिरा हुआ है, और व्यक्तिगत रुचि का एक क्यूरेट फीड है, नई पीढ़ी अंतहीन रूप से इस बात पर त्वरित निर्णय ले रही है कि उनके ध्यान की अवधि के योग्य क्या है और क्या नहीं। इन नए दिमाग में अलग-अलग फोकसिंग क्षमताएं हो सकती हैं। जहां पुरानी पीढ़ियों को लंबे समय तक ध्यान केंद्रित करने के लिए अपने दिमाग को प्रशिक्षित करने के लिए बनाया गया था, आज के युवा छात्र बहुत तेजी से गति वाले वातावरण में बड़े हुए हैं जो उन्हें उनके धीरज के बजाय उनकी गतिशीलता के लिए लाभ पहुंचाता है। ध्यान और संज्ञानात्मक कार्य पर प्रभाव शॉर्ट-फॉर्म सामग्री के सबसे अधिक चर्चा किए गए परिणामों में से एक ध्यान स्पैन पर इसका प्रभाव है। इन वीडियो की तेजी से आग प्रकृति, उनके त्वरित कटौती, निरंतर दृश्य उत्तेजना और तत्काल संतुष्टि के साथ, मस्तिष्क को निरंतर नवीनता और तेजी से पुस्तक जानकारी की उम्मीद करने के लिए प्रशिक्षित करती है। इससे छात्रों के लिए कई चुनौतियां हो सकती हैं:

ध्यान में कमी स्पैन: अध्ययनों में छात्रों द्वारा शॉर्ट-फॉर्म सामग्री पर खर्च किए जाने वाले समय की मात्रा और धीमी गति, संज्ञानात्मक रूप से मांग वाले कार्यों पर ध्यान केंद्रित करने की उनकी क्षमता के बीच एक नकारात्मक सहसंबंध पाया गया है। वे पाठ्यपुस्तकों, व्याख्यानों और वृत्तचित्रों जैसी दीर्घकालिक सामग्री के साथ संघर्ष कर सकते हैं जिन्हें विस्तारित एकाग्रता की आवश्यकता होती है।

कम वर्किंग मेमोरी: शॉर्ट-फॉर्म सामग्री की अत्यधिक खपत को कम काम करने वाली मेमोरी से जोड़ा जा सकता है, जो जानकारी को बनाए रखने और संसाधित करने के लिए महत्वपूर्ण है। इससे छात्रों के लिए जटिल तर्कों का पालन करना या किसी पाठ से विवरण याद रखना मुश्किल हो सकता है।

अधीरता और शिथिलता: लघु-रूप सामग्री की डोपामाइन-चालित प्रकृति तत्काल संतुष्टि का एक चक्र बना सकती है जो छात्रों के लिए उन कार्यों में संलग्न होना कठिन बनाता है जो तत्काल पुरस्कार प्रदान नहीं करते हैं, जैसे कि कठिन परीक्षा के लिए अध्ययन करना। इससे शैक्षणिक शिथिलता बढ़ सकती है। "स्क्रॉल, जानें, दोहराएं" चक्र: एक डबल-एड्ड तलवार हालांकि नकारात्मक प्रभाव संबंधित हैं, "स्क्रॉल, सीखना, दोहराना" मॉडल सीखने और कौशल विकास के लिए नए रास्ते भी प्रदान करता है।

माइक्रो-लर्निंग एंड इंफॉर्मेशन फ़िल्टरिंग: शॉर्ट-फॉर्म कंटेंट "माइक्रो-लर्निंग" के लिए एक प्रभावी उपकरण हो सकता है, जो आसानी से पचने वाली जानकारी के काटने के आकार के टुकड़े वितरित करता है। छात्रों के लिए, यह एक सूचना-अतिभारित दुनिया में एक लाभ हो सकता है, क्योंकि यह उन्हें सामग्री के बारे में जल्दी से स्कैन, फ़िल्टर और निर्णय लेने में मदद करता है।

सगाई और प्रेरणा: टिकटोक जैसे मंच शैक्षिक सामग्री को मनोरंजक और नेत्रहीन आकर्षक तरीके से प्रस्तुत करके सीखने को अधिक आकर्षक और सुलभ बना सकते हैं। उदाहरण के लिए, कुछ अध्ययनों से पता चला है कि एक पूरक उपकरण के रूप में TikTok का उपयोग करने से भाषा सीखने में महत्वपूर्ण सुधार हो सकता है, क्योंकि यह छात्रों को प्रामाणिक भाषा उपयोग के लिए उजागर करता है।

कंटेंट क्रिएशन एंड क्रिटिकल थिंकिंग: शॉर्ट-फॉर्म कंटेंट के साथ जुड़ना केवल निष्क्रिय खपत के बारे में नहीं है। जो छात्र अपने स्वयं के वीडियो बनाते हैं, उन्हें जटिल विचारों को एक संक्षिप्त प्रारूप में जोड़ना सीखना चाहिए, एक कौशल जिसके लिए एक अलग तरह की महत्वपूर्ण सोच और संचार की आवश्यकता होती है। लर्निंग के भविष्य को नेविगेट करना शॉर्ट-फॉर्म सामग्री द्वारा छात्र दिमागों का पुनर्जीवन एक सतत प्रक्रिया है। यह त्वरित सूचना पहुंच के लाभों और कम फोकस की संभावित कमियों और सतह-स्तर की सगाई के लिए प्राथमिकता के बीच एक व्यापार-बंद है। इस नए परिदृश्य को नेविगेट करने के लिए, शिक्षकों और छात्रों को समान रूप से अनुकूलित करने की आवश्यकता हो सकती है। इसमें शामिल हो सकते हैं:

माइंडफुल कंजम्पशन: छात्रों को उनके स्क्रीन समय और उनके ध्यान में लघु-रूप सामग्री के संभावित प्रभावों के बारे में जागरूक करने के लिए प्रोत्साहित करना।

प्रौद्योगिकी को बुद्धिमानी से एकीकृत करना: पारंपरिक, लंबे समय तक सीखने के तरीकों के प्रतिस्थापन के बजाय, एक पूरक उपकरण के रूप में सूक्ष्म-सीखने और आकर्षक वीडियो सामग्री की शक्ति का लाभ उठाना।

नए कौशल विकसित करना: इस नए डिजिटल वातावरण में आवश्यक कौशल को बढ़ावा देना, जैसे कि जानकारी को जल्दी से संश्लेषित करने की क्षमता और विभिन्न स्रोतों से जानकारी का मूल्यांकन करने के लिए आवश्यक महत्वपूर्ण सोच। लक्ष्य शॉर्ट-फॉर्म सामग्री को खत्म करना नहीं है, बल्कि इसके प्रभाव को समझना है और इसका उपयोग इस तरह से करना है, जो बाधा के बजाय, एक छात्र के संज्ञानात्मक विकास और शैक्षणिक सफलता का समर्थन करता है। अब, शिक्षा की भूमिका केवल जानकारी देने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि छात्रों को इरादे के साथ अपना ध्यान संतुलित करने के लिए है। जोर केवल 'क्या ध्यान केंद्रित करना है' पर नहीं बल्कि 'कैसे ध्यान केंद्रित

स्वास्थ्य बनाम प्लास्टिक और एल्युमीनियम

विजय गर्ग

पिछले 20 सालों में दुनिया बदल गई है। इस तरक्की ने हमें ढेर सारी खुशियाँ दी हैं। तरह-तरह के साधन हमारे जीवन का हिस्सा हैं। लेकिन हमने ईश्वर के इस उपहार (शरीर) को बीमार बना दिया है। आज हर घर में एक या एक से ज़्यादा मरीज़ हैं जो लगातार दवाइयाँ ले रहे हैं। इस वजह से हमारी शारीरिक श्रम करने की क्षमता भी कम हुई है। इस वजह से हमें आर्थिक बोझ भी झेलना पड़ रहा है। कई बीमारियों का कारण हमारी जीवनशैली और खानपान है। आज हम प्लास्टिक और चाँदी (एल्युमीनियम) के दुष्प्रभावों का ज़िक्र करेंगे। जब अंग्रेज़ भारत आए तो वे अपने साथ बहुत कुछ ले गए और कुछ अपने साथ लाए। उनके पास एल्युमीनियम या चाँदी के बर्तन भी थे। जिनका इस्तेमाल वे भारतीय कैदियों के लिए करते थे। यह एक तरह का मीठा ज़हर था जो धीरे-धीरे शरीर में बनता था और कई बीमारियाँ पैदा करता था। लेकिन इनका इस्तेमाल इसलिए किया जाता था क्योंकि ये सस्ते, टिकाऊ, हल्के और ज़्यादा टिकाऊ होते थे। इनका हमारे स्वास्थ्य से कोई लेना-देना नहीं था। यह धातु, जिसे हम चाँदी के नाम से भी जानते हैं, अम्लीय भोजन के साथ प्रतिक्रिया करके धीरे-धीरे हमारे शरीर में घुल जाती है और कई बीमारियाँ पैदा करती है। चाँदी अम्लीय खाद्य पदार्थों जैसे टमाटर, सिरका, जैम, नींबू और दही आदि के साथ प्रतिक्रिया करके भोजन में घुल जाती है। लंबे समय तक इस्तेमाल से

यह पदार्थ हमारे शरीर में जमा हो जाता है। क्षारीय खाद्य पदार्थों जैसे दूध, हरी सब्ज़ियाँ, दालें, कई फल और मेवे आदि के साथ इसकी प्रतिक्रिया भी खतरनाक है। यह धीरे-धीरे हमारे शरीर में जमा होता जाता है। इसके साथ ही, इससे मस्तिष्क या तंत्रिका संबंधी रोग जैसे अल्जाइमर और तंत्रिका तंत्र संबंधी अन्य बीमारियाँ भी होती हैं। यह भोजन के पोषक तत्वों को नष्ट कर देता है ( )। गुर्दे की बीमारियों वाले मरीज़ों को इसका इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना चाहिए। यह खाने का स्वाद और रंग भी बिगाड़ देता है। इसके लिए लोहे, कच्चे लोहे, चीनी मिट्टी के गिलास, तांबे और पीतल जैसे सुरक्षित बर्तनों का इस्तेमाल किया जा सकता है।

प्लास्टिक के दुष्परिणाम...? यह कई प्रकार या विकल्पों में आता है। जैसे सिंथेटिक, सेमी-सिंथेटिक आदि। इसके लचीलेपन के कारण इसका उपयोग अनेक कार्यों में होता है। इसके अन्य गुणों जैसे टिकाऊपन, लचीलापन और सस्ता होने के कारण इसका उपयोग विश्व स्तर पर होता है। 1950 से 2017 तक 9.2 अरब मीट्रिक टन प्लास्टिक का उत्पादन हुआ, जिसका आधा उत्पादन 2004 से 2023 के बीच हुआ, यानी पिछले दो दशकों से इसका उपयोग बहुत बड़े पैमाने पर हो रहा है। इसके लाभ इसके साथ ही पर्यावरण प्रदूषण में भी इसकी बड़ी हिस्सेदारी है, जिसका इस पर बुरा असर ही देखने को मिला है। हमारे जंगल, पानी, मिट्टी और मौसम पर इसका बुरा असर पड़ रहा है। इसके कारण यह हमारे शरीर के लिए खतरनाक बीमारियों का कारण भी बन रहा है। इस पर हो रहे शोध के आधार पर विशेषज्ञ हमें निम्नलिखित प्रभावों के बारे में सचेत कर रहे हैं। यह कैंसर, प्रजनन तंत्र, तंत्रिका तंत्र की समस्याएं, अंतःस्रावी तंत्र संबंधी, श्वसन या अस्थमा रोग, हृदय रोग, महिलाओं से संबंधित रोग, स्तन और प्रोस्टेट कैंसर आदि जैसी बीमारियों का कारण बन रहा है। बच्चों में खिलौनों और खाने के कारण इसके बुरे प्रभाव सामने आ रहे हैं। कनाडा के डॉ. परगट सिंह भुर्जी के अनुसार, एक पीईटी बोतल के कारण लगभग एक हजार सूक्ष्म प्लास्टिक कण हमारे अंदर प्रवेश करते हैं। हमें एक महीने के अंदर अपना टूथब्रश भी बदल देना चाहिए। पुरानी बसों के कारण भी सूक्ष्म प्लास्टिक प्रवेश करता है। उन्होंने बताया कि एक मरीज की पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में उसके मस्तिष्क में पांच ग्राम प्लास्टिक (करीब एक चम्मच माइक्रोप्लास्टिक) पाया गया। अन्य अंगों में भी माइक्रोप्लास्टिक पाया गया। ये हैरान करने वाले तथ्य हैं। यूपीएससी कोच रहे प्रोफेसर धर्मेंद्र ने बताया कि एक मरीज के अंडाशय में माइक्रोप्लास्टिक पाया गया। कुछ प्लास्टिक पुराने या गर्म किए हुए खाने या पानी में घुलकर हार्मोन संबंधी गड़बड़ी, बांझपन, कैंसर आदि का कारण बनते हैं। नॉन बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक सैकड़ों सालों तक जमीन और पानी में रहता है। यह नदियों, समुद्री मछलियों और जानवरों के लिए जानलेवा साबित होता है। गर्म खाने में भी प्लास्टिक डालने से जहरीले कण खाने में घुल जाते हैं। हमें ऐसे प्लास्टिक का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना चाहिए जिस पर फूड सेफ नहीं लिखा हो। अगर हमें इस्तेमाल करना ही है तो हमें बीपीए फ्री प्लास्टिक का इस्तेमाल करना चाहिए। खाने-पीने की चीजों में प्लास्टिक का इस्तेमाल कम से कम करना चाहिए। हमें अपने खिलौनों, टिफिन, बोतलों के लिए हो सके तो कांच, लोहा, स्टील, तांबा आदि का इस्तेमाल करना चाहिए, अन्यथा बीपी फ्री प्लास्टिक का इस्तेमाल करना चाहिए। उपरोक्त सभी परिणामों से हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं अपनी सेहत के प्रति बेहद सचेत रहने की ज़रूरत है। आजकल हर कोई किसी न किसी तरह की दवा ले रहा है। अगर किसी बीमारी के लिए नहीं, तो विटामिन की कमी तो हो ही रही है। इसका कारण भोजन में प्लास्टिक, चाँदी आदि का प्रयोग है। इसलिए हमें संतुलित आहार, व्यायाम और मन की शांति का पूरा ध्यान रखना चाहिए ताकि हम इस अमूल्य शरीर को स्वस्थ रखकर इसका अधिकतम लाभ उठा सकें।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 भारत की शिक्षा प्रणाली के सबसे प्रभावशाली और महत्वाकांक्षी ओवरहॉल में से एक है

विजय गर्ग

भारत की राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 भारत की शिक्षा प्रणाली के सबसे प्रभावशाली और महत्वाकांक्षी ओवरहाल में से एक है, क्योंकि यह शिक्षा पारिस्थितिकी तंत्र को बड़े पैमाने पर बदलने का मार्ग प्रशस्त करता है। सरकार ने कुछ पथप्रदर्शक सुधार किए हैं, जिसमें एक प्रगतिशील ढांचे को शामिल किया गया है जो पुराने पाठ्यक्रम, रटने सीखने और सीमित अप-स्किलिंग प्रथाओं से अतिरेक को समाप्त करने पर केंद्रित है। एनईपी, 2020, एक लचीली, समग्र और समावेशी शिक्षा प्रणाली के लिए एक दृष्टि है जो युवा दिमाग के विकास को बढ़ावा देती है, जबकि उनकी तकनीक-आधारित सीखने की जरूरतों को पूरा करती है।

एक नया फाउंडेशन: 5 + 3 + 3 + 4 मॉडल एनईपी 2020 के अनुसार, स्कूल पाठ्यक्रम को 5 + 3 + 3 + 4 प्रणाली में पुनर्गठित किया गया है, जो पुराने 10 + 2 मॉडल को पुनर्जीवित करता है। यह ढांचा एक बच्चे के संज्ञानात्मक विकास चक्र के अनुरूप हैः

मूलभूत चरण (5 वर्ष): पूर्वस्कूली + ग्रेड 1 और 2 के 3 वर्ष

प्रारंभिक चरण (3 वर्ष): ग्रेड 3 से 5

मध्य चरण (3 वर्ष): ग्रेड 6 से 8

माध्यमिक चरण (4 वर्ष): ग्रेड 9 से 12

3 वर्ष की आयु से शुरू होने वाले इस ढांचे के मूल बनाने वाले मूलभूत सीखने के साथ, यह नई नींव प्रारंभिक बचपन देखभाल और शिक्षा के लिए मार्ग प्रशस्त करती है, यह सुनिश्चित करती है कि बच्चों को उनके शुरुआती वर्षों में संरचित उत्तेजना दी जाए।

इस दृष्टिकोण के साथ, बढ़ते वर्षों में सीखने के परिणामों में काफी सुधार होगा

कौशल विकास और राष्ट्रीय प्रशिक्षण कौशल एनईपी 2020 कौशल-आधारित और व्यावसायिक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सुधारों और संरचनाओं को दृढ़ता से विकसित करता है। एनईपी 2020 का लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि कौशल-आधारित और व्यावसायिक शिक्षा को अनिवार्य इंटर्नशिप के साथ ग्रेड 6 की शुरुआत में लागू किया जाए।

यह सुनिश्चित करता है कि बच्चों को अपनी कक्षा की शिक्षा जारी रखते हुए वास्तविक जीवन के अनुभव मिलें। इस पहल के माध्यम से बच्चे वास्तविक जीवन के आवेदन-आधारित कौशल जैसे बढ़ईगीरी, कोडिंग, बागवानी या डिजिटल साक्षरता को आगे की सड़क के लिए तैयार करेंगे।

उच्च शिक्षा में लचीलापन यह नीति स्नातक शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्रों के लिए कई निकास विकल्प प्रदान करके एक लचीला सीखने का दृष्टिकोण पेश करती है। इसमें कहा गया है कि छात्र सर्टिफिकेट के साथ 1 साल बाद, डिप्लोमा के साथ 2 साल बाद और डिग्री के साथ 3-4 साल बाद बाहर निकल सकते हैं।

डिजिटल स्कोरिंग को बढ़ावा देने के लिए, नीति अकादमिक बैंक ऑफ क्रेडिट (एबीसी) का भी परिचय देती है जो डिजिटल रूप से छात्र क्रेडिट को स्टोर करती है, जिससे उनके लिए अकादमिक ब्रेक लेना और शिक्षा फिर से शुरू करना आसान हो जाता है जब वे कर सकते हैं।

यह एक गेम चेंजर है क्योंकि यह छात्रों को वित्तीय, सामाजिक या स्वास्थ्य संबंधी व्यवधानों से संबंधित होने के बाद भी अपनी शिक्षा जारी रखने में मदद करता है, जिससे हमारी शिक्षा प्रणाली अंतर्राष्ट्रीय मानकों के साथ संरेखित होती है।

क्रिटिकल थिंकिंग एंड हॉलीस्टिक डेवलपमेंट पर ध्यान दें एनईपी 2020 अंतःविषय और अनुभवात्मक सीखने को बढ़ावा देता है, रटने सीखने और सख्त विषय कोर सीमाओं से दूर जाता है। इसका तात्पर्य यह है कि संगीत और भौतिकी, या रसायन विज्ञान और अर्थशास्त्र में रुचि रखने वाला छात्र अब कठोर धाराओं का पालन किए बिना दोनों का पीछा कर सकता है।

मूल्यांकन योग्यता-आधारित सीखने में भी बदल जाएगा, बोर्ड परीक्षा के साथ अब अधिक आवेदन-आधारित और न केवल स्मृति-आधारित है। नई नीति छात्रों के बीच बढ़ी हुई समझ, रचनात्मकता और समस्या को सुलझाने के दृष्टिकोण को बढ़ावा देने पर केंद्रित है।

डिजिटल पुश और समावेशी शिक्षा

यह नीति शिक्षा में प्रौद्योगिकी के पहलू पर विशेष जोर देती है और विशेष रूप से डिजिटल बुनियादी ढांचे, ई-सामग्री और ऑनलाइन शिक्षण प्लेटफार्मों के विकास की सिफारिश करती है।

साथ ही, यह डिजिटल इक्विटी को भी बढ़ावा देता है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि दूरस्थ और वंचित छात्र पीछे न रहें।

एनईपी 2020 भी विकलांग शिक्षार्थियों और सामाजिक-आर्थिक रूप से पीछे की ओर पृष्ठभूमि से आने वाले लोगों के लिए समावेशी शिक्षा की दृढ़ता से वकालत करता है, सभी के लिए इक्विटी और पहुंच को बढ़ावा देता है।

प्रभावी प्रभाव कुंजी है! एनईपी 2020 भारतीय शिक्षा प्रणाली के लिए एक प्रगतिशील दृष्टिकोण रखता है, एकमात्र चुनौती इसका प्रभावी कार्यान्वयन है।

यह आवश्यक है कि केंद्र और राज्य सरकार सभी शैक्षणिक संस्थानों और समुदायों में नीतियों को लागू करने के लिए निकट सहयोग में काम करें।

पाठ्यक्रम विकास, शिक्षक प्रशिक्षण, बुनियादी ढांचा विकास और जन जागरूकता को भारतीय शिक्षा प्रणाली के लिए मजबूत स्तंभ रखने के लिए विशेष जोर दिया जाना चाहिए।

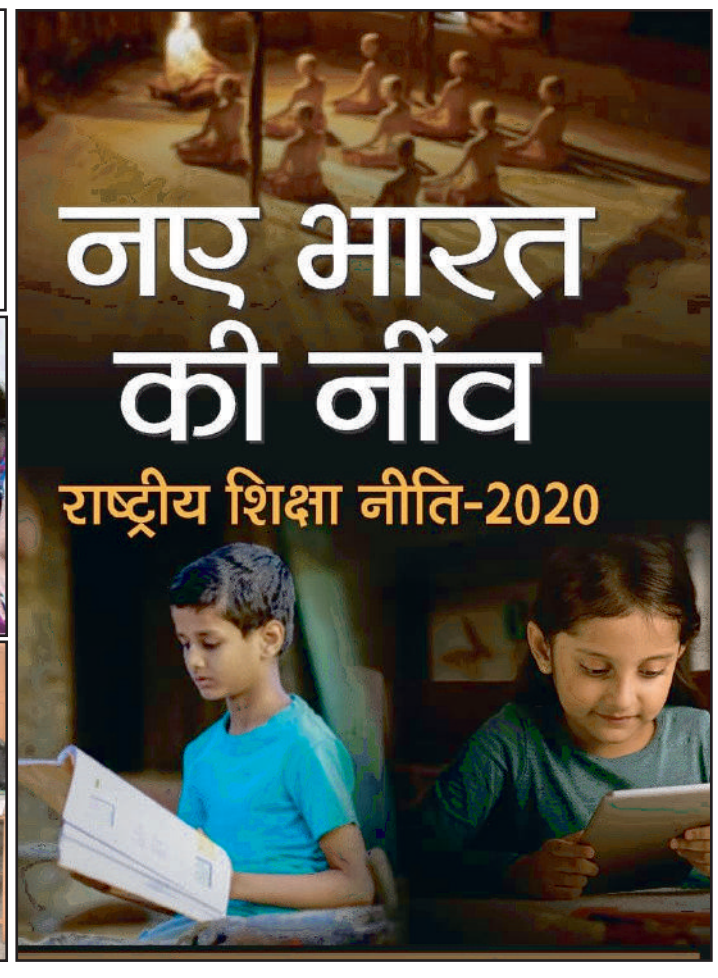

धरती के ताप से उर्जा उत्पादन की नयी किरण

जयसिंह रावत

केन्द्र शासित लद्दाख के बाद अब उत्तराखंड सरकार ने भी भूतापीय ऊर्जा के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुये सीमान्त चमोली जिले के तपोवन में राज्य का पहला भू-तापीय ऊर्जा पायलट प्रोजेक्ट शुरू कर दिया है। इस परियोजना स्थल पर जमीन से फूटने वाला पानी का स्रोत 90 से 100 डिग्री सेल्सियस तक तापमान देता हैं। उम्मीद की जा रही है कि यह प्रोजेक्ट न केवल उत्तराखण्ड बल्कि देश के ऊर्जा उत्पादन स्वावलंबन और पर्यावरण अनुकूल ऊर्जा की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा क्योंकि हिमालयी राज्यों सहित देश के लगभग एक दर्जन राज्यों में तापीय ऊर्जा उत्पादन की संभावनाएं मानी जा रही है। उत्तराखंड राज्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी परिषद (यूकॉस्ट), आइआइटी रुड़की और एनजीआरआइ के सहयोग से इस परियोजना में वैज्ञानिक अध्ययन शुरू हो चुके हैं। यह न केवल विद्युत उत्पादन, बल्कि पर्यटन, जल उपचार, और कृषि के लिए नए द्वार खोलेगा।

भू-तापीय ऊर्जा, जो पृथ्वी की आंतरिक ऊष्मा से प्राप्त होती है, निरंतर उपलब्ध, पर्यावरण सहज, और कम कार्बन उत्सर्जन वाला स्रोत है। भारत में लद्दाख की पूगा घाटी में 2022 में ओएनजीसी के पायलट प्रोजेक्ट के रूप में 2022 में शुरू हो चुका है। हिमाचल प्रदेश के मणिकरण में हालांकि अभी व्यावसायिक संयंत्र शुरू नहीं हुआ मगर गर्म पानी का उपयोग काफी पहले से हो रहा है। इनके अलावा छत्तीसगढ़ (तत्तापानी) और अन्य क्षेत्रों में इसकी संभावनाएँ मौजूद हैं। यह ऊर्जा सौर और पवन ऊर्जा से अलग, मौसम पर निर्भर नहीं, और जीवाश्म ईंधन की तुलना में स्थायी है। भारत की बढ़ती ऊर्जा आवश्यकताओं के लिए भूतापीय ऊर्जा एक छोटा किंतु महत्वपूर्ण योगदान दे सकती है, बशर्ते नीतिगत सहायता और तकनीकी उन्नति हो।

राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में देखें तो भारत सरकार ने देश के जिन पांच स्थलों को भूतापीय ऊर्जा विकास के लिए प्राथमिकता पर रखा है, उनमें हिमाचल प्रदेश का पग्घी, उत्तराखंड का तपोवन, लद्दाख के मानसरोवर और पामयांग क्षेत्र, छत्तीसगढ़ का तत्तापानी और गुजरात के कच्छ क्षेत्र में स्थित गरमपानी शामिल हैं। ये सभी क्षेत्र पृथ्वी की टेक्टोनिक प्लेटों की हलचलों से प्रभावित हैं और यहां की सतह के नीचे मौजूद मैग्मा के कारण प्राकृतिक गर्म जल स्रोत उपलब्ध हैं। इन स्थलों का चयन वैज्ञानिकों और ऊर्जा मंत्रालय के संयुक्त सर्वेक्षण के आधार पर किया गया है। भूगर्भ विशेषज्ञों के अनुसार भारत में भूतापीय ऊर्जा की कुल अनुमानित क्षमता 10,000 मेगावाट से अधिक है, जबकि वर्तमान में इस क्षेत्र में कोई व्यावसायिक उत्पादन नहीं हो रहा है।

एक अनुमान के अनुसार उत्तराखंड में कम से कम 60 से अधिक प्राकृतिक गर्म ज्ञात जल स्रोत हैं, जिनमें से कई में पानी का तापमान 70 से 100 डिग्री सेल्सियस के बीच है। इनमें से प्रमुख स्थल हैं तपोवन (नीती घाटी, चमोली), सूर्यकुंड और तप्तकुंड (बद्रीनाथ, चमोली), यमुनोत्री, नारदकुंड, गौचर, फूलचट्टी, हनुमानचट्टी, कुंड

(टिहरी), और झूलाघाट (पिथौरागढ़)। इनमें तपोवन और बद्रीनाथ के निकट के जल स्रोत न केवल तीर्थ और स्नान के लिए प्रसिद्ध हैं, बल्कि वैज्ञानिक दृष्टि से उच्च तापीय संभावनाओं वाले स्थल हैं। तपोवन में प्रस्तावित 2 मेगावाट क्षमता का पायलट प्लांट सफल हुआ तो उत्तराखण्ड सरकार इसे अन्य स्थलों पर 3 से 5 मेगावाट क्षमता तक विस्तारित करने की योजना है।

हिमाचल प्रदेश में कुल्लू और किन्नौर के पग्घी और मणिकर्ण क्षेत्र वर्षों से गर्म जलस्रोतों के लिए प्रसिद्ध रहे हैं। यहां तापमान भी 80 से 95 डिग्री के बीच दर्ज होता है और राज्य सरकार इस संसाधन के दोहन के प्रति संकल्पित है। लद्दाख का भूगर्भीय परिदृश्य भारत में सबसे सक्रिय क्षेत्रों में से एक है। वहां के मानसरोवर और पामयांग क्षेत्रों में चस्मों का तापमान 90 से 110 डिग्री सेल्सियस तक पाया गया है। लद्दाख प्रशासन ने सौर और जल विद्युत के साथ-साथ भूतापीय ऊर्जा को तीसरे स्तंभ के रूप में स्थापित करने की रणनीति बनाई है, जिससे वहां की कठोर जलवायु में निरंतर ऊर्जा आपूर्ति सुनिश्चित हो सके।

उत्तराखंड में धामी सरकार की वर्तमान पहल इसलिए भी उल्लेखनीय है, क्योंकि यह राज्य पहले से ही जल विद्युत उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, परंतु भूतापीय ऊर्जा इसका एक नया, नवाचार-आधारित अध्याय हो सकता है। यह ऊर्जा स्रोत जलवायु और मौसम पर निर्भर नहीं करता, इसलिए पर्वतीय क्षेत्रों में यह सौर और जल विद्युत की तुलना में अधिक निरंतर और विश्वसनीय हो सकता है। इसके अलावा यह पूरी तरह से हरित और शून्य कार्बन उत्सर्जन वाली ऊर्जा है, जो भारत के जलवायु लक्ष्यों के अनुरूप है। भू-तापीय ऊर्जा का उपयोग न केवल बिजली उत्पादन के लिए सीमित है, बल्कि इसे ग्रीनहाउस खेती, औद्योगिक प्रसंस्करण, दूध उत्पादन इकाइयों, होटलिंग, बर्फबारी वाले क्षेत्रों में सड़क की बर्फ हटाने, और जल चिकित्सा जैसे विभिन्न क्षेत्रों में किया जा सकता है। दुर्गम पहाड़ी इलाके जो स्थायी और भरोसेमंद बिजली से वंचित हैं, वहां यह ऊर्जा विकेन्द्रीकृत मिनी-ग्रिड सिस्टम के रूप में क्रांतिकारी बदलाव ला सकती है।

दरअसल भारत सरकार द्वारा 2022 में प्रस्तावित नेशनल जियोथर्मल एनर्जी मिशन अभी तक लागू नहीं हो सका है परंतु उत्तराखण्ड जैसे राज्यों की पहल इस दिशा में केंद्र को भी जागरूक कर रही है। विशेषज्ञों की मानें तो यदि उचित नीति, निवेश और तकनीकी सहयोग दिया जाए, तो भारत अगले 10 वर्षों में कम से कम 1000 मेगावाट भूतापीय ऊर्जा उत्पादन प्रारंभ कर सकता है। इससे देश के कई दूरवर्ती और सीमावर्ती क्षेत्रों को स्थायी बिजली आपूर्ति मिल सकती है, जिन तक बड़े ग्रिड पहुंचाने में भारी लागत और समय लगता है। उत्तराखंड की धामी सरकार ने इस दिशा में यूकॉस्ट, आइआइटी रुड़की और एनजीआरआइ जैसे संस्थानों को जोड़कर एक वैज्ञानिक और व्यावहारिक मॉडल की आधारशिला रखी है। इसके साथ ही पर्यटन, जैविक खेती, और स्वास्थ्य क्षेत्र को भी इससे जोड़ा जा सकता है। यदि बद्रीनाथ, यमुनोत्री और तपोवन जैसे धार्मिक स्थलों पर भू-तापीय ऊर्जा आधारित स्नानगृह, वेलनेस सेंटर और ग्रीनहाउस प्रकल्प विकसित किए जाएं तो यह धार्मिक पर्यटन को आधुनिक, टिकाऊ और आय-सृजनकारी रूप दे सकता है।

हिमालयी क्षेत्रों की भूगर्भीय अस्थिरता, भूस्खलन, और तकनीकी अनुभव की कमी जैसी चुनौतियां भी हैं लेकिन ये समस्याएं वैज्ञानिक दृष्टिकोण और अंतर्राष्ट्रीय अनुभव से हल की जा सकती हैं। आइसलैंड, केन्या और फिलीपींस जैसे देशों ने भू-तापीय ऊर्जा को अपने ऊर्जा मिश्रण में सफलतापूर्वक शामिल किया है। भारत के पास भी वही क्षमता है बशर्ते निवेश और योजना-निर्माण में निरंतरता बनी रहे। इस संदर्भ में धामी सरकार की यह पहल केवल एक राज्यीय परियोजना नहीं, बल्कि भारत की ऊर्जा क्रांति की संभावित दिशा है। यदि यह प्रयोग सफल होता है तो यह अन्य राज्यों को भी प्रेरित करेगा। पर्वतों की गोद से निकलती यह गर्मी अब केवल स्नान तक सीमित नहीं रहेगी, यह ऊर्जा में बदलेगी, गांवों को रोशन करेगी, और विकास की उस लौ को जलाएगी जो जलवायु परिवर्तन से लड़ने की ताकत रखती है।

मनोरंजन से मन की बात तक-रेडियो की अमर प्रासंगिकता

[बिनाका गीतमाला से पॉडकास्ट तक—रेडियो का जादू]

प्रो. आरके जैन "अरिजीत", बड़वानी (मप्र)

रेडियो, वह जादुई माध्यम, जिसने बीसवीं सदी से इक्कीसवीं सदी तक मानव जीवन को गहराई से प्रभावित किया, आज भी उतना ही प्रासंगिक है। यह केवल एक तकनीकी उपकरण नहीं, बल्कि एक ऐसा सेतु है, जो समाज को जोड़ता है, भावनाओं को आवाज़ देता है और बदलाव की प्रेरणा बनता है। रेडियो की तरंगें, जो कभी बिजली की अनुपस्थिति में भी गाँव-गाँव तक पहुँचती थीं, आज डिजिटल युग में भी अपनी आत्मीयता और पहुंच के कारण लाखों दिलों में बसी हैं। राष्ट्रीय रेडियो दिवस इस अनमोल धरोहर का उत्सव है, जो हमें याद दिलाता है कि कैसे रेडियो ने सूचना, मनोरंजन और एकता को हर घर तक पहुँचाया।

रेडियो का उदय उस युग में हुआ जब संचार साधन सीमित थे। 1890 के दशक में मार्कोनी ने रेडियो तरंगों से संचार की क्रांति शुरू की। भारत में 1920 के दशक में बॉम्बे और कलकत्ता में रेडियो स्टेशन बने, और 1936 में आल इंडिया रेडियो ने इसे औपचारिक मंच दिया। टेलीविजन और इंटरनेट के अभाव में, रेडियो की सरलता—बिना साक्षरता या महंगे उपकरणों की आवश्यकता—ने गाँवों से शहरों तक हर दिल को जोड़ा। स्वतंत्रता संग्राम में आजाद हिंद रेडियो जैसे प्रसारणों ने नेताजी के संदेशों से ब्रिटिश शासन को चुनौती दी। स्वतंत्रता के बाद, रेडियो भारत की सांस्कृतिक और राष्ट्रीय एकता का प्रतीक बना।

रेडियो ने सूचना प्रसार के साथ-साथ सामाजिक परिवर्तन को भी बढ़ावा दिया। किसानों को कृषि कार्यक्रमों से आधुनिक तकनीक और मौसम की जानकारी मिली, जिसने उनकी आजीविका को सशक्त किया। गृहणियों ने स्वास्थ्य, स्वच्छता और शिक्षा के प्रसारणों से जागरूकता प्राप्त की। बच्चों की कल्पनाशीलता को कहानियों-कविताओं ने पंख दिए, तो बुजुर्गों को भक्ति और शास्त्रीय संगीत ने आत्मिक शांति दी। इस तरह, रेडियो हर वर्ग का प्रिय साथी बना। आपदा में इसकी भूमिका अनमोल रही—2004 की सुनामी और 2013 की उत्तराखंड बाढ़ में बैटरी चालित रेडियो ने जीवन रक्षक सूचनाएँ पहुँचाकर राहत कार्यों को दिशा दी। संयुक्त राष्ट्र भी इसे आपदा प्रबंधन का सबसे विश्वसनीय माध्यम मानता है।

रेडियो ने मनोरंजन में अमिट छाप छोड़ी। 1950-60 के दशक में 'बिनाका गीतमाला' और 'विविध भारती' ने अमीन सायानी की आवाज़ में फिल्मी संगीत को घर-घर पहुँचाया, हर गाना उत्सव बन गया। क्रिकेट कमेंट्री ने श्रोताओं को स्टेडियम का रोमांच जिया, उन्हें घटनास्थल से जोड़ा। आज रेडियो ने ट्रांजिस्टर से एफ.एम. और इंटरनेट रेडियो तक का सफर तय किया। 400 से अधिक सामुदायिक रेडियो स्टेशन स्थानीय भाषाओं में शिक्षा, स्वास्थ्य और संस्कृति को बढ़ावा दे रहे हैं। इंटरनेट रेडियो और पॉडकास्ट ने इसकी वैश्विक पहुँच बनाई, जिससे मोबाइल पर दुनिया भर के स्टेशन सुने जा सकते हैं।

रेडियो ने अर्थव्यवस्था को गति देते हुए रेडियो जॉकी, ध्वनि इंजीनियर, स्क्रिप्ट राइटर और विज्ञापन विशेषज्ञ जैसे पेशों में लाखों युवाओं, खासकर महिलाओं, को रोजगार दिया, जहाँ केवल आवाज़ मायने रखती थी, लैंगिक समानता को बढ़ावा मिला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 'मन की बात' कार्यक्रम, जो 2014 से आल इंडिया रेडियो पर प्रसारित होता है, ने रेडियो को फिर से जन-जन का माध्यम बनाया। यह मासिक कार्यक्रम सामाजिक मुद्दों, सरकारी योजनाओं जैसे स्वच्छ भारत, बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ, डिजिटल इंडिया और प्रेरक कहानियों को स्थानीय भाषाओं में गाँव-शहर तक पहुँचाता है, लोगों को प्रेरित करता है। 'मन की बात' ने रेडियो की प्रभावशीलता और समावेशिता को पुनर्जनन दिया।

राष्ट्रीय रेडियो दिवस रेडियो की विरासत और वर्तमान-भविष्य में इसकी प्रासंगिकता को रेखांकित करता है। टेलीविजन और इंटरनेट के युग में भी रेडियो की आत्मीयता अद्वितीय है, जो बिना स्क्रीन के लोगों को उनके रोजमर्रा के कामों के साथ जोड़ता है। शहरों में ट्रैफिक में फँसा व्यक्ति हो या गाँव का किसान, रेडियो उनकी भाषा में संवाद करता है। डिजिटल इंडिया में सामुदायिक रेडियो ग्रामीण भारत के लिए सूचना-शिक्षा का सशक्त साधन है, जो किसानों को बाज़ार भाव-मौसम की जानकारी, छात्रों को ई-लर्निंग, महिलाओं को स्वास्थ्य-स्वच्छता शिक्षा, और युवाओं को कौशल विकास प्रदान करता है। पॉडकास्टिंग ने नई पीढ़ी को, और इंटरनेट रेडियो ने स्थानीय संस्कृतियों को वैश्विक मंच से जोड़ा, जबकि प्रवासी भारतीय अपनी मातृभाषा में रेडियो सुनकर जड़ों से जुड़े रहते हैं।

रेडियो वह अमर आवाज़ है, जो कभी थमती नहीं। बिना चेहरा दिखाए, यह दिलों को जोड़ता है। राष्ट्रीय रेडियो दिवस हमें इसकी समृद्ध विरासत को संजोने और इसके उज्ज्वल भविष्य को गढ़ने की प्रेरणा देता है। 'मन की बात' जैसे कार्यक्रमों ने साबित किया कि रेडियो आज भी समाज को एकजुट करने, शिक्षित करने और प्रेरित करने का सबसे लोकतांत्रिक और शक्तिशाली माध्यम है। यह न केवल अतीत की अनमोल धरोहर है, बल्कि वह सेतु भी है, जो हमें हमारी जड़ों से जोड़े रखता है। इसकी तरंगें सदा हमारे दिलों में गूंजती रहेंगी।

सद्भावना: विविधता में एकता का वास्तविक सूत्र

प्रो. आरके जैन "अरिजीत", बड़वानी (मप्र)

[सहानुभूति से समरसता तक: सद्भावना का जीवन दर्शन]

सद्भावना, एक ऐसा शब्द जो न केवल शब्दकोश की पंक्तियों में सिमटा है, बल्कि उन हृदयों में जीवंत है जो मानवता को एकता के सूत्र में बाँधना चाहते हैं। यह वह भाव है जो व्यक्तिगत जीवन को समृद्ध करता है और समाज व राष्ट्र को एकता का बल प्रदान करता है। भारत जैसे विविधतापूर्ण देश में, जहाँ हर कदम पर नई संस्कृति, भाषा और परंपराएँ साँस लेती हैं, सद्भावना वह जादुई रंग है जो इस विविधता को इंद्रधनुषी एकता में ढालता है। 20 अगस्त को मनाया जाने वाला सद्भावना दिवस केवल राजीव गांधी की जयंती का उत्सव नहीं, बल्कि एक ऐसी विचारधारा का प्रतीक है जो आपसी विश्वास, करुणा और सहयोग की राह प्रशस्त करती है। यह दिवस हमें सिखाता है कि मतभेदों को गले लगाकर उनमें सामंजस्य स्थापित करना ही सच्ची मानवता की नींव है।

सद्भावना दिवस का महत्व केवल औपचारिक समारोहों या शपथों तक सीमित नहीं है; यह एक गहन चेतना का आह्वान है जो हमें रोज़मर्रा के जीवन में छोटे-छोटे कार्यों से एक-दूसरे के प्रति सम्मान और संवेदना व्यक्त करने को प्रेरित करता है। भारत के इतिहास में सद्भावना की जड़ें गहरी हैं। स्वतंत्रता संग्राम में विभिन्न समुदायों ने कंधे से कंधा मिलाकर अंग्रेजी शासन का मुकाबला किया। महात्मा गांधी की अहिंसा और सत्याग्रह की शिक्षाएँ न केवल स्वतंत्रता की प्रेरणा बनीं, बल्कि यह भी दर्शाया कि सच्ची शक्ति हथियारों में नहीं, बल्कि एकजुटता और आपसी भरोसे में निहित है। आज, जब हम सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक चुनौतियों से जूझ रहे हैं, सद्भावना वह अमृत है जो हमें एकजुट रखती है और एक बेहतर, समावेशी भविष्य की ओर अग्रसर करती है।

आधुनिक भारत में सद्भावना की आवश्यकता पहले से कहीं अधिक तीव्र है। डिजिटल युग ने हमें एक-दूसरे से जोड़ा तो है, परंतु इसके साथ नई चुनौतियाँ भी उभरी हैं। सोशल मीडिया पर फैलने वाली गलत सूचनाएँ, नफरत भरे भाषण और साइबर उत्पीड़न समाज में फूट डाल रहे हैं। 2023 के एक सर्वेक्षण के अनुसार, 70% से अधिक भारतीय मानते हैं कि सोशल मीडिया ने सामाजिक ध्रुवीकरण को गहरा किया है। ऐसे में सद्भावना दिवस हमें प्रेरित करता है कि हम सूचनाओं को विवेकपूर्ण ढंग से परखें, रचनात्मक संवाद को बढ़ावा दें और मतभेदों को सहानुभूति व समझदारी से सुलझाएँ। यह दिन हमें जागृत करता है कि तकनीक का उपयोग नफरत का जहर फैलाने के लिए नहीं, बल्कि शिक्षा, जागरूकता और एकता को मजबूत करने के लिए होना चाहिए।

सद्भावना का एक और गहन आयाम है इसका वैश्विक स्वरूप। आज विश्व जलवायु परिवर्तन, युद्ध, आतंकवाद और आर्थिक असमानता जैसे वैश्विक संकटों से जूझ रहा है। संयुक्त राष्ट्र के 2023 के आँकड़ों के अनुसार, 28 करोड़ से अधिक लोग युद्ध और हिंसा के कारण विस्थापित हुए हैं। इन जटिल समस्याओं का समाधान केवल देशों के बीच आपसी सहयोग और गहरी समझ से ही संभव है। भारत ने वैश्विक मंच पर हमेशा शांति और सहयोग का दामन थामा है—1950 के दशक के पंचशील सिद्धांतों से लेकर आज जी-20 जैसे मंचों पर अपनी प्रभावी भूमिका तक। सद्भावना दिवस हमें यह सिखाता है कि वैश्विक नागरिक के रूप में अपनी जिम्मेदारी निभाकर हम एक ऐसी दुनिया का निर्माण कर सकते हैं, जहाँ शांति और समृद्धि सभी के लिए सुलभ हो।

युवाओं की भूमिका इस दिन को और भी विशेष बनाती है। राजीव गांधी ने अपने समय में सूचना प्रौद्योगिकी और संचार क्रांति की नींव रखी थी। 1980 के दशक में उनके प्रयासों से भारत में कंप्यूटर और टेलीकॉम क्षेत्र में क्रांति आई, जिसने आज भारत को डिजिटल शक्ति बनाया। आज के युवा, जो इस डिजिटल युग का नेतृत्व कर रहे हैं, उनके सामने अवसर है कि वे इस तकनीक का उपयोग समाज को जोड़ने, शिक्षा को बढ़ावा देने और सामाजिक समस्याओं का समाधान करने में करें। उदाहरण के लिए, भारत में 2024 तक 1.2 अरब से अधिक लोग इंटरनेट का उपयोग कर रहे हैं, और इनमें से अधिकांश युवा हैं। यदि यह युवा शक्ति सद्भावना के मूल्यों को अपनाए, तो सामाजिक परिवर्तन की एक नई लहर शुरू हो सकती है।

सद्भावना को जीवन का हिस्सा बनाने के लिए इसे रोज़मर्रा के छोटे-छोटे कार्यों में ढालना होगा। यह केवल भव्य आयोजनों या प्रेरक भाषणों तक सीमित नहीं होनी चाहिए। मिसाल के तौर पर, पड़ोसी की मदद करना, विभिन्न समुदायों की परंपराओं का सम्मान करना, या कार्यस्थल पर सहकर्मियों के बीच सहयोग बढ़ाना—ये सभी सद्भावना के जीवंत उदाहरण हैं। 2022 के एक सरकारी सर्वेक्षण के अनुसार, 65% भारतीय मानते हैं कि सामुदायिक सहयोग सामाजिक समस्याओं के समाधान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये छोटे प्रयास, जब सामूहिक रूप लेते हैं, तो समाज में गहरा और सकारात्मक बदलाव लाते हैं।

सद्भावना का एक और महत्वपूर्ण आयाम शिक्षा में निहित है। स्कूलों और कॉलेजों में बच्चों को बचपन से ही विविधता का सम्मान, सहानुभूति और सहयोग की भावना सिखानी चाहिए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 भी इस बात पर बल देती है कि शिक्षा का लक्ष्य केवल अकादमिक ज्ञान तक सीमित नहीं, बल्कि नैतिक मूल्यों और सामाजिक जिम्मेदारी को बढ़ावा देना भी है। यदि हम बच्चों में शुरू से ही सद्भावना के बीज बो दें, तो एक अधिक सहिष्णु, समावेशी और सशक्त समाज का निर्माण निश्चित रूप से संभव है।

सद्भावना दिवस हमें भारत की अनूठी ताकत, उसकी विविधता की याद दिलाता है। 2011 की जनगणना के अनुसार, भारत में 19,500 से अधिक भाषाएँ और बोलियाँ जीवंत हैं, 22 से ज्यादा आधिकारिक भाषाएँ और अनगिनत परंपराएँ यहाँ सहअस्तित्व में हैं। यह विविधता हमारी कमजोरी नहीं, बल्कि हमारी सबसे बड़ी शक्ति है। सद्भावना का असली अर्थ है इस विविधता को गले लगाना, विभिन्न समुदायों की संस्कृतियों, परंपराओं और विश्वासों का सम्मान करना, और एक समावेशी समाज की नींव रखना।

सद्भावना दिवस महज एक तारीख नहीं, बल्कि एक जीवन दर्शन है। यह हमें सिखाता है कि चाहे नफरत और असहिष्णुता कितनी भी प्रबल हो, मानवता का मूल सार करुणा, सहयोग और प्रेम में ही निहित है। यह दिन हमें आत्ममंथन का अवसर देता है—क्या हमारे विचार, शब्द और कर्म सद्भावना को प्रतिबिंबित करते हैं? यदि हम इस भावना को व्यक्तिगत, सामाजिक और वैश्विक स्तर पर आत्मसात करें, तो कोई भी चुनौती हमें डिगा नहीं सकती। यह वह संदेश है, जो हर पीढ़ी तक पहुँचाना जरूरी है, ताकि हम एक ऐसी दुनिया रच सकें, जहाँ हर दिल में अपनापन और हर रिश्ते में विश्वास हो।

उपराष्ट्रपति के लिए राधाकृष्णन को आगे कर भाजपा ने विपक्ष को असमंजस में डाला

रामस्वरूप रावतसरे

एनडीए के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन के नाम पर भाजपा ने आम सहमति बनाने की शुरुआत कर दी है। भाजपा की कोशिश है कि उपराष्ट्रपति के चुनाव की नौबत ना आए और सर्वसम्मति से ही राधाकृष्णन को अगला उपराष्ट्रपति चुन लिया जाए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इसके लिए कॉन्ग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे से बातचीत की है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी यह स्पष्ट कर चुके हैं कि भाजपा उपराष्ट्रपति पद के लिए निर्विरोध चुनाव सुनिश्चित करने के लिए विपक्ष से बात करेगी। सभी विपक्षी दलों का समर्थन जुटाने की कोशिश में पूरी तरह से जुटी हुई है हालाँकि, कॉन्ग्रेस ने इस पर अभी अपने पत्ते नहीं खोले हैं। चुनाव आयोग द्वारा जारी शेड्यूल के मुताबिक, 21 अगस्त 2025 उपराष्ट्रपति के उम्मीदवारों द्वारा नामांकन दाखिल किए जाने की आखिरी तारीख है। ऐसे में अगर आम सहमति नहीं बनती है तो विपक्षी गठबंधन आईएनडीआई को अगले 1-2 दिन में ही अपने उम्मीदवार के नाम का ऐलान करना होगा। 9 सितंबर को उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव कराया जाना है।

भाजपा ने अपने उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर विपक्ष का सिर दर्द बढ़ा दिया है। मूल रूप से तमिलनाडु से आने वाले और वर्तमान में महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन का नाम भाजपा द्वारा मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है। तमिलनाडु में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं और भाजपा लगातार दक्षिण भारत में विस्तार की कोशिश में लगी है। ऐसे में राधाकृष्णन का नाम भाजपा की सोची समझी चाल के तौर पर देखा जा रहा है। इसकी एक नहीं बल्कि कई वजहें हैं।

राधाकृष्णन की उम्मीदवारी के बाद सबसे अधिक दुविधा में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री और डीएमके के प्रमुख एमके स्टालिन हैं। स्टालिन अब तक केंद्र के फैसलों का तमिल अस्मिता के नाम पर विरोध करते रहे हैं। अब अगर आईएनडीआई गठबंधन अपने उम्मीदवार का ऐलान करता है और वो तमिलनाडु से नहीं होता है तो तमिल अस्मिता का प्रश्न फिर स्टालिन को ही घेरेगा। अगर स्टालिन इस निर्णय पर एनडीए के साथ खड़े हो जाते हैं तो यह आईएनडीआई गठबंधन में टूट का स्पष्ट संकेत होगा। स्टालिन ने अपने पत्ते नहीं खोले हैं लेकिन उनकी पार्टी ने अपना नरम रुख दिखाना शुरू कर दिया है।

विपक्षी गठबंधन की धुरी आज राहुल गांधी बन चुके हैं लेकिन इस स्थिति में सबसे बड़ी चुनौती उन्हीं के सामने है। वे जिस विपक्षी एकजुटता का दावा करते हैं, वह राधाकृष्णन के नाम से डगमगा सकती है। 2022 का उदाहरण उनके सामने है. जब जगदीप धनखड़ को भाजपा ने उपराष्ट्रपति उम्मीदवार बनाया था तो ममता विपक्षी मंच पर होने के बावजूद समर्थन करने को मजबूर हो गई थीं। अब वही दुविधा ठाकरे और स्टालिन के सामने है। अगर वे एनडीए के उम्मीदवार का समर्थन कर देते हैं तो यह मैसेज जाएगा कि कांग्रेस विपक्षी गठबंधन को एकजुट रखने में नाकाम है। राहुल गांधी के नेतृत्व पर सवाल उठेंगे। आखिर उनके साथ खड़े होने वाले ही क्यों डगमगा जाते हैं?

जानकारों के अनुसार मोदी और शाह की राजनीति की खासियत यह है कि वे चुनावी मुकाबले को सिर्फ आंकड़ों का खेल नहीं मानते बल्कि उसे मनोवैज्ञानिक लड़ाई बना देते हैं। राधाकृष्णन का नाम घोषित कर वे एक तीर से तीन निशाने साध चुके हैं। उद्धव ठाकरे को मजबूर कर दिया कि वे विरोध न कर पाएं। स्टालिन को ऐसी स्थिति में डाल दिया कि कोई भी फैसला उनके लिए भारी पड़े। राहुल गांधी को कमजोर दिखा दिया क्योंकि विपक्षी एकता अब सवालों के घेरे में आ गई। अगर उद्धव ठाकरे और स्टालिन जैसे बड़े चेहरे समर्थन की तरफ झुकते हैं तो विपक्षी गठबंधन में दरार साफ दिखाई देगी। उनके वोट भी कम हो जाएंगे।

राधाकृष्णन ने तमिलनाडु में लंबे वक्त तक राजनीति की है। वे दो बार के सांसद रहे हैं और तमिलनाडु भाजपा के अध्यक्ष भी रहे हैं। मूल रूप से तमिलनाडु के तिरुपुर से आते हैं। वे ओबीसी समुदाय से हैं जो तमिलनाडु में अल्पसंख्यक है लेकिन भाजपा का पारंपरिक समर्थन आधार रहा है। संगठनात्मक स्तर पर वे आरएसएस के खांटी स्वयंसेवक माने जाते हैं, यानी विचारधारा से पूरी तरह जुड़े और लंबे समय तक जमीनी स्तर पर काम करने वाले नेता के रूप में उनकी पहचान रही है।

तमिलनाडु दक्षिण भारत की सबसे जटिल राजनीतिक जमीन है। यहां दशकों से द्रविड़ दलों डीएमके और एआईएडीएमके का दबदबा रहा है। भाजपा को अभी तक यहां निर्णायक सफलता नहीं मिली जबकि केरल, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की तुलना में यहां का सांस्कृतिक-राजनीतिक समीकरण उसके लिए ज्यादा चुनौतीपूर्ण रहा है। पीएम मोदी और अमित शाह जानते हैं कि अगर तमिलनाडु में जरा भी पैठ बनानी है तो इसके लिए स्थानीय चेहरा और जातीय - सामाजिक बैलेंस बेहद जरूरी है। भाजपा यहां से एक नेशनल कनेक्ट बनाकर दिखाना चाहती है कि दक्षिण का नेता भी पश्चिमी भारत में शासन संभाल सकता है और अब दिल्ली में नंबर दो पद पर आसीन है।

तमिलनाडु की राजनीति में जाति का वजन बहुत अहम बताया जाता हैं। यहां ओबीसी और द्रविड़ जातियां राजनीति पर हावी हैं। ब्राह्मण समाज की हिस्सेदारी कम है, लेकिन भाजपा को लगता है कि यही उसका नैचुरल कैडर बेस है, क्योंकि द्रविड़ दलों की एंटी-ब्राह्मण राजनीति ने इस वर्ग को हाशिए पर धकेला है। राधाकृष्णन को उपराष्ट्रपति बनाने से भाजपा ब्राह्मण वोटरों के साथ-साथ उस शहरी, पढ़े-लिखे मध्यम वर्ग तक पहुंच बनाना चाहती है जो अभी भी डीएमके या एआईएडीएमके की राजनीति से दूरी रखता है। अगर इतिहास देखें तो तमिलनाडु के नेताओं को केंद्र की राजनीति में अहम पद मिले हैं। आर. वेंकटरमण राष्ट्रपति भवन तक पहुंचे। कई नेता मंत्री और स्पीकर रहे। लेकिन उपराष्ट्रपति पद तक पहुंचने वाले तमिलनाडु के नेता पहली बार दिख रहे हैं। यह कदम प्रतीकात्मक तौर पर बहुत बड़ा है, क्योंकि भाजपा यह मैसेज देना चाहती है कि तमिल पहचान और राष्ट्रीय पहचान साथ-साथ चल सकती है।

सीपी राधाकृष्णन का सबसे बड़ा गुण यही है कि वे आरएसएस की पॉलिटिक्स और संस्कारों से पूरी तरह प्रशिक्षित नेता हैं। मोदी-शाह की जोड़ी ने हमेशा ऐसे नेताओं पर भरोसा किया है जो विचारधारा और अनुशासन में बिना डगमगाए खरे उतरें हैं। उपराष्ट्रपति जैसे संवैधानिक पद पर किसी बाहरी या समझौता वाले चेहरे को लाने की बजाय, एक ऐसे नेता को आगे करना जिसने दशकों तक संगठन को अपना जीवन समर्पित किया, यह भाजपा की "काडर-टू-कॉर्नरस्टोन" रणनीति को भी दर्शाता है।

भाजपा पिछले एक दशक से लगातार दक्षिण भारत में अपनी पैठ बनाने की कोशिश कर रही है। कर्नाटक में उसे सफलता मिली है। तेलंगाना में भी ग्रोथ दिखी है। लेकिन तमिलनाडु अब तक किले की तरह अडिग रहा है। सीपी राधाकृष्णन को उपराष्ट्रपति बनाकर भाजपा ने साफ संकेत दिया है कि वह तमिलनाडु को लॉन्ग-टर्म इन्वेस्टमेंट जोन मान रही है। उसे पता है कि एक-दो चुनाव में परिणाम नहीं आएंगे। लेकिन अगर तमिल समाज को यह भरोसा हो जाए कि भाजपा उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान दे रही है, तो धीरे-धीरे राजनीतिक जमीन बदल सकती है।

जानकारों की माने तो यह पहली बार नहीं है कि विपक्षी गठबंधन की एकता में दरार आने की अटकलें लग रही हैं। इससे पहले भी ऐसे हालात बन चुके हैं, जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनावों में विपक्षी एकता छिन्न भिन्न हो गई हो। जिन जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के चलते उपराष्ट्रपति की कुर्सी खाली हुई है उनके चुनाव में भी विपक्षी एकता में दरार साफ दिखी थी। जगदीप धनखड़ उपराष्ट्रपति बनने से पहले पश्चिम बंगाल के राज्यपाल थे। बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की पार्टी उनसे तल्ख रिश्तों के बाद भी धनखड़ का विरोध नहीं कर पाई थी। 2022 में जब राष्ट्रपति पद का चुनाव हुआ था तो भी विपक्षी एकता टूट गई थी। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने विपक्षी खेमे में रहते हुए ही द्रौपदी मुर्मू के समर्थन का ऐलान किया था। अब फिर वैसी ही स्थिति विपक्ष के लिए बनती दिख रही हैं। भाजपा ने अपने मास्टर स्ट्रोक से एक साथ कई निशाने साधने की कोशिश की है जिसका असर आने वाले दिनों में साफ नजर आ सकता है।

ऑनलाइन गेमिंग बिल : "मनोरंजन, रोजगार और सामाजिक ज़िम्मेदारी के बीच संतुलन की तलाश"

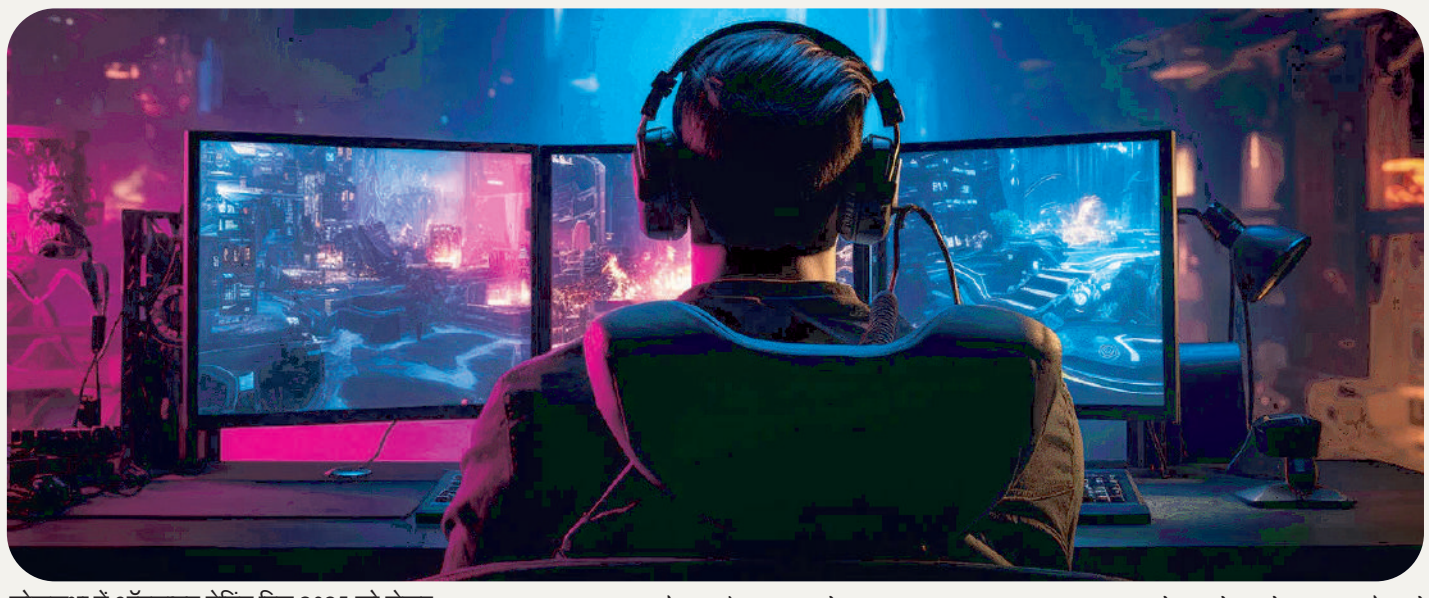

लोकसभा में ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025 को लेकर गहन बहस हुई। सरकार ने इसे समाज में जुए और लत जैसी प्रवृत्तियों को रोकने के लिए आवश्यक बताया, जबकि विपक्ष ने इसे रोजगार और उद्योग पर चोट मानते हुए संशोधन की माँग रखी। सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री ने स्पष्ट किया कि बिल केवल रियल-मनी गेमिंग और सट्टेबाज़ी पर रोक लगाता है, जबकि ई-स्पोर्ट्स और कौशल आधारित खेलों को प्रोत्साहित करेगा। कुछ सांसदों ने युवाओं की मानसिक सेहत और परिवारों की सुरक्षा पर चिंता जताई, वहीं उद्योग से जुड़े हितों पर विशेष समिति गठित करने का सुझाव आया।

डॉ. सत्यवान सौरभ

भारत में डिजिटल क्रांति के बाद से मोबाइल और इंटरनेट ने जिस तरह लोगों के जीवन को प्रभावित किया है, उसमें ऑनलाइन गेमिंग का संसार सबसे अधिक आकर्षक और विवादित रहा है। स्मार्टफोन की बढ़ती पहुँच, तेज़ इंटरनेट और युवाओं के बीच डिजिटल प्लेटफॉर्म की लोकप्रियता ने इस क्षेत्र को तेजी से विस्तार दिया है। लेकिन जहाँ एक ओर ई-स्पोर्ट्स और कौशल-आधारित खेलों ने भारत को विश्व मानचित्र पर जगह दिलाई है, वहीं दूसरी ओर पैसे के दाँव पर खेले जाने वाले खेल, बेटिंग ऐप्स और जुए जैसी प्रवृत्तियों ने समाज और सरकार दोनों को चिंतित किया है। इसी पृष्ठभूमि में केंद्र सरकार ने हाल ही में ऑनलाइन गेमिंग बिल को मंजूरी दी है। यह बिल न केवल आर्थिक और सामाजिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है बल्कि भविष्य में भारत की डिजिटल नीति की दिशा भी तय करेगा।

यह बिल स्पष्ट रूप से कहता है कि कोई भी वास्तविक धन पर आधारित गेमिंग या ऑनलाइन सट्टेबाज़ी प्रतिबंधित होगी। इसके साथ ही ऐसे खेलों के विज्ञापन, प्रचार और वित्तीय लेन-देन पर भी रोक लगाने का प्रावधान है। इसका सीधा मतलब है कि बैंक और वित्तीय संस्थान किसी भी रूप में ऐसे खेलों से जुड़े लेन-देन को प्रोसेस नहीं करेंगे। इस प्रावधान से सरकार यह सुनिश्चित करना चाहती है कि पैसे के लालच में जुए जैसी प्रवृत्तियाँ समाज में न फैलें।

परंतु इस बिल की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह ई-स्पोर्ट्स और कौशल-आधारित गैर-आर्थिक गेमिंग को बढ़ावा देता है। सरकार ने साफ किया है कि उसे खेल के रूप में ई-स्पोर्ट्स को प्रोत्साहित करना है। आने वाले समय में ₹नेशनल ई-स्पोर्ट्स अथॉरिटी₹ जैसी संस्था की स्थापना की जा सकती है, जो ई-स्पोर्ट्स को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत का प्रतिनिधि बनाने की दिशा में काम करेगी। यह कदम न केवल डिजिटल खेलों को वैधता देगा बल्कि उन लाखों युवाओं को भी अवसर देगा जो गेमिंग को कैरियर बनाना चाहते हैं।

इस बिल का एक और महत्वपूर्ण पहलू यह है कि इसके तहत सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) को केंद्रीय नियामक की भूमिका सौंपी गई है। मंत्रालय को यह अधिकार होगा कि वह गैर-पंजीकृत या अवैध गेमिंग प्लेटफॉर्म को ब्लॉक कर सके। यह व्यवस्था उपभोक्ताओं को धोखाधड़ी और अवैध गतिविधियों से बचाने के उद्देश्य से की गई है। भारत में अब तक ऑनलाइन गेमिंग से जुड़े नियम अलग-अलग राज्यों में अलग थे। कहीं इसे वैध माना गया तो कहीं प्रतिबंधित। ऐसे में एक राष्ट्रीय स्तर की रूपरेखा बनाना समय की मांग थी।

यह बिल केवल नियम-कानून का दस्तावेज़ नहीं है बल्कि इसके पीछे गहरे सामाजिक और मनोवैज्ञानिक कारण भी हैं। पिछले कुछ वर्षों में देखा गया है कि ऑनलाइन बेटिंग और वास्तविक धन से जुड़े खेलों की लत ने कई युवाओं की ज़िंदगियाँ बर्बाद कर दी हैं। कई मामलों में लोगों ने कर्ज़ लेकर खेला और परिवार तबाह हो गए। बच्चों में भी मोबाइल गेम्स की लत मानसिक स्वास्थ्य पर गहरा असर डाल रही है। सरकार को यह भी एहसास है कि इस समस्या को रोकना उतना ही ज़रूरी है जितना मादक पदार्थों की लत को रोकना। कई विशेषज्ञों ने तो इसे नशे से भी खतरनाक बताया है क्योंकि यह बिना किसी भौतिक पदार्थ के सीधे दिमाग़ पर नियंत्रण कर लेती है।

हालाँकि उद्योग जगत का पक्ष बिल्कुल अलग है। गेमिंग इंडस्ट्री का कहना है कि इस बिल से लगभग दो लाख नौकरियों पर खतरा मंडराने लगा है और सरकार को हर साल मिलने वाले बीस हज़ार करोड़ रुपये के जीएसटी राजस्व पर भी असर पड़ सकता है। ₹ड्रीम11₹, ₹गेम्स24x7₹, ₹विन्ज़ो₹ जैसी कंपनियाँ लंबे समय से करोड़ों रुपये का कारोबार कर रही हैं। उनका कहना है कि यदि घरेलू प्लेटफॉर्म को पूरी तरह रोक दिया गया तो उपयोगकर्ता विदेशी और ऑफशोर प्लेटफॉर्म की ओर रुख करेंगे, जहाँ न तो सरकार का कोई नियंत्रण होगा और न ही उपभोक्ताओं की सुरक्षा। इससे उल्टा नुकसान ही होगा।

इस बहस में दोनों पक्षों की अपनी-अपनी दलीलें हैं। सरकार का तर्क है कि समाज को जुए और नशे की लत से बचाना ज़रूरी है, वहीं उद्योग जगत मानता है कि यह क्षेत्र देश की डिजिटल अर्थव्यवस्था का बड़ा हिस्सा है और इसे खत्म करना युवाओं के रोजगार और नवाचार दोनों के लिए नुकसानदायक होगा। असली चुनौती यही है कि सही संतुलन कैसे कायम किया जाए।

बिल के समर्थकों का कहना है कि इस कदम से न केवल सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित होगी बल्कि युवाओं की ऊर्जा सही दिशा में लगेगी। ई-स्पोर्ट्स को प्रोत्साहन देकर भारत अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मेडल जीत सकता है, जैसा कि हमने बैडमिंटन, कुश्ती या क्रिकेट में देखा है। इसके अलावा गैर-आर्थिक गेम्स को बढ़ावा देने से बच्चों का मनोरंजन भी सुरक्षित दायरे में रहेगा।

दूसरी ओर आलोचकों का मानना है कि सरकार को ₹पूर्ण प्रतिबंध₹ की बजाय ₹कड़े नियमन₹ का रास्ता चुनना चाहिए था। यदि धन-आधारित गेमिंग को लाइसेंस प्रणाली और कड़े कराधान के तहत नियंत्रित किया जाता तो न केवल सरकार को राजस्व मिलता बल्कि उपभोक्ताओं की सुरक्षा भी बनी रहती। पूरी तरह प्रतिबंध लगाने से समस्या यह है कि लोग भूमिगत या विदेशी प्लेटफॉर्म की ओर भागेंगे और सरकार का नियंत्रण और भी कमजोर हो जाएगा।

यह बहस केवल भारत तक सीमित नहीं है। विश्व के कई देशों में ऑनलाइन गेमिंग को लेकर अलग-अलग दृष्टिकोण हैं। अमेरिका और यूरोप के कई हिस्सों में इसे सख्त नियमों और टैक्स प्रणाली के तहत वैध किया गया है। वहीं चीन जैसे देशों ने बच्चों के लिए गेमिंग के समय पर ही पाबंदी लगा दी है। भारत ने अब तक इस दिशा में कोई स्पष्ट राष्ट्रीय नीति नहीं बनाई थी, यही कारण है कि राज्यों के स्तर पर भ्रम और असमानता बनी रही।

अब सवाल यह उठता है कि आगे क्या होगा? यह बिल लोकसभा में पेश किया जाएगा और संभव है कि इसमें संशोधन हों। उद्योग जगत की चिंताओं को देखते हुए सरकार कुछ नरमी दिखा सकती है। उदाहरण के लिए ₹फैंटेसी स्पोर्ट्स₹ को कौशल-आधारित खेल मानकर सीमित अनुमति दी जा सकती है। इसी तरह कराधान और नियमन के ज़रिए सरकार और उद्योग के बीच समझौता हो सकता है।

परंतु एक बात तय है कि यह बिल भारत की डिजिटल यात्रा का अहम पड़ाव है। यह देश को यह सोचने पर मजबूर करता है कि तकनीक और समाज का संतुलन कैसे बनाया जाए। तकनीक अपने आप में न अच्छी है न बुरी, उसका इस्तेमाल उसे अच्छा या बुरा बनाता है। यदि ऑनलाइन गेमिंग युवाओं को कैरियर, रोजगार और अंतरराष्ट्रीय पहचान दे सकती है तो यह सकारात्मक है। लेकिन यदि वही गेमिंग परिवारों को तोड़ दे, युवाओं को कर्ज में डुबो दे और अपराध को बढ़ावा दे, तो यह खतरनाक है।

इसलिए ज़रूरी है कि सरकार, उद्योग, समाज और परिवार – सभी मिलकर समाधान निकालें। अभिभावकों को बच्चों पर नज़र रखनी होगी, शिक्षा संस्थानों को डिजिटल साक्षरता सिखानी होगी, उद्योग जगत को आत्मनियंत्रण और पारदर्शिता अपनानी होगी और सरकार को नियमन और प्रोत्साहन के बीच संतुलन बनाना होगा।

ऑनलाइन गेमिंग बिल केवल एक कानून नहीं है, यह हमारे समाज के भविष्य की रूपरेखा है। यह हमें यह सोचने पर विवश करता है कि क्या हम डिजिटल क्रांति को सिर्फ मनोरंजन और जुए का साधन बनने देंगे या इसे शिक्षा, रोजगार और वैश्विक प्रतिस्पर्धा का अवसर बनाएँगे। आने वाले वर्षों में यह बिल किस रूप में लागू होगा और समाज पर इसका क्या असर पड़ेगा, यह देखने वाली बात होगी। लेकिन एक बात स्पष्ट है कि यह बहस भारत के हर घर तक पहुँचेगी, क्योंकि मोबाइल और इंटरनेट अब हर जेब में है और गेमिंग हर उम्र की पसंद।

भारत में कंप्यूटर और टेलीकॉम क्रांति के जनक-राजीव गांधी

२० अगस्त को 'सद्भावना दिवस' के रूप में मनाया जाता है। वास्तव में, इस दिन भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी का जन्म हुआ था। पाठकों को बताता चलूं कि राजीव गांधी (२० अगस्त 1944 – २१ मई 1991) को भारत के सबसे युवा प्रधानमंत्री और 'आधुनिक भारत' के प्रवर्तक/शिल्पकार के रूप में याद किया जाता है। वे आधुनिक भारत के ऐसे नेता थे जिन्होंने परंपरागत राजनीति में नवाचार, तकनीकी सोच और युवाओं की भागीदारी को प्राथमिकता दी, लेकिन उनके जीवन और कार्यों से जुड़ी कई खास बातें ऐसी हैं, जो आम तौर पर कम ही लोग जानते हैं।राजीव गांधी राजनीति में नहीं आना चाहते थे।दरअसल, वे पेशे से पायलट थे और इंडियन एयरलाइंस में काम करते थे। इंदिरा गांधी की असमय मृत्यु और संजय गांधी के निधन ने उन्हें राजनीति में आने पर मजबूर किया। महज़ 40 वर्ष की आयु में प्रधानमंत्री बनने वाले वे भारत के इतिहास के सबसे युवा प्रधानमंत्री थे।उन्होंने लंदन के इंपीरियल कॉलेज और ट्रिनिटी कॉलेज, कैम्ब्रिज में पढ़ाई की, लेकिन इंजीनियरिंग की पढ़ाई अधूरी छोड़ दी थी। सोनिया गांधी से उनकी मुलाकात कैम्ब्रिज में एक इटैलियन रेस्टोरेंट में हुई थी, और दोनों का विवाह 1968 में हुआ। उपलब्ध जानकारी के अनुसार वे बहुत ही सादगी पसंद थे तथा उनके दोस्त उन्हें 'राजा' कहकर बुलाते थे।"

आज हम डिजिटल इंडिया की ओर अग्रसर हैं, लेकिन बहुत कम लोग जानते होंगे कि राजीव गांधी ही हमारे देश में कंप्यूटर क्रांति के असली जनक माने जाते हैं। दूसरे शब्दों में यह कहना ग़लत नहीं होगा कि देश में 'कंप्यूटर और सूचना प्रौद्योगिकी' की नींव रखने का असली श्रेय उन्हें ही जाता है। उन्हें कंप्यूटर, संचार और सूचना तकनीक से खास लगाव था। उनके प्रयासों से भारत में कंप्यूटर और टेलीकॉम क्रांति की शुरुआत हुई। हालांकि, 1980 के दशक में कंप्यूटर लाने के कारण उनका खूब विरोध भी हुआ था।उनके कार्यकाल में भारत में मतदान की न्यूनतम आयु २१ वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई।उन्होंने पंचायती राज को मजबूत किया। युवाओं के लिए 18 वर्ष की उम्र में उन्हें मतदान का अधिकार दिलवाना उनका एक बहुत बड़ा कदम था। सच तो यह है कि उनका यह कदम युवाओं को राजनीति में सीधे तौर पर जोड़ने के लिए ऐतिहासिक माना जाता है। यहां पाठकों को बताता चलूं कि 64वां संशोधन विधेयक (1989) राजीव गांधी सरकार द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को मजबूत करने के उद्देश्य से पेश किया गया था, लेकिन यह राज्यसभा में पारित नहीं हो सका था। तथा 65वां संशोधन अधिनियम, 1990, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग की स्थापना से संबंधित था, और इसमें विशेष अधिकारी के पद को हटा दिया गया था।64वें संविधान संशोधन विधेयक (1989) का उद्देश्य क्रमशः पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा देना,उन्हें अधिक शक्तिशाली और व्यापक बनाना तथा राज्यों में पंचायती राज व्यवस्था को मजबूत करना था, वहीं दूसरी ओर 65वें संविधान संशोधन अधिनियम (1990) का उद्देश्य क्रमशः अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए एक बहु-सदस्यीय राष्ट्रीय आयोग की स्थापना करना, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए विशेष अधिकारी का पद हटाना तथा अनुसूचित जातियों और जनजातियों के कल्याण और विकास के लिए आयोग को अधिक प्रभावी बनाना था। सत्ता का विकेंद्रीकरण करने के लिए राजीव गांधी ने 73वां और 74वां संवैधानिक संशोधन लाने की पहल की तथा पंचायतों और नगरपालिकाओं को संवैधानिक मान्यता दी।इससे आम जनता को निर्णय प्रक्रिया में भागीदारी का अधिकार मिला। राजीव गांधी विदेश नीति में बहुत ही दूरदर्शी व्यक्तित्व थे और पड़ौसी देश श्रीलंका में शांति सेना(आइपीकेएफ) भेजना उनका बड़ा कदम था।

हालांकि, यह विवादास्पद जरूर रहा, लेकिन वे क्षेत्रीय स्थिरता के पक्षधर थे।गुटनिरपेक्ष आंदोलन (एनएएम) और शांति प्रयासों में उन्होंने सक्रिय भूमिका निभाई। इतना ही नहीं, उन्होंने देश में आर्थिक उदारीकरण की नींव रखी। इस क्रम में लाइसेंस-परमिट राज को कम करने और अर्थव्यवस्था को आधुनिक बनाने की दिशा में पहल की तथा उद्योग और व्यापार को सरल बनाने के कदम उठाए। एक उपलब्ध जानकारी के अनुसार उन्हें फोटोग्राफी और पश्चिमी संगीत का गहरा शौक था तथा यात्रा में अक्सर अपना कैमरा साथ रखते थे। इतना ही नहीं, उन्हें मोटरबोटिंग और फ्लाइंग का भी शौक था। कहना ग़लत नहीं होगा कि वे भारत को 21वीं सदी में आधुनिक और आत्मनिर्भर राष्ट्र के रूप में देखना चाहते थे। बहुत कम लोग ही यह बात जानते होंगे कि उन्होंने दूरसंचार, टेक्नोलॉजी और शिक्षा में बड़े सुधार किए थे।एमटीएनएल और पीसीओ बूथों का नेटवर्क उन्हीं की पहल का नतीजा था।

उन्होंने देश में जवाहर नवोदय विद्यालयों की स्थापना कर ग्रामीण क्षेत्रों के प्रतिभाशाली बच्चों को गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा का अवसर दिया। साफ-सुथरी, बेदाग राजनीति के कारण मीडिया ने उन्हें 'मिस्टर क्लीन' की छवि प्रदान की थी। मरणोपरांत (वर्ष 1991) उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया। अंत में यही कहूंगा कि राजीव गांधी ने भारतीय राजनीति को पारंपरिक ढांचे से निकालकर आधुनिक युग की ओर मोड़ा। सूचना प्रौद्योगिकी, शिक्षा, पंचायत सशक्तीकरण और देश के युवाओं को राजनीति में जोड़ने का उनका प्रयास भारत के राजनीतिक इतिहास में मील का पत्थर माना जाता है। सच तो यह है कि उनकी दूरदृष्टि ने भारत को 21वीं सदी की चुनौतियों के लिए तैयार किया।

-सुनील कुमार महला

पांच युवकों ने नौवीं कक्षा की छात्रा के साथ सुनसान जगह पर सामूहिक दुष्कर्म किया...

मनोरंजन सासमल , बरिष्ठ पत्रकार

सम्बलपुर/भूबनेश्वर : युवाओं में अपराध की प्रवृत्ति बढ़ रही है। खासकर किशोरों की अपराध में संलिप्तता हाल ही में चिंता का विषय बन गई है। संबलपुर जिले के युयुमुरा में रविवार शाम एक नाबालिग लड़की के साथ सामूहिक बलात्कार हुआ। इसमें कुल 5 लोगों के शामिल होने का आरोप है, जिनमें से 2 नाबालिग हैं।पुलिस ने मुख्य आरोपी सुशांत मिर्धा (21) निवासी डुम्बूरीपाड़ा, जिवदारलेनपाली को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि दो नाबालिगों को भी गिरफ्तार किया गया है। संबलपुर के एसपी मुकेश कुमार भामू ने बताया कि अन्य दो आरोपी फरार हैं।

युयुमुरा थाना अंतर्गत जिवदारलेनपाली इलाके में रहने वाली पीड़िता नौवीं कक्षा की छात्रा है। रविवार शाम करीब साढ़े छह बजे वह शौच के लिए पाड़ा के पास नाले के पास गई थी। उसी समय मुख्य आरोपी मिर्धा और वहां मौजूद चार अन्य लोग उसे एक सुनसान जगह पर ले गए। इसके बाद उन्होंने उसके साथ बलात्कार किया और वहां से फरार हो गए। नाबालिग के घर लौटने और अपने परिवार को सारी बात बताने के बाद, परिवार पीड़िता के साथ रात में युयुमुरा थाने गया और उसे पुलिस के हवाले कर दिया। सूचना और पीड़िता के बयान के आधार पर पुलिस ने थाने में भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 70 (बलात्कार) और पोक्सो अधिनियम की धारा 6 (गंभीर यौन उत्पीड़न) के तहत मामला (क्रमांक 174/25) दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पीड़िता का तुरंत इलाज कराया गया। रेढ़ाखोल एसडीपीओ प्रशांत कुमार मेहर के नेतृत्व में पुलिस ने विभिन्न स्थानों पर छापेमारी कर देर रात मुख्य आरोपी समेत तीन लोगों को गिरफ्तार कर लिया। एसपी भामू ने कहा कि मामले के दो आरोपियों को गिरफ्तार कर जल्द से जल्द अदालत में आरोप पत्र दायर किया जाएगा और मामले के शीघ्र फैसले के लिए पुलिस आरोपियों के खिलाफ मजबूत सबूत पेश करने का प्रयास करेगी। गिरफ्तार मुख्य आरोपी मिर्धा को सोमवार को अदालत में पेश किया गया। जमानत खारिज होने के बाद उसे जेल भेज दिया गया है।

आईएएस विनय चौबे को बेल,90 दिनों में एसीबी आरोपपत्र दे पाने मे असफल

कार्तिक कुमार परिच्छा, स्टेट हेड -झारखंड

जमीन घोटाले का आरोपी होने कारण जेल में ही रहेंगे

रांची , झारखंड के निलंबित आईएएस अधिकारी विनय कुमार चौबे को आज शराब घोटाले के एक मामले में जमानत दे दी गयी है। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो तय समय सीमा के भीतर आरोप पत्र दायर करने में विफल होने के कारण ऐसा हुआ है । पर चौबे को जेल से शीघ्र निकल नहीं पायेंगे ,कारण वे हजारीबाग में जमीन से जुड़े एक मामले में भी आरोपी हैं।

चौबे के वकील देवेश अजमानी के अनुसार अदालत को बताया गया कि मंगलवार को इस मामले में 92 दिन बीत चुके हैं, लेकिन एसीबी ने आरोप पत्र दायर नहीं किया है। उच्चतम न्यायालय ने कई मामलों में निर्देश दिया है कि यदि तय समय सीमा के भीतर आरोप पत्र दायर नहीं किया जाता है, तो आवेदक डिफॉल्ट जमानत का हकदार हो जाता है।₹ चौबे फिलहाल रांची रिम्स में इलाज करा रहे हैं।

एसीबी अदालत ने उन्हें बीएनएनएस की धारा 187(2) के तहत डिफ़ॉल्ट जमानत दी। अजमानी ने बताया कि अदालत ने उन्हें जमानत के लिए 25,000 रुपये के दो निजी मुचलके जमा करने, उसकी अनुमति के बिना राज्य न छोड़ने और अपना मोबाइल नंबर न बदलने का निर्देश दिया है। चौबे ने अपनी याचिका में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो द्वारा अपनी गिरफ्तारी को चुनौती दी थी। याचिका में दावा किया गया था कि उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर सही नहीं है और उसे खारिज किया जाना चाहिए। एसीबी ने चौबे को 20 मई को गिरफ्तार किया था। उनके खिलाफ लगे आरोपों के मद्देनजर राज्य सरकार ने उन्हें निलंबित कर दिया था। चौबे पर 38 करोड़ रुपये की शराब की बिक्री से जुड़े घोटाले में शामिल होने का आरोप है।

750करोड फर्जी जीएसटी घोटाले पर झारखंड मे कबाड़ी वाले के यहां ईडी का छापा

कार्तिक कुमार परिच्छा, स्टेट हेड -झारखंड

रांची साहिबगंज में प्रवर्तन निदेशालय की टीम ने मंगलवार सुबह छापेमारी की। ईडी की यह कार्रवाई नगर थाना क्षेत्र के बंगाली टोला स्थित तिलकधारी कुआं के पास रहने वाले नवीन कुमार दास उर्फ बबलू कबाड़ी के घर पर की गई।

सूत्रों के अनुसार, छापेमारी सुबह करीब 7 बजे शुरू हुई। इस दौरान ईडी के दो अधिकारी और सीआरपीएफ के आधा दर्जन जवान मौके पर मौजूद थे। ईडी की टीम ने साहिबगंज में एक साथ तीन जगहों पर दबिश दी है। बताया जा रहा है कि टीम गोवा ब्रांच से पहुंची है और जीएसटी से जुड़े मामले में बबलू कबाड़ी के ठिकाने पर कागजात खंगाल रही है। छापेमारी की जद में संतोष कुमार गुप्ता का नाम भी सामने आया है, जो स्क्रैप डीलर हैं। संतोष गुप्ता भाजपा नगर अध्यक्ष सुबोध दास के चचेरे भाई बताए जाते हैं।

उल्लेखनीय है कि इससे पहले 7 अगस्त को भी ईडी ने 750 करोड़ रुपये के फर्जी जीएसटी चालान बनाने के मामले में झारखंड, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र में छापेमारी की थी। उस दौरान धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत तीन राज्यों में 12 परिसरों पर तलाशी ली गई थी।

इंडिगो भुवनेश्वर से दुबई के लिए उड़ानें बंद करेगी

मनोरंजन सासमल , बरिष्ठ पत्रकार

भूबनेश्वर : राज्य की अंतरराष्ट्रीय उड़ानों को बड़ा झटका देते हुए, इंडिगो अपनी भुवनेश्वर-दुबई उड़ान सेवा बंद करने जा रही है। कंपनी 24 अक्टूबर से इस रूट पर अपनी सेवाएँ बंद कर देगी। इंडिगो इस रूट पर हफ़्ते में तीन बार उड़ान भरती थी। उम्मीद है कि कंपनी यह सेवा बंद कर देगी क्योंकि 'एयरोरूट्स' के संशोधित उड़ान कार्यक्रम में इंडिगो के भुवनेश्वर-दुबई रूट का ज़िक्र नहीं है।दुबई जाने के इच्छुक यात्री अबू धाबी होते हुए यात्रा कर सकते हैं। वैकल्पिक रूप से, वे भुवनेश्वर से देश के किसी अन्य शहर में जाकर वहाँ से दुबई के लिए सीधी उड़ान ले सकते हैं। इंडिगो ने मई 2023 से भुवनेश्वर और दुबई के बीच सीधी उड़ान सेवाएँ शुरू की थीं। कंपनी राज्य सरकार के साथ मिलकर राज्य से अंतरराष्ट्रीय उड़ानें बढ़ाने के लिए काम कर रही थी। दुबई के लिए सीधी उड़ान सेवा ने राज्य के सूचना प्रौद्योगिकी, विनिर्माण और पर्यटन क्षेत्रों में निवेश आकर्षित करने में भी मदद की।

स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक एवं संपादक संजय कुमार बाटला द्वारा इम्प्रेशंस प्रिंटिंग एंड पैकेजिंग लिमिटेड, सी-18,19,20 सेक्टर 59, नोएडा (उत्तर प्रदेश) से मुद्रित एवं 3, प्रियदर्शनी अपार्टमेंट ए-4, पश्चिमी विहार, नई दिल्ली- 110063 से प्रकाशित। सम्पर्क : 9212122095, 9811902095. newstransportvishesh@gmail.com
(इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी) किसी भी कानूनी विवाद की स्थिति में निपटारा दिल्ली के न्यायालय के अधीन होंगे। RNI No :- DELHIN/2023/86499. DCP Licensing Number F.2 (P-2) Press/2023